राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

स्विंग और चपलता से भुवी बने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज

>> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 64

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 13 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

एक नई आजादी...

एनआइए (संशोधन) अधिनियम के तहत एनआइए को विदेशों में किसी भारतीय या भारतीय हितों पर हमलों की जांच का अधिकार मिला। पेज 3

जय हिंद

घायल राठौर 18 घंटे तक संभाले रहे मोर्चा

कोरबा : इस सुपरकॉप के नाम से नक्सलगढ़ के दहशतगर्द भी कांप जाते हैं। 35 एनकाउंटर और आधा दर्जन नक्सल कमांडरों को ढेर करने वाले जांबाज अफसर प्रकाश राठौर को 15 अगस्त को वीरता पदक मिलेगा। ● पेज 13

ताकत वतन की हमसे है...

स्वतंत्रता के सारथी

गंदे नाले में बदल चुकी नदी को बना दिया आस्था का केंद्र

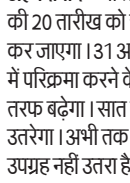

भिलाई : जल संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ के युवा समाजसेवी संजय कुमार मिश्रा का प्रेरक प्रयास सामने है। दो साल पहले तक बदबूदार गंदे नाले में तब्दील हो चुकी शिवनाथ नदी आज आमजन की आस्था का विषय बन गई है। आइये इस जल प्रहरी के जज्बे को सराहें और प्रेरणा लें। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

अब राजनीति के दंगल में उतरीं बबीता फौगाट

चंडीगढ़ : अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फौगाट और उनके पिता द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर फौगाट सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। बबीता पुलिस की नौकरी छोड़ भाजपा में शामिल हुई हैं, जबकि महावीर ने जजपा के खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर भाजपा में आस्था जताई।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, एयरपोर्ट बंद

हांगकांग : चीन के खिलाफ लोकतंत्र समर्थकों के विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए हांगकांग एयरपोर्ट से आने-जाने वाली सारी उड़ानें सोमवार को रद कर दी गईं। हवाई अड्डे पर जमा पांच हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर लोकतंत्र समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारे लगा रहे थे।

आजकल ▶ पृष्ठ 14

20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा चंद्रयान-2

अहमदाबाद : भारत का चंद्रयान-2 इस माह की 20 तारीख को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। 31 अगस्त तक चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करने के बाद यान दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेगा। सात सितंबर को दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अभी तक चंद्रमा के इस हिस्से में कोई उपग्रह नहीं उतरा है।

सुधरते हालात ▶ 30 वर्षों में पहली बार नहीं हुई हिंसा, नहीं सुनाई दिए देश विरोधी नारे

कश्मीर में शांति से मनाई गई बकरीद

मस्जिदों में जुटी नमाजियों की भीड़, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बकरीद पर थे कड़े सुरक्षा इंतजाम

नवीन नवाज, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बकरीद पर हालात बिगड़ने की आशंकाएं गलत साबित हुईं। कड़ी सुरक्षा के बीच त्योहार आम तौर पर पूरी तरह शांति से मना। सोमवार को बकरीद पर बीते 30 वर्षों में पहली बार न कहीं पाकिस्तानी झंडों के साथ जुलूस निकला और न हिंसा हुई। अधिकारियों के अनुसार, यह पहली बार है जब बकरीद पर सुरक्षाबलों को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी।

जम्मू से लेकर कश्मीर तक सभी इलाकों के लोग अपने आसपास की मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाज के लिए पहुंचे थे। हालांकि बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों के तैनात रहने से त्योहार का वैसा माहौल नहीं दिखा जैसा हमेशा होता था। कश्मीर के कुछ इलाकों में प्रदर्शन भी हुए, जिनमें कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरे दिन कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। उन्होंने श्रीनगर के लालचौक से लेकर दक्षिण कश्मीर में जवाहर सुरंग तक हवाई सर्वे भी किया।

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद सोमवार को उल्लासपूर्वक बकरीद मनाई गई। श्रीनगर में मस्जिद के बाहर जुटे हजारों लोगों ने इस मौके पर नमाज अदा की। एपी

श्रीनगर में ही नहीं, बारामुला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बांडीपोर, बड़गाम, सोपोर, गांदरबल, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम में भी नमाज-ए-ईद बिना किसी हंगामे के संपन्न हुई। बारामुला की मस्जिद में 10 हजार से ज्यादा नमाजी थे, जबकि अनंतनाग में करीब 14 हजार नमाजियों ने लालचौक के पास स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ी। शरारती तत्वों पर अंकुश के लिए वादी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। सभी संवेदनशील इलाकों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात थे। किसी अप्रिय घटना से निपटने को सुरक्षाबलों के विशेष दस्तों को पूरी तरह तैयार रखा गया था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ।

मस्जिद में कोई जिहादी नारा नहीं लगा : राज्य पुलिस की सीआइडी विंग के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे पास जो रिपोर्ट आई हैं उसके आधार पर किसी मस्जिद में कोई जिहादी नारा नहीं लगा है, किसी जगह पाकिस्तानी झंडे और आतंकियों के पोस्टर भी नहीं दिखे।

कहां कितने नमाजी पहुंचे

बारामुला	10,000
बड़गाम, मागाम	8,000
गांदरबल	7,000
कुलगाम, कोयमू	6,000
कांजीगुंड	5,500
बांडीपोरा, दारूल-रहीमिया	5,000
बड़गाम, चरार-ए-शरीफ	5,000
जम्मू, जामिया मस्जिद	5,000
शोपियां	3,000
अनंतनाग अच्छाबल	3,000
अवंतीपोरा	2,500
बांडीपोरा, जामिया	2,000
पुलवामा	1,800

नहीं चलानी पड़ी एक भी गोली : कश्मीर रेंज के आइजी एसपी पाणि ने कहा कि कश्मीर में कुछ जगह पथराव और हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुईं, जिन पर जल्द ही काबू पा लिया गया। पुलिस को या किसी अन्य सुरक्षा बल को कहीं गोली नहीं चलानी पड़ी है। उन्होंने कश्मीर में सीआरपीएफ कर्मी द्वारा अपने ही पांच साथियों को गोली मारे जाने की खबर को भी निराधार बताया। यह खबर पाकिस्तान के पत्रकार के ट्वीट करने के बाद वायरल हुई है।

जम्मू में दिखा उल्लास : जम्मू में बड़ी संख्या में लोग इबादतगाहों में नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज अदा होने तक सुरक्षा की दृष्टि से शहर की मुख्य सड़कों और मोहल्लों को कंटीले तारों से बंद रखा गया था। सुरक्षाकर्मी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। बकरीद की खुशियां साझा करने के लिए ईदगाह मैदान रेजीडेंसी रोड पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने मीठी सेवइयों और हलवे का स्टाल भी लगाया था।

यासीन मलिक के घर के पास मस्जिदों में भी रही भीड़ : जेकेएलएफ के मुखिया यासीन मलिक के मैसूमा स्थित घर से 50 कदम की दूरी पर स्थित दोनों मस्जिदों में भी नमाज शांति से संपन्न हुई। दोनों मस्जिदों में लोगों की सुविधा के लिए नमाज में करीब 40 मिनट का अंतर रखा गया था। जुबैर नामक एक युवक ने कहा, मेरी मां बहुत खुश है। उसने कहा कि आज मैं ईदगाह नहीं गया, क्योंकि वहां हर बार पथराव होता है। बीते साल वहां पथराव में मेरा सिर फूटा था। इसी तरह कुरसु राजबाग स्थित मस्जिद में नमाज के बाद पड़ोसी को ईद की मुबारक देते हुए यूसुफ ने कहा, पहली बार लगा कि ईद की नमाज की मजलिस है। अन्यथा यहां नमाज से पूर्व जो होता था उसमें सिर्फ सियासत, बंदूक व जिहाद का जिक्र होता था।

आधा दर्जन से ज्यादा ट्विटर अकाउंट पर लगेगी रोक पेज>>5

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध हटाए जाने की मांग पर सुनवाई आज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने तथा मोबाइल और इंटरनेट सेवा शुरू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर यह मांग रखी है।

जस्टिस अरुण मिश्रा, एमआर शाह और अजय रस्तोगी की पीठ पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने भी कोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पत्रकारों पर लगाए गए नियंत्रण को समाप्त करने की मांग की है। तहसीन पूनावाला की याचिका में जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू और प्रतिबंध हटाए जाने और मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग की गई है। साथ ही हिरासत में लिए गए नेताओं को तत्काल रिहा करने की भी मांग की गई है। गुरुवार को इस याचिका पर कोर्ट से जल्दी सुनवाई की मांग की गई थी जिस पर कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई पर लगाए जाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करने का आदेश दिया था।

ज्ञात हो, राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। संसद के दोनों सदनों से अनुच्छेद 370 खत्म करने का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था। इसके बाद राज्य में सुरक्षा के लिहाज से कुछ कदम उठाए गए हैं।

अब गुलाम कश्मीर पर बड़ा कदम उठा सकती है सरकार : जावड़ेकर

नईदुनिया, इंदौर

- केंद्रीय मंत्री ने कहा-अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान घबराया
- बोले-अयोध्या में राम मंदिर तो बना है, वहां केवल भव्य मंदिर बनाना है

केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है। अब केंद्र सरकार जल्द ही गुलाम कश्मीर पर भी बड़ा कदम उठा सकती है। वह हमारे देश का हिस्सा है और उसे भारत में मिलाना हमारा काम है।

इंदौर के भाजपा कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में जावड़ेकर ने कहा कि गुलाम कश्मीर के लिए सर्वसम्मति से संसद में भी प्रस्ताव पारित होते रहे हैं। 1994 में भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुलाम कश्मीर क्षेत्र की सीटें अभी खाली रहेंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाक बेहद घबराया हुआ है। इसी का परिणाम है कि उसने समझौता एक्सप्रेस और भारत-पाक के बीच चलने वाली बस सेवा बंद कर दी। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास के सोपान स्थापित होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बयान पर टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए जावड़ेकर ने कहा, उनके तर्कों का अब कोई मतलब नहीं है। ज्ञात हो, चिदंबरम ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, इसलिए अनुच्छेद 370 हटा दिया। यदि हिंदू बहुल होता तो नहीं हटाते। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तो पहले से ही बना है, बस उसे भव्य रूप देने की जरूरत है।

हमने 75 दिन में 75 फैसले ले लिए वे अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन सके: जावड़ेकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा में बहुत फर्क है। भाजपा की नई सरकार बने 75 दिन हो गए हैं। इस अवधि में सरकार ने 75 बड़े फैसले ले लिए, जबकि इतने ही दिनों में कांग्रेस अपनी पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं चुन सकी। 75 दिन में सबसे बड़ा फैसला अनुच्छेद 370 हटाने का है, जो कांग्रेस सरकार 70 सालों में भी नहीं कर सकी।

370 से अलग है 371 की पृष्ठभूमि : उत्तर-पूर्वी राज्यों में लगे अनुच्छेद 371 की तुलना अनुच्छेद 370 से करने को गलत बताते हुए जावड़ेकर ने कहा, दोनों में बहुत फर्क है। इनकी पृष्ठभूमि भी अलग-अलग है। 371 किसी राज्य में विशेष अधिकार के लिए लगाया जाता है, जबकि 370 में भारत में लागू होने वाले कानून का पालन नहीं होता है। यह अनुच्छेद किसी राज्य को अपने ही देश से अलग कर देता है।

इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। नई दुनिया

बौखलाए पाक ने लद्दाख के पास तैनात किए लड़ाकू विमान

नई दिल्ली : भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने से बौखलाया पाकिस्तान लद्दाख के पास अपने अग्रणी वायु सैन्य अड्डे स्कर्दू में लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ ही सैन्य उपकरण भी जमा कर रहा है। भारतीय सेना चौकस निगाह रख रही है। (पेज-5)

अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट क्रांति की ओर रिलायंस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- ब्रॉडबैंड के सालाना प्लान के साथ लैंडलाइन फोन, सेट-टॉप बॉक्स और एलईडी टीवी फ्री
- पांच सितंबर को कंपनी देशभर में लांच करेगी गीगा फाइबर सेवा
- देश के 1,600 शहरों में दो करोड़ घरों तक पहुंचेगी यह सर्विस
- सिर्फ डाटा भुगतान पर मिलेंगी वॉयस कॉल, टीवी प्रसारण, अन्य एंटरटेनमेंट सेवाएं

ब्रॉडबैंड के माध्यम से होम एंटरटेनमेंट से लेकर इंटरनेट सेवा के बाजार में रिलायंस जियो अगले माह धमाका करने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 42वीं सालाना आमसभा में एलान किया है कि देश में जियो गीगा फाइबर की सेवा पांच सितंबर से शुरू हो जाएगी। यह सेवा 700-10,000 रुपये प्रति माह के टैरिफ प्लान पर उपलब्ध होगी। इसके तहत टीवी देखने वाले ग्राहकों को न सिर्फ हाई डेफिनिशन चैनल उपलब्ध होंगे, बल्कि देश भर में किसी भी नेटवर्क पर वॉयस कॉल सुविधा भी ताउम्र मिलेगी।

अंबानी ने बताया कि जियो फॉरएवर (सालाना प्लान) चुनने वालों को 4के टीवी और 4के सेट टॉप बॉक्स मुफ्त मिलेगा। अगले वर्ष मध्य तक जियो गीगा फाइबर के प्रीमियम ग्राहक घर बैठे किसी भी फिल्म को उसकी रिलीज के दिन ही देख सकेंगे। इस स्कीम को जियो ने 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' नाम दिया है।

मुंबई में सोमवार को आरआइएल की 42वीं सालाना आमसभा में चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ उनकी पत्नी नीता और मां कोकिलाबेन भी शामिल हुईं। प्रेट्र

कंपनी के मुताबिक, जियो गीगा फाइबर प्लान 100 एमबी प्रति सेकंड (एमबीपीएस) से शुरू होकर एक जीबी प्रति सेकंड की स्पीड वाले डाटा के साथ होंगे। कंपनी ने खुद को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया है। अब वह ग्राहकों को बेहतर सुविधाओं के साथ हाई-डेफिनिशन चैनलों की सबसे बड़ी पेशकश कर सकती है। अंबानी ने कहा, सेट टॉप बॉक्स हेडसेट के जरिये मिक्स्ड रियलिटी को सपोर्ट करेगा और ग्राहक खुद का 3डी होलोग्राम बना सकेंगे। उन्होंने कहा, 'इस साल पांच सितंबर को जियो की तीसरी वर्षगांठ है। जियो के आने से पहले हिंदुस्तान में 'डाटा डार्क' था अब 'डाटा शाइनिंग' है। जियो ने 34 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है, एक करोड़ ग्राहक हर माह जियो से जुड़ रहे हैं। जियो फाइबर टैरिफ योजना के तहत कंपनी 1,600 शहरों में दो करोड़ घरों में पहुंचना चाहती है।

रिलायंस में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी अरैमको पेज>>10

ग्राहकों को यह मिलेगा

- न्यूनतम 700 रुपये वाले मंथली प्लान के साथ लैंडलाइन फोन से जिंदगीभर किसी भी नेटवर्क पर फ्री वॉयस कॉल
- न्यूनतम 100 एमबीपीएस से अधिकतम एक जीबीपीएस की इंटरनेट स्पीड
- जियो फॉरएवर के तहत सालाना प्लान के साथ सेट टॉप बॉक्स और एक एलईडी टीवी मुफ्त
- इंटरनेशनल कॉलिंग प्लान के तहत सिर्फ 500 रुपये शुल्क पर महीनेभर अमेरिका और कनाडा के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग सुविधा
- प्लान के प्रीमियम ग्राहकों के लिए थिएटर में रिलीज वाले दिन ही टीवी पर वही फिल्म देखने की सुविधा

अगले तीन साल तक देश में नहीं खुल सकेगा कोई भी लॉ कॉलेज

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में तेजी से खुल रहे लॉ कॉलेजों पर चिंता जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने अगले तीन सालों तक नए संस्थानों के खोले जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि राज्य द्वारा प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर यह रोक प्रभावी नहीं होगी। बीसीआइ ने कहा कि वह इस दौरान मौजूदा लॉ कालेजों के मानकों में सुधार पर जोर देगा।

रविवार को एक बैठक में बीसीआइ ने देश में तेजी से खुल रहे लॉ कॉलेजों के बारे में अपने सदस्य वेद प्रकाश शर्मा द्वारा उठाए गए सवाल पर विचार-विमर्श किया। काउंसिल ने राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने, चार माह के अंदर सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लॉ शिक्षकों के रिक्त पद भरने का अनुरोध किया है। अपने प्रस्ताव में बीसीआइ ने कहा कि देश भर में 1,500 लॉ कॉलेज हैं। विवि और राज्यों के

- बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लगाई रोक, चार माह में कॉलेजों-विवि में लॉ प्रोफेसरों के रिक्त पद भरने को कहा

सुस्त रवैये के कारण कई कॉलेज बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे के चल रहे हैं। राज्य सरकारें शायद ही कभी सरकारी लॉ कॉलेजों और संबंधित संस्थानों के लॉ संकायों की नियुक्ति में रुचि लेती हैं।

बीसीआइ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की आलोचना करते हुए कहा कि 90 प्रतिशत लॉ कॉलेजों को मानकों में सुधार करने के लिए कोई अनुदान नहीं मिलता है। एलएलएम या पीएचडी की डिग्री लेना बहुत आसान है। बता दें कि एलएलएम और पीएचडी की डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में नहीं आती है।

जयशंकर बोले, अनुच्छेद 370 हटाने से न पाक की सीमा बदली, न चीन की

राजीव सचान, बीजिंग

- विदेश मंत्री ने चीनी समकक्ष से कहा, संवेदनशील मुद्दों का रखना होगा खयाल
- बोले, जमीनी हकीकत देखकर भारत और पाक के रिश्तों का आकलन करे चीन

चीन की ओर से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को सवाल की शक्ल दिए जाने पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने समकक्ष वांग यी से सोमवार को साफ-साफ कहा कि भारत के इस कदम से न तो पाकिस्तान से लगती सीमा बदली है और न ही चीन की। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बेहतर शासन संचालन के लिए यह निर्णय लेकर भारत ने किसी नए इलाके पर दावा भी नहीं किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चीन ने 'के' शब्द यानी कश्मीर का उल्लेख तो किया, लेकिन 'क्यू' यानी पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं लिया।

जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री की ओर से कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप मसले के समाधान की जरूरत रेखांकित करने पर उक्त जवाब दिया। भारत से गए पत्रकारों से देर रात मुलाकात में जयशंकर ने वांग यी से बातचीत का विवरण देते समय खास तौर पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने चीनी नेताओं से कहा, 'भारत-चीन के रिश्तों का भविष्य एक दूसरे के मुख्य चिंताओं को लेकर बरती जाने वाली संवेदनशीलता से ही तय होगा। यह बेहद प्राकृतिक भी है क्योंकि दोनों पड़ोसी होने के साथ ही आर्थिक तौर पर बड़े विकासशील देश भी हैं, ऐसे में इनके बीच कई मुद्दे बने रहेंगे। ऐसे में मतभेदों का सही तरीके से प्रबंधन बहुत जरूरी है। जैसा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच अस्ताना में यह सहमति बनी थी कि मतभेदों को अब विवाद नहीं बनने देंगे।' खास बात यह है कि कुछ साल पहले तक चीन भारत को यह सलाह देता था कि दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती के लिए जरूरी है कि वे एक दूसरे के संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखें। अब यही सलाह भारत चीन को दे रहा है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, विदेश मंत्री जयशंकर ने यह बताने में कोई गुरेज नहीं किया कि चीन बेवजह ही भारत के आंतरिक मामले को लेकर चिंतित हो रहा है। भारत ने अपने संविधान के तहत किए गए एक अस्थायी फैसले को बदला है। जहां तक भारत-पाक के बीच रिश्तों की बात है तो चीन को वास्तविक हालात पर आकलन करना चाहिए। भारत एक जिम्मेदार शक्ति है और वह पाकिस्तान की तरफ से होने वाले उकसावे का संयम से जवाब देता है। भारत आतंक से मुक्त सामान्य संबंध में भरोसा करता है। विदेश मंत्री ने बताया कि चीन के साथ सीमा विवाद के मामले में दोनों देश उसके स्थायी और उचित समाधान में जुटे हुए हैं।

पाक से तनातनी के बीच चीन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में अपने चीन के समकक्ष वांग यी से भेंट की। प्रेट्र

चार समझौतों पर हस्ताक्षर : जयशंकर के अनुसार, उनकी चीनी विदेश मंत्री के साथ सभी महत्वपूर्ण मसलों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने चीन के साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करने वाले चार समझौतों का भी उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने शाम को एक सांस्कृतिक समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। इस समारोह का आयोजन भारत-चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए उच्चस्तरीय व्यवस्था निर्माण की दूसरी बैठक के उपलक्ष्य में किया गया। समारोह में वांग यी भी उपस्थित थे।

मोदी-चिनफिंग के बीच होने वाली वार्ता में कारोबार होगा बड़ा मुद्दा पेज>>3

नया रूप

एडवेंचर शो 'मैन वर्सेस वाइल्ड' में दुनिया बनी रोमांचक अनुभव की साक्षी, चेहरे पर शिकन के बिना मोदी ने जंगल के बीच सहजता से बिताए पल, मेजबान बेयर ग्रिल्स को बनाया भारतीय संस्कृति और विचारों का कायल

साहस के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिखाया प्रकृति प्रेम

जेएनएन, नई दिल्ली

बादलों की गरज, पक्षियों की चहक, नदी की कल-कल और इन सबके बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार की शाम पूरी दुनिया ऐसे ही रोमांचक अनुभव का गवाह बनी। डिस्कवरी चैनल के एडवेंचर शो 'मैन वर्सेस वाइल्ड' के मेजबान बेयर ग्रिल्स के साथ उत्तराखंड स्थित जिम कार्बेट के जंगलों में प्रधानमंत्री मोदी का नया रूप देखने को मिला।

शो में निसंदेह मोदी से कोई बड़ा जोखिम उठाने की अपेक्षा नहीं थी, जैसा बेयर ग्रिल्स के शो में आमतौर पर दिखता है। हालांकि मोदी ने इस शो में जैसा साहस और जैसी सहजता दिखाई, वह प्रेरणास्पद थी। बेयर ग्रिल्स भी मोदी के मुरीद हुए बिना नहीं रह पाए। रोमांचक सफर के दौरान बेयर ग्रिल्स ने मोदी से उनके बचपन, प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों, सपनों और परिवार से जुड़े कई सवाल किए, जिनका उन्होंने खुलकर जवाब दिया। चलते-चलते ग्रिल्स ने प्रधानमंत्री मोदी को महान व्यक्तित्व का धनी बताते हुए उनके लिए और भारत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

डिस्कवरी चैनल के एडवेंचर शो 'मैन वर्सेस वाइल्ड' को भारत समेत 180 देशों में प्रसारित किया गया। देश में इस शो को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता दिखी। पूरे शो के दौरान लोग टीवी के सामने डटे रहे। एएफपी

प्रकृति से साम्य का अनूठा संदेश : बेयर ग्रिल्स से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकृति से साम्य स्थापित करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते समय हमें सोचना चाहिए कि आज से 50 साल बाद पैदा होने वाले बच्चे हमसे क्या सवाल करेंगे। प्रकृति के बारे में आने वाली पीढ़ियों की चिंता को ध्यान में रखकर ही पूरी दुनिया प्रकृति संरक्षण का कदम उठा सकती है।

डर कहीं छू भी नहीं पाया : मेजबान बेयर ग्रिल्स ने मोदी को कई बार जंगली जीवों विशेषतौर पर बाघ का भय दिखाने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने हमेशा मुस्कुराकर जवाब दिया। ग्रिल्स ने उनसे पूछा कि आखिर वह डर की स्थिति में खुद को कैसे संभालते हैं। इस पर मोदी ने कहा, 'मैं डर से संभलने के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका अनुभव कभी हुआ ही नहीं। मेरा अंतर्मन सदैव शांत रहता है। जो होता है, मैं उसे सहजता से स्वीकार करता हूं।' मोदी ने यह भी कहा कि प्रकृति से डर तभी लगता है, जब हम उससे संघर्ष करते हैं।

सहजता ने लुभाया : ग्रिल्स के साथ जंगल और उफनती नदी के सफर में मोदी की सहजता लुभाने वाली थी। मोदी ने कहीं ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि वह कितना बड़ा व्यक्तित्व हैं। ग्रिल्स ने कई बार उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मोदी ने इसे बहुत सहजता से लिया। ग्रिल्स के साथ उन्होंने चाय का स्वाद भी लिया। यहां तक कि लकड़ियों से बनी और बिना जांची-परखी नाव पर सवार होकर उफनती नदी पार करते हुए भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी।

भारत के विचारों से रूबरू हुई दुनिया : मोदी ने इस शो के माध्यम से दुनियाभर को प्रकृति के प्रति भारतीय संस्कृति के विचारों से रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि यहां हर जीव, पेड़-पौधे में ईश्वर का अंश माना जाता है। उन्होंने प्रकृति से संघर्ष नहीं, साम्य का संदेश दिया। सवाल-जवाब के बीच मोदी ने बचपन में प्रकृति के सानिध्य में बिताए पलों और बाद में हिमालय की गोद में बीती जिंदगी को भी याद किया। प्रकृति को लेकर परिवार से मिले संस्कारों की झलक भी उनकी बातों में स्पष्ट थी।

3 फुट ओवरब्रिज बनाएगा लोक निर्माण विभाग राजधानी में। इनके निर्माण में करीब नौ करोड़ रुपये खर्च आने की संभावना है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 13 अगस्त 2019

एनसीआइ की रेडियोलॉजी की हालत ठीक नहीं

संकट ▸ झज्जर स्थित संस्थान से अनुबंधित डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा

वर्किंग समूह की बैठक में रेडियो डायग्नोसिस की सुविधाओं का निजीकरण करने का दिया गया सुझाव

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

एम्स के झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआइ) का भले ही संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन डॉक्टरों की कमी से कई सुविधाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। इस बीच एनसीआइ से दो अनुबंधित डॉक्टरों (सहायक प्रोफेसर) ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें एक रेडियोलॉजी विभाग की महिला डॉक्टर शामिल हैं। उनके इस्तीफे के बाद एम्स कैंसर सेंटर के रेडियोलॉजी विभाग ने एनसीआइ में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सीटी गाइडेड बायोप्सी, एमआरआइ जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने से हाथ खड़े कर दिए हैं। एम्स के एनसीआइ के वर्किंग समूह की बैठक में रेडियो डायग्नोसिस की सुविधाओं का निजीकरण करने का सुझाव दे दिया है। ऐसे में एनसीआइ में रेडियोलॉजी से संबंधित जांच सुविधाओं के आउटसोर्स होने की आशंका बढ़ गई है।

इस पर एम्स के डॉक्टर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैंसर के मरीजों को अत्याधुनिक जांच व इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने एम्स के झज्जर कैंपस में एनसीआइ का निर्माण कराया है। इस साल जनवरी में एम्स ने एनसीआइ में ओपीडी सेवा शुरू की थी। बाद में मरीजों को भर्ती करने की सुविधा भी शुरू हुई। 710 बेड की क्षमता वाले एनसीआइ में पहले फेज में करीब 250 बेड के साथ इलाज शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण अभी तक 250 बेड का संचालन नहीं हो पा रहा है।

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब तक एम्स एनसीआइ में स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर सका है। कुछ अस्थायी फैकल्टी की नियुक्ति हुई थी। इनमें से कुछ दिन पहले रेडियो डायग्नोसिस की एक महिला डॉक्टर व सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग से एक डॉक्टर ने एनसीआइ से इस्तीफा दे दिया क्योंकि यहां उनकी नौकरी अस्थायी थी और वेतन भी कम था।

एम्स कैंसर सेंटर के डॉक्टर कहते हैं कि दोनों डॉक्टरों की ऋषिकेश एम्स में स्थायी नियुक्ति हो गई है। हालांकि एम्स में एक साल से 161 स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। इनमें से एनसीआइ के लिए भी 32 डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है। इनमें रेडियोलॉजी के तीन डॉक्टरों के पद शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीआइ के लिए स्वीकृत पद पर साक्षात्कार में रेडियोलॉजी का कोई डॉक्टर शामिल नहीं हुआ। इससे रेडियोलॉजी विभाग के सामने सबसे अधिक संकट खड़ा हो गया है। मौजूदा समय में एनसीआइ में सिर्फ अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। सीटी स्कैन मशीन लगने वाली है। यही वजह है कि पिछले दिनों एनसीआइ के संचालन और सुविधाओं में विस्तार के लिए वर्किंग समूह की बैठक हुई थी। इसमें एम्स कैंसर सेंटर के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल हुए थे। इसमें ही रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा को आउटसोर्स करने की बात कही गई। ऐसे में मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस बारे में एम्स कैंसर सेंटर व एनसीआइ के प्रमुख डॉ. जीके रथ से बात करने की कोशिश की गई पर उनसे बात नहीं हो पाई।

सीबीएसई ने नहीं घटाई फीस तो दिल्ली सरकार उठाएगी खर्च

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क में की गई भारी बढ़ोतरी को गलत ठहराते हुए दिल्ली सरकार ने इसे वापस लेने की अपील की है। उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि परीक्षा शुल्क बढ़ने के बाद गरीबों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ऐसे में सीबीएसई को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो गरीब वर्ग के सभी बच्चों की फीस का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। वहीं, शिक्षाविदों और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों का भी यह कहना है कि शुल्क बढ़ने से गरीब तबके के बच्चों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

सरकारी स्कूल में एसएमसी मेंबर और शिक्षाविद डॉ. डीके तनेजा ने अपील की है कि जो गरीब बच्चे बढ़ी हुई परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हैं, उनकी फीस पीडब्ल्यूएफ (पब्लिक वेलफेयर फंड) से भरी जाए। गौरतलब है कि सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत एससी व एसटी वर्ग के बच्चों को अब 24 गुना अधिक शुल्क देना होगा। सामान्य वर्ग के बच्चों को भी पहले की अपेक्षा दो गुना शुल्क देना होगा।

दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एक तरह दिल्ली सरकार जहां शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और कम पैसे में या मुफ्त में शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, वहीं सीबीएसई ने शुल्क बढ़ोतरी कर बच्चों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है।

तोड़े गए संत रविदास मंदिर को बनवाया जाए : गौतम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी ने तुगलकाबाद स्थित संत रविदास का वर्षों पुराना मंदिर तोड़े जाने के मामले में डीडीए पर आरोप लगाए हैं। आप ने कहा कि 10 अगस्त को सुबह तोड़े गए इस मंदिर की मूर्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) वाले उठा ले गए। आप ने कहा है कि डीडीए के इस कदम का पूरे देश में विरोध हो रहा है।

आप मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि सिकंदर लोधी के समय में संत रविदास यहां आए थे और उन्होंने आश्रम बनवाया था। यहां एक तालाब भी था, जो सरकारी दस्तावेजों में भी उल्लेखित है। उसके बाद भी डीडीए ने मंदिर को तोड़ दिया और कर्मचारी मूर्ति को उठाकर ले गए। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है कि देश के करीब 30 करोड़ लोग संत रविदास में आस्था रखते हैं। इसलिए लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए मंदिर को पुनः स्थापित कराएं। गौतम ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और मंदिर फिर से बनाया जाए। इसके लिए आंदोलन की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं, आप के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीडीए लोगों को जमीन बांट रहा है। लेकिन उसे 100 गज जमीन भी संत रविदास जी के मंदिर के लिए देना मुश्किल हो गया है।

रविदास मंदिर मामले में उपराज्यपाल से मिले अकाली नेता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तुगलकाबाद में रविदास मंदिर तोड़े जाने के मुद्दे पर बात करने के लिए शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अन्य अकाली नेताओं के साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिले। उन्होंने कहा कि यह पुराना मंदिर था और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसे ध्यान में रखकर इस मामला का कोई हल निकाला जाए। अकाली नेताओं ने मंदिर के पुनर्निमाण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके का कहना है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मंदिर के ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलकर मंदिर के पुनर्निमाण के लिए जमीन की मांग की जाएगी।

गुरुग्राम में विकसित किया जाएगा लेपर्ड-डियर सफारी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : इटावा लॉयन सफारी की तर्ज पर गुरुग्राम में लेपर्ड एवं डियर सफारी विकसित किया जाएगा। इसे लेकर वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित लॉयन सफारी का दौरा किया। वह यहां की व्यवस्था से खासे प्रभावित हुए। इसी दौरान वन मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को गुरुग्राम में लेपर्ड एवं डियर सफारी के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

प्रस्तावित लेपर्ड एवं डियर सफारी सेक्टर-76 के पास गांव सकतपुर व गैरतपुर बास के आसपास के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। नरबीर सिंह ने कहा कि आने वाले समय में सिटी फॉरेस्ट व लेपर्ड सफारी प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद बनकर उभरेगा जो पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगी। उन्होंने कहा कि लेपर्ड सफारी दिल्ली एयरपोर्ट से मात्र 25 मिनट की दूरी पर होगी।

बता दें कि वन मंत्री ने नौ अगस्त को गांव सकतपुर में सिटी फॉरेस्ट विकसित करने के कार्य का शुभारंभ किया था। सिटी फॉरेस्ट कई प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। यह लोगों के लिए पसंदीदा प्राकृतिक स्थल बनेगा। सिटी फॉरेस्ट और लेपर्ड-डियर सफारी भविष्य में पर्यावरणविदों व पर्यटकों का सबसे पसंदीदा केंद्र बनेंगे। यहां आकर लोगों को आज के तनाव भरे माहौल से राहत मिलेगी। यह क्षेत्र गुरुग्राम के लिए ग्रीन लंग्स का काम करेगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल को खाली करना होगा सरकारी घर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अनधिकृत रूप से सरकारी आवास में जमे रहने से न केवल भारी असुविधा होती है, बल्कि यह उन लोगों की राह में रोड़ा बनता है, जो सरकारी आवास के इंतजार में रहते हैं। यह टिप्पणी अदालत ने महिला सैन्य अधिकारी को सरकारी आवास खाली करने का निर्देश देते हुए की है।

पटियाला हाउस कोर्ट के जिला न्यायाधीश यशवंत कुमार ने लेफ्टिनेंट कर्नल विनस देशवाल को दिल्ली छावनी क्षेत्र के मानेकशॉ रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का निर्देश दिया है। ले. कर्नल देशवाल को आवास मई 2016 में आवंटित किया गया था। जब उन्हें एम्स में ट्रेनिंग करने जाना था, तो अक्टूबर 2017 में आवास खाली करने के लिए कहा गया था। उन्हें अपना पंजीकरण मकान किराया भत्ता के लिए करवाने का निर्देश दिया गया था, ताकि सरकारी आवास खाली करने पर उन्हें भत्ता मिल सके।

वहीं, सरकारी आवास खाली करने से इन्कार करते हुए अधिकारी ने कहा कि उन्हें ऐसे नियमों की जानकारी नहीं है, जिसके तहत ट्रेनिंग या पढ़ाई के लिए जाने पर सरकारी आवास खाली करना पड़े। केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि 16 अगस्त 2018 को उपलब्ध सूची के मुताबिक 420 अधिकारी सरकारी आवास की प्रतीक्षा सूची में थे। अगर सभी अधिकारी ऐसा ही करेंगे तो प्रतीक्षा करने वालों के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी।

फुल ड्रेस रिहर्सल आज, सुरक्षा कड़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के मद्देनजर 13 अगस्त को दिल्ली पुलिस समेत पैरा मिलिट्री फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी। इस दौरान लाल किला के आसपास वीवीआइपी मूवमेंट के कारण कई प्रमुख मार्गों पर परिचालन पूरी तरह से ठप रहेगा। परेड रूटों पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस व पैरा मिलिट्री की तैनाती रहेगी। आतंकी अलर्ट जारी होने के कारण अभेद सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं।

डीसीपी उत्तरी जिला नुपूर प्रसाद के मुताबिक परेड रूटों पर बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह-जगह मचान व मोर्चा बनाए गए हैं, जिनमें अत्याधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। जगह-जगह चेक प्वाइंट बनाए गए हैं।

जिला पुलिस के अलावा सुरक्षा यूनिट, ट्रैफिक यूनिट, एसपीजी, एनएसजी व आर्मी के जवान तैनात किए जाएंगे। सभी बाजारों, रेलवे स्टेशनों व बस अड्डे पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मेट्रो में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लाल किले की पार्किंग को बंद कर दिया गया है। ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। साथ ही पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध है। सुरक्षा में 10 कंपनी पैरा मिलिट्री लगाई गई है। स्नाइपर की तैनाती की गई है। लाल किला के आसपास पांच किलोमीटर तक रेंज के एचडी कैमरे लगाए गए हैं।

स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए तैयार लाल किला। वीवीआइपी मूवमेंट के कारण आसपास कई प्रमुख मार्गों पर परिचालन पूरी तरह से ठप रहेगा। ध्रुव कुमार

सुबह 11 बजे तक कालिंदी कुंज, डीएनडी से दिल्ली में प्रवेश बंद

जागरण संवाददाता, नोएडा : स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। इस दौरान लाल किले के आसपास वीवीआइपी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लिहाजा माल वाहक व भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर सोमवार रात 12 से सुबह 11 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यही हालत 15 अगस्त को भी रहेगा। हालांकि पुलिस तीनों मार्गों पर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए मुस्तैद रहेगी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर परेड की रिहर्सल होती है। मंगलवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 15 दिन पहले 13 और 15 अगस्त को रात 12 से सुबह 11 बजे तक भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने की पत्र भेजा था। हालांकि हल्के वाहनों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। कालिंदी कुंज, डीएनडी और चिल्ला मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं। दिल्ली से भी वाहन नोएडा में आते हैं। यातायात पुलिस ने बताया कि फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान दिल्ली से भी भारी वाहन नोएडा में नहीं आएंगे। यातायात पुलिस 12 बजे से तीनों मार्गों से भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं होने देगी।

एनबीसीसी ने मांगा आम्रपाली बिल्डर की संपत्तियों का ब्योरा

जासं, ग्रेटर नोएडा : आम्रपाली बिल्डर की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत एनबीसीसी बिल्डर की उन संपत्ति का ब्योरा एकत्र कर रहा है, जिनसे वह परियोजनाओं के लिए रकम जुटाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से बिल्डर से जुड़ी संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। प्राधिकरण के अधिकारी इसे तैयार करने में जुट गए हैं। अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एनबीसीसी की बिल्डर की संपत्ति एवं निवेशकों से 11 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।

सुप्रीम कोर्ट ने 42 हजार निवेशकों को राहत देते हुए आम्रपाली बिल्डर की अधूरी योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को सौंपी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आम्रपाली बिल्डर को छह आवासीय योजनाओं के लिए विभिन्न सेक्टरों में 305 एकड़ जमीन आवंटित की थी। इसके अलावा प्राधिकरण ने बिल्डर को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कामर्शियल समेत कई अन्य भूखंड भी आवंटित किए हैं। बिल्डर की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का दारोमदार इन संपत्तियों पर ही टिका है। एनबीसीसी बिल्डर की संपत्ति को बेचकर अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रकम जुटाएगा।

गार्डेनिया गेट-वे के खरीदारों को फ्लैट खाली करने का नोटिस

जागरण संवाददाता, नोएडा

▸ बिल्डर ने बैंक से लिया था 78.45 करोड़ रुपये का लोन

▸ राहत के लिए खरीदारों ने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार से लगाई गुहार

आम्रपाली के बाद अब सेक्टर-75 के गार्डेनिया गेट-वे के खरीदारों को घर खाली करने का नोटिस आया है। यह नोटिस बैंक की तरफ से फ्लैट मालिकों को थमाया गया है। खरीदारों का आरोप है कि उन्होंने बिल्डर गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड को चार वर्ष पहले ही पूरा भुगतान कर फ्लैट लिया था। अब उन्हें उसी फ्लैट को खाली करने का नोटिस पकड़ाया गया है। खरीदारों ने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की है कि वह उनकी समस्या का समाधान करें।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने चार वर्ष पहले बिल्डर गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड को 78,45,22,970.20 रुपये का लोन निर्माण के लिए दिया था, जबकि उस वक्त बिल्डिंग का पूरा निर्माण हो चुका था और फ्लैट मालिकों ने भी सारा पैसा बिल्डर को दे दिया था। इस लोन के बारे में फ्लैट मालिकों को कुछ भी नहीं बताया गया था, जबकि बहुत से फ्लैट मालिकों ने अपने फ्लैट पर पहले से ही लोन ले रखा था, जिसकी एनओसी बिल्डर पहले ही बैंकों को दे चुका था। ऐसे में एक ही प्रॉपर्टी पर दो बार लोन बैंक की ओर से कैसे दिया गया।

बकाया के बावजूद कैसे जारी हो गई एनओसी : खरीदारों का आरोप है कि इस धोखाधड़ी में नोएडा प्रशासन भी बराबर भागीदार है, जबकि बिल्डर पर प्राधिकरण का भी कई करोड़ रुपये बकाया है। इसके बाद भी प्राधिकरण ने बिल्डर को एनओसी कैसे जारी की। बिल्डर ने सारा पैसा कहीं और डायवर्ट किया है। वह पैसे वापस नहीं कर रहा तो बैंक उसको पकड़ें और पैसा वसूल करें। ऐसे में फ्लैट मालिकों को नोटिस जारी कर फ्लैट खाली करवाना अमानवीय और गैरकानूनी है। खरीदारों का कहना है कि अब केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान कर दें।

> बैंकों की ओर से गलत नोटिस जारी किया गया है। इसकी जानकारी से बिल्डर को अवगत नहीं कराया गया है। बैंक के बोर्ड से बातचीत हो चुकी है। करीब दस दिन में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी।
> –सुरेंद्र देयोल, प्रोजेक्ट हेड, गार्डेनिया गेट-वे (अतिरिक्त निदेशक)

कैंटर चालक की हत्या में सात लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा

▸ नोएडा से दिल्ली जाने के दौरान कालिंदीकुंज बार्डर पर एमसीडी के टोल को लेकर हुआ था विवाद

▸ 14 सौ के बदले 14 हजार छह सौ रुपये टोल की अवैध पर्ची कटवाने के विरोध पर हुई थी चालक की हत्या

बिना टोल दिए दिल्ली में घुसने पर जबरन 10 गुना टोल वसूली की मांग के विरोध पर वहां मौजूद बाउंसरों ने पीट-पीटकर कैंटर चालक विमल तिवारी को मौत के घाट उतार दिया था। शुक्रवार रात दिल्ली के कालिंदीकुंज बार्डर पर हुई इस वारदात में शामिल रहे टोल बूथ पर कार्यरत सात बाउंसरों को गिरफ्तार कर कोतवाली सेक्टर-39 पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपितों की पहचान गोवर्धनपुरा सीकर राजस्थान निवासी मनरूप व धर्मपाल, डाबला सीकर राजस्थान निवासी अमित, हरियासर चूरू राजस्थान निवासी चेतन प्रकाश, पडिहारा चूरू राजस्थान निवासी सराजुद्दीन, दादिया सीकर राजस्थान निवासी मनोज व धनौता, महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी कृष्ण कुमार के रूप में हुई। टोल बूथ का मैनेजर अभी फरार है।

महाराष्ट्र की कंपनी के पास है टोल वसूली का ठेका : एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि जांच में पता चला है कि एमसीडी की तरफ से दिल्ली में टोल वसूली का ठेका महाराष्ट्र की कंपनी महाराष्ट्र एंट्री प्वाइंट (एमईपी) के पास है। उसकी तरफ से ही हरियाणा व राजस्थान के इन बाउंसरों को टोल वसूली में लगाया गया था। इन बाउंसरों के अलावा एक टोल का मैनेजर भी वहां था। टोल मैनेजर के ही कहने पर आरोपित अवैध पर्ची काटते थे। इस टोल बूथ पर किसी लोकल गैंग के शामिल होने या संरक्षण की बात से उन्होंने इन्कार किया है।

एक दिन पहले ही समन्वय बैठक में उठा था मुद्दा : एसएसपी ने कहा कि घटना से एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बैठक हुई थी। उस दौरान एमसीडी के टोल पर अवैध तरीके से पर्ची काटकर वसूली का मुद्दा उठा था। इसके अगले ही दिन उसी बात को लेकर विवाद में यह हत्या हो गई। जहां मारपीट हुई, वह एरिया दिल्ली क्षेत्र का है। इस प्रकरण में बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग कर कार्रवाई की जरूरत है। दिल्ली पुलिस से इस कार्रवाई की अपेक्षा है। नोएडा एरिया में अगर कहीं टोल के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत मिलती है तो तत्परता से कार्रवाई होगी। जिस टोल कंपनी ने इन बाउंसरों को रखा था, उसके के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को लिखा जाएगा।

शुक्रवार रात करीब एक बजे हुई थी वारदात : मूलरूप से बलिया निवासी विमल तिवारी सेक्टर-58 स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी में कैंटर चलाते थे और ट्रांसपोर्ट पर रहते थे। शुक्रवार रात वह सेक्टर-59 स्थित एक कंपनी से बिजली का सामान लेकर दिल्ली के घिटोरनी एरिया के लिए चले थे। कालिंदीकुंज बार्डर पर वह एमसीडी का टोल देना भूलकर आगे बढ़ गए थे।

इस बीच टोल बूथ पर मौजूद बाउंसरों ने पीछा कर उन्हें पकड़ा लिया। वे 14 सौ रुपये टोल के बजाय उनसे 10 गुना फाइन सहित कुल 14 हजार छह सौ रुपये की पर्ची कटवाने की मांग करने लगे। विमल ने इसका विरोध किया और कहा था कि उनके पास उतनी रकम नहीं है। इसके बाद आरोपितों ने कैंटर वहीं खड़ा कराकर चालक की डंडों व लात घूसों से पिटाई की थी। मारपीट के बाद जख्मी हालत में विमल को नोएडा एरिया में यमुना पुल के पास फेंककर फरार हो गए थे। मारपीट में विमल की मौत हो गई।

गुरुद्वारों के बाहर जान सकेंगे लंगर का इतिहास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सिख धर्म में लंगर का विशेष महत्व है। लंगर की शुरुआत कैसे हुई इसकी जानकारी देने के लिए दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के आगे विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें बताया जाएगा कि किस तरह से गुरु नानक देव जी ने पिता से व्यापार करने के लिए मिले 20 रुपये से भूखे साधुओं को भोजन कराया था और उसके बाद से लंगर की शुरुआत हुई थी।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर युवा पीढ़ी को लंगर प्रथा के इतिहास से परिचित कराने के लिए विशेष मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम में ऐतिहासिक गुरुद्वारों के बाहर स्टॉल लगाकर लंगर के इतिहास की जानकारी दी जाएगी।

स्टॉल पर विशेष यादगारी पत्र भी मिलेगा, जिससे कि लोग सिख धर्म में लंगर के महत्व को जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू किए गए लंगर की बदौलत ही आज पूरे संसार में सिखों द्वारा लंगर लगाए जाते हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारों में 24 घंटे मुफ्त लंगर चलता है इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं।

मोटी कहने पर पत्नी ने प्रेमी को दी थी हत्या की सुपारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

रिश्तों का खून

▸ प्रबंधक को मारी गई थीं चार गोलियां, दिल्ली निवासी तीनों आरोपित धरे

▸ प्रबंधक के लंच बाक्स से पत्नी ने की थी मुखबिरी, 16 साल पहले हुई थी शादी

सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित ओसिस बिल्डर की साइट पर 23 जुलाई को प्रबंधक को ताबड़तोड़ चार गोलियां मारकर हत्या का प्रयास किया गया था। उपचार के दौरान प्रबंधक की जान बच गई थी। पुलिस ने घटना का पर्दाफाश किया है। प्रबंधक की पत्नी ने पति की हत्या के लिए एक लाख बीस हजार की सुपारी जिम ट्रेनर प्रेमी को दी थी। वह भी महज इस वजह से कि उसका पति उसको कहता था कि कभी देखा है खुद को आइने में, कितनी मोटी लगती हो। आरोपित महिला व प्रबंधक का 16 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। दोनों का पंद्रह साल का बेटा भी है। प्रबंधक के लंच बाक्स से पत्नी ने मुखबिरी कर प्रेमी को बता दिया था कि वह किस साइट पर मिलेगा। खास बात यह है कि आरोपित जिम ट्रेनर प्रेमी का भी नौ साल पहले अन्य महिला से प्रेम विवाह हुआ था। पुलिस ने घटना में शामिल प्रबंधक की पत्नी, उसके प्रेमी जिम ट्रेनर व ट्रेनर के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।

एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि दिल्ली बुराड़ी निवासी राजीव वर्मा को चार गोलियां मारने के आरोप में उनकी पत्नी शिखा, जिम ट्रेनर शिखा के प्रेमी रोहित कश्यप व रोहन उर्फ मनीष को गिरफ्तार किया गया। तीनों ही आरोपित दिल्ली के रहने वाले है। आरोपितों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक व पिस्टल, कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि रोहित ने रोहन के साथ मिलकर प्रबंधक को ताबड़तोड़ गोलियां मारी थीं। दोनों 22 जुलाई को भी प्रबंधक को गोली मारने आए थे, लेकिन उस दिन वह बिल्डर की अन्य साइट पर चले गए थे।

आरोपित रोहित कश्यप ने प्रबंधक की हत्या करने के लिए अलीगढ़ के एक युवक से पिस्टल ली थी। पुलिस जांच में पता चला है कि दो महीने से प्रबंधक की हत्या की साजिश रची जा रही थी। कभी पिस्टल तो कभी अन्य वजह से मामला टल गया।

एक साल पहले प्यार चढ़ा परवान : प्रबंधक की पत्नी शिखा ने एक साल पहले जिम जाना शुरू किया था। वहां उसकी दोस्ती जिम ट्रेनर रोहित कश्यप से हुई। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने मिलकर प्रबंधक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। शिखा ट्रेनर की दूसरी पत्नी के रूप में रहने को तैयार थी। प्रबंधक के ताने के बाद ही उसने जिम जाना शुरू किया था। आरोपित पत्नी ने बताया कि राजीव जब केवल पुरुष कर्मचारी वाली साइट पर जाते थे तो लंच में सिर्फ दो रोटी और सब्जी लेकर जाते थे। जब उस साइट पर जाना होता था, जहां महिला कर्मी भी काम करती थीं तो दो से अधिक रोटी व अच्छी सब्जी लेकर जाते थे। घटना वाले दिन प्रबंधक राजीव केवल दो रोटी लेकर गए थे। इस वजह से वह समझ गई थी कि वह ओसिस बिल्डर की सूरजपुर साइट पर गए हैं। इस पर उसने प्रेमी को बता दिया था कि राजीव कहां मिलेंगे।

पत्नी और प्रेमी के मोबाइल से मिला सुराग : पुलिस जांच में पता चला कि घटना वाले दिन आरोपित पत्नी व प्रेमी के बीच फोन पर कई बार बात हुई। इससे पहले भी दोनों के बीच कई बार बात हुई थी। इस पर पुलिस ने दोनों को पूछताछ कर घटना का पर्दाफाश किया। पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे, इसमें प्रेमी कैद हुआ था।

प्रदर्शनी

दुश्मन पर नजर रखने वाले हथियार देख जोश से भरे लोग

सेना की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में हजारों लोग पहुंचे और अत्याधुनिक हथियारों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए।

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली

सुभाष नगर स्थित पैसेफिक मॉल में भारतीय सेना की ओर से सोमवार को लगाई गई प्रदर्शनी में अत्याधुनिक हथियारों को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। सैन्य कर्मी व अधिकारी प्रदर्शनी में आए लोगों को उपकरणों व हथियारों के बारे में जानकारी भी दे रहे थे। इस प्रदर्शनी हजारों लोग पहुंचे।

बम निष्क्रिय करने के लिए पहननी पड़ती है 44 किलोग्राम की पोषाक : बम को निष्क्रिय करने के दौरान सैन्यकर्मी जिस विशेष पोशाक को पहनते हैं, उसका वजन 44 किलो होता है। भारी-भरकम पोशाक पहनने के बाद शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए इस पोशाक के नीचे शरीर को ठंडक प्रदान करने वाली हल्की पोशाक पहनी जाती है। इसमें पतली पाइप का जाल बिछा होता है, जिसमें ठंडे पानी का प्रवाह होता रहता है।

नाइट विजन कैमरे से 30 किमी तक रखते हैं नजर : सेना की ओर से जिस नाइट विजन कैमरे का इस्तेमाल होता है, उससे 30 किमी तक के दायरे में प्राणी की ओर से की गई हलचल का पता लग जाता है। यह कैमरा जीवित प्राणी के हलचल को ऊष्मा आधारित सेंसर में कैद कर लेता है, जिसकी पूरी छवि कैमरे में नजर आती है।

सुभाष नगर स्थित पैसेफिक मॉल में सोमवार को सेना की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में लोगों ने उपकरणों और हथियारों के बारे में जानकारी ली। हरि प्रकाश

आकर्षण का केंद्र रही बोफोर्स तोप : सैन्य अधिकारियों ने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों पर बोफोर्स तोप ने कहर बरपा दिया था। इसका इस्तेमाल दूर बैठे दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है, जब वे नजर नहीं आते हैं। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 31 किलोमीटर तक होती है। सैन्य अधिकारी ने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन पहाड़ों के पीछे छुपे थे, लेकिन बोफोर्स तोप पहाड़ के पीछे छुपे दुश्मनों को भी जद में ले लेती थी। ऊंचाई पर जाकर बोफोर्स तोप से छोड़ा गया गोला 70 डिग्री का कोण बनाते हुए पहाड़ के उस पार गिरकर दुश्मनों को तबाह कर देता था। इसका इस्तेमाल तीन तरह से हो सकता है। दुश्मनों पर सीधा गोला बरसाने में, धुंध की दीवार खड़ी करने में और रात के समय सेना को अंधेरे में रोशनी प्रदान करने में।

एमपी-9 से एक मिनट में निकलती हैं 1100 गोलियां : प्रदर्शनी में एमपी 9 नामक हथियार भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस अचूक हथियार की रेंज करीब 100 मीटर है। एक मिनट के भीतर इसके बैरल से 1100 गोलियां दागी जा सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें साइलेंसर लगा दिया जाए तो गोली निकलने पर पानी के टपकने जैसी आवाज निकलती है। इसके अलावा इंसास राइफल, सरफेस टू एयर मिसाइल लांचर, मोर्टार जैसे हथियार के बारे में जानने की लोगों में दिलचस्पी थी।

सूट-बूट में आया लुटेरा जगुआर लेकर फरार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आरके पुरम थाना क्षेत्र में गाड़ी में टक्कर मारने के बाद गन प्वांइट पर जगुआर कार लूटने वाले बदमाश महंगी लग्जरी कार को लूटने के इरादे से ही निकले थे। यही कारण था कि चार लुटेरों में से एक सूट-बूट पहने हुए था। वह जगुआर कार लेकर फरार हुआ, जबकि बाकी तीनों लुटेरे अपनी हुंडई वरना कार से ही फरार हुए।

सरिता विहार थानाक्षेत्र में रहने वाले अंकुश मल्होत्रा ने बताया कि 10 अगस्त को वह पत्नी के साथ एक दोस्त की गाड़ी में बैठकर संगम कोटयार्ड, पीवीआर के लिए निकले थे। उनका ड्राइवर जोनू पीछे से उनकी जगुआर कार लेकर आ रहा था। रात करीब साढ़े 12 बजे वह अफ्रीका एवेन्यू मार्ग से वेंकटेश्वर मंदिर मार्ग की तरफ मुड़े। तभी एक सफेद रंग की हुंडई वरना कार ने जगुआर कार में टक्कर मारी। ड्राइवर कार से उतरा, तभी हुंडई वरना सवार चार लुटेरे भी अपनी कार से बाहर आ गए। पहले तो बदमाशों ने माफी मांगी। फिर एक लुटेरे ने ड्राइवर की कनपटी पर पिस्टल तान दी और दूसरे लुटेरे ने जेब से गाड़ी की चाबी निकाल ली।

ड्राइवर ने बताया कि तीन लुटेरे सामान्य कपड़े पहने हुए थे, जबकि एक सूट-बूट पहने हुए था जो जगुआर लेकर फरार हुआ। बाकी तीनों लुटेरे घटनास्थल से अपनी कार मोड़कर विपरीत दिशा में भाग गए। वारदात के बाद पीड़ित ड्राइवर ने मौके से गुजर रही एक कार को रोका और जगुआर कार का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन 100 मीटर बाद ही कार आंखों से ओझल हो गई। इसके बाद पीड़ित ड्राइवर जोनू सड़क किनारे पेट्रोल पंप पर गए और वहां से फोन कर पुलिस व मालिक को वारदात की जानकारी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। शिकायत पर लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

6197 ग्राम पंचायतें है हरियाणा में, जिनमें से 3604 में ड्राप आउट की समस्या खत्म हो गई है। 1108 ग्राम पंचायतों ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। 465 पंचायतें ऐसी हैं, जहां बेटों से अधिक बेटियों ने जन्म लिया अथवा लिंगानुपात पूरी तरह बराबर रहा।

मोदी–चिनफिंग वार्ता में कारोबार होगा मुद्दा

एजेंडा ▸ बीजिंग में हुई वार्ता में भी द्विपक्षीय कारोबार से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सहमति बनी

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच होने वाली दूसरी अनौपचारिक वार्ता का प्रमुख एजेंडा आर्थिक होगा। वुहान (चीन) में अप्रैल, 2018 में इन दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता ने सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर जिस तरह से तनाव को दूर करने का काम किया है, उसी तरह से माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में होने वाली दूसरी वार्ता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों से जुड़ी तमाम अड़चनों को दूर करने वाली साबित हो सकती है। सोमवार को बीजिंग में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की अगुआई में दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता में भी द्विपक्षीय कारोबार से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सहमति बनी है। मोदी और चिनफिंग की बैठक से पहले दोनो देशों के प्रतिनिधियों के बीच इस बारे में अभी और बातचीत होगी।

मोदी और चिनफिंग के बीच पहली अनौपचारिक वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी सेनाओं को साफ निर्देश दिए थे कि वे आपसी भरोसे को मजबूत करें। उसके कुछ ही महीने पहले डोकलाम में दोनो

नरेंद्र मोदी और शी चिनफिंग फाइल फोटो

देशों की सेनाएं तकरीबन ढाई महीने तक एक दूसरे के आमने-सामने रही थीं। उक्त बैठक के बाद से भारत-चीन के बीच तकरीबन 3500 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शांति बनी हुई है।

उस बैठक के बाद चीन ने भारत से चावल समेत कुछ अन्य उत्पादों के आयात के लिए अपने बाजार भी खोले हैं, लेकिन इसका अभी तक द्विपक्षीय कारोबार संतुलन पर असर नहीं पड़ा है। यही वजह है कि भारत दूसरी अनौपचारिक वार्ता में आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रहा है। चीन की तरफ से भी साफ संकेत हैं कि वह भारत की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर संवेदनशील है। दरअसल, अमेरिका के साथ बढ़ते आर्थिक तनाव की वजह से भी चीन भारत की आर्थिक चिंताओं को लेकर अब ज्यादा गंभीर है।

चीन के साथ कारोबार को लेकर भारत की सबसे बड़ी दिक्कत व्यापार घाटे का संतुलन है जो पूरी तरह से चीन के पक्ष में है। 2018-19 में दोनों देशों के बीच करीब 95.5 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ था और इसमें 57 अरब डॉलर का व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में था। यानी भारत से जितना आयात चीन करता है उससे 57.86 अरब डॉलर का निर्यात वह भारत को करता है। चालू वर्ष के पहले दो माह की बात करें तो भारत से चीन को होने वाले निर्यात में और चीन से होने वाले आयात में कमी आई है। भारत से चीन को होने वाले निर्यात में भारी वृद्धि के बगैर व्यापार घाटे की स्थिति में बहुत फर्क नहीं दिख रहा है।

लंबित कारोबारी मुद्दे

- भारतीय आइटी कंपनियों के लिए चीन में कई तरह के अवरोध
- बिना अनुमति भारत के लिए चावल, सोयाबीन जैसे खाद्य उत्पादों का निर्यात करना आसान नहीं
- द्विपक्षीय कारोबार में भारतीय रुपये के इस्तेमाल पर चीन नहीं है तैयार
- अपनी आइटी कंपनी हुवई के लिए चीन चाहता है अनुकूल माहौल
- चीन से आयातित इस्पात व लौह अयस्क पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने पर विचार

अक्टूबर में भारत आ सकते हैं चिनफिंग

जयशंकर ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने चीनी समकक्ष से राष्ट्रपति चिनफिंग की आगामी भारत यात्रा की तैयारी को पुख्ता किए जाने पर बात की। यह तैयारी वुहान सम्मेलन की अगली कड़ी के रूप में हो रही है। माना जा रहा कि चिनफिंग अक्टूबर में वाराणसी की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने संभावित तिथि का उल्लेख करने से इन्कार किया। उन्होंने बताया कि चीन ने मानसरोवर यात्रा को विस्तार देने में भी रुचि दिखाई और व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से बात की।

उच्च शिक्षण संस्थानों को डिजिटल लेनदेन में सुस्ती पड़ेगी भारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : डिजिटल लेनदेन को लेकर सरकार की सक्रियता फिर से सामने आई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से इसके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी मांगी है। साथ ही इनमें फिसड्डी संस्थानों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के भी संकेत दिए हैं। इसमें संस्थानों को मिलने वाली जरूरी मदद भी रोकी जा सकती है।

यूजीसी देश भर के सभी संस्थानों को डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश पहले से दे चुका है। बावजूद इसके हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ बैठक में यूजीसी के सामने कुछ ऐसे मामले सामने आए, जिसमें डिजिटल लेनदेन को लेकर संस्थानों का रवैया सुस्त दिखा है। इसके बाद तो यूजीसी ने सभी संस्थानों से इससे संबंधित ब्योरा देने को कहा है जिसमें पिछले सालों में किए गए डिजिटल लेनदेन सहित संस्थानों में यह व्यवस्था कहां-कहां लागू है, आदि की जानकारी मांगी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में जारी निर्देश में सभी संस्थानों से 16 अगस्त तक पूरा ब्योरा देने को कहा है।

विधायक संगीत सोम से सात मुकदमे वापस लेने की तैयारी

अनुज शर्मा, मेरठ

▸ मुजफ्फनगर दंगा, सहारनपुर और नोएडा में पंचायत करने से संबंधित हैं मामले

उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद भाजपा के तमाम नेताओं से मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। अब फायर ब्रांड नेता और सरधना विधायक संगीत सोम के विरुद्ध कायम मुकदमे वापस लेने की तैयारी है। उन पर 2003 से 2017 के बीच मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और गौतमबुद्धनगर में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान, सहारनपुर और नोएडा में पंचायत कर धारा 144 का उल्लंघन और सरधना से कैराना के लिए पैदल मार्च निकालने पर दर्ज किया गया मुकदमा भी शामिल है। लगभग ढाई साल में भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर दर्ज तमाम ऐसे मुकदमे सरकार वापस ले चुकी है, जो बसपा और सपा सरकार के कार्यकाल में उनके खिलाफ दर्ज हुए थे। इस सूची में संगीत सोम का नाम भी है।

शासन ने मांगी सभी थानों से रिपोर्ट : संगीत सोम के खिलाफ सहारनपुर के देवबंद, मुजफ्फरनगर के खतौली, सिखेड़ा, मेरठ के सरधना तथा गौतमबुद्धनगर के थाना बिसाहड़ा में मामले दर्ज हैं। प्रदेश शासन के विशेष सचिव राम बिलास सिंह ने चारों जिलों से रिपोर्ट मांगी है। शासन ने निर्देश दिया है कि केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण अभियोजन अधिकारी से करा कर अभियोजन की सफलता और दुर्बलता का पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराएं।

सपा और बसपा सरकार में राजनीतिक द्वेष के चलते हमारे खिलाफ जबरन मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनका कोई औचित्य नहीं है। मिरकपुर की पंचायत में जाने पर देवबंद में मुकदमा दर्ज कराया गया। मुजफ्फरनगर में 2013 में आइटी एक्ट में दर्ज मामले में साक्ष्य न होने के कारण पुलिस आज तक चार्जशीट भी नहीं दे सकी। हत्या का विरोध करने तथा पैदल मार्च निकालने पर भी मुकदमे लिख दिए गए। मुकदमा वापसी को लेकर शासन की कार्रवाई की हमें जानकारी नहीं है।
–संगीत सोम, सरधना विधायक

पूर्व चीनी राजदूत ने सीमा को महत्वहीन कहा

राजीव सचान, बीजिंग : चीन भारत से अपने संबंध बेहतर बनाने पर जोर तो दे रहा है, लेकिन भारत की चिंताओं को समझने और आपसी भरोसे को बल देने के लिए सक्रियता दिखाने में जरूरी दिलचस्पी दिखाने से बच रहा है। इसकी एक झलक चीन-भारत मीडिया फोरम के दौरान हुई चर्चा के दौरान भी मिली। इस फोरम पर जब सीमा विवाद में अपेक्षित प्रगति न होने का उल्लेख किया गया तो भारत में चीन के पूर्व राजदूत सुन सेन ने यह हैरान करने वाली टिप्पणी की कि उनकी समझ से तो कोई सीमा होनी ही नहीं चाहिए। उनके मुताबिक सीमा विवाद को लेकर लंबी बातचीत में शामिल रहने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच सीमा का महत्व ही नहीं है। वैसे भी यह हाल के 100-150 सालों का मसला है। भारतीय मीडिया दल ने उनके इस नजरिये का उल्लेख विदेश मंत्री जयशंकर के समक्ष किया, जिसकी उन्होंने हंसकर अनदेखी कर दी।

इस फोरम पर भारतीय मीडिया दल की इस शिकायत का भी कोई समाधान नहीं नजर आया कि ग्लोबल टाइम्स और कुछ अन्य अखबारों के चीनी पत्रकार खुद तो ट्विटर पर मौजूद हैं और टिप्पणियां भी करते रहते हैं, लेकिन चीन आए भारतीय पत्रकारों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ज्ञात हो कि चीन में जी मेल के साथ ट्विटर, वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म प्रतिबंधित हैं। इन तक पहुंच किसी जुगाड़ से ही बनाई जा सकती है और वह भी मुश्किल से।

विफल रहा है कांग्रेस में युवा नेतृत्व का एक दशक का प्रयोग

संजय मिश्र, नई दिल्ली

▸ सोनिया गांधी की वापसी से हुआ तय फिलहाल बुजुर्ग पीढ़ी ही पार्टी की रीति–नीति का करेगी संचालन

मझधार में फंसी अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने के लिए सोनिया गांधी को फिर से पार्टी की पतवार थमा कांग्रेस भले राहत की सांस ले रही हो मगर पार्टी के इस फैसले ने कांग्रेस में युवा नेतृत्व की नाकामी को साबित कर दिया है। बीते एक दशक से नई पीढ़ी को कांग्रेस का भविष्य बनाने का राहुल गांधी का प्रयोग भी विफल हो गया है। इससे यह भी तय हो गया है कि सोनिया गांधी की अगुआई में कांग्रेस की सियासी दशा-दिशा अभी कुछ समय तक पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के हाथों में ही रहेगी।

शनिवार को पुरानी पीढ़ी के नेताओं ने कार्यसमिति की बैठक में गांधी परिवार से बाहर के नेता को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की राहुल गांधी के बार-बार की घोषणाओं को दरकिनार कर दिया। पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी को उनकी अनिच्छा के बावजूद दुबारा अध्यक्ष बनने के लिए राजी कर लिया। 1998 में भी वह अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं थीं और राहुल ने भी उनके सक्रिय राजनीति में आने का विरोध किया था। सीताराम केसरी के बाद अध्यक्ष बनी सोनिया ने राहुल की राजनीति का रास्ता बनाते हुए उन्हें कांग्रेस की कमान भी सौंपी।

सोनिया की इस सियासी सफलता में जाहिर तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और रणनीतिकारों की अहम भूमिका रही। मगर राहुल के नेतृत्व संभालने के बाद से ही पार्टी में बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के बीच एक खाई बन गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इस खाई को बढ़ाने में हाई प्रोफाइल संस्थानों से पढ़कर आए राहुल के युवा सलाहकारों के साथ कुछ नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। अविश्वास इतना गहरा हो गया कि वरिष्ठ नेता अपनी तरफ से किसी तरह की पहल करने से भी बचने लगे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सियासी लड़ाई में राहुल का अकेले पड़ने की व्यथा इसका साफ सबूत थी। राहुल ने कार्यसमिति को सौंपे इस्तीफे में भी इसका जिक्र किया है। राजनीतिक लिहाज से राहुल की सियासी विफलता में युवा और बुजुर्ग पीढ़ी के नेताओं के बीच 2007 के बाद शुरू हुआ अंदरूनी संघर्ष बड़ी वजह रही। तब पहली बार कांग्रेस महासचिव बने राहुल ने पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र की महात्वाकांक्षी पहल शुरू करते हुए युवा और छात्र संगठनों के पदों पर चुनाव कराने का सिलसिला शुरू किया। इस प्रयोग को वह कांग्रेस के शीर्ष स्तर पर भी लाना चाहते थे और वरिष्ठ नेताओं की पीढ़ी इससे असहमत थी। 2014 के जनवरी में राहुल ने बतौर उपाध्यक्ष पार्टी की कमान व्यावहारिक रूप से अपने हाथों में ली उसके बाद पार्टी की बुजुर्ग पीढ़ी में असुरक्षा की भावना कहीं ज्यादा बढ़ती गई। पार्टी में पीढ़ियों के इस टकराव का ही नतीजा रहा कि संगठन के सीधे चुनाव तो दूर राहुल अपनी कार्यसमिति का चुनाव भी नहीं करा पाए। कांग्रेस में राहुल ब्रिगेड के युवा नेताओं की फौज बीते एक दशक से सुर्खियों में जरूर चमकती रही है मगर सचिन पायलट जैसे अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश चेहरे सियासी जमीन पर अपना प्रभाव जमाने में नाकाम ही रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, दीपेंद्र हुड्डा और जितिन प्रसाद जैसे कुछ चेहरे जिन्होंने राष्ट्रीय पहचान बनाई भी है उसमें उनकी जमीनी सियासत से ज्यादा पारिवारिक सियासी विरासत का योगदान रहा है।

पार्टी की यह युवा पीढ़ी भी मौजूदा संकट के दौर में राजनीतिक वापसी की राह बनाने के लिए फिर से सोनिया के नेतृत्व में ही उम्मीद देख रही है। सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले के बाद युवा पीढ़ी ब्रिगेड के नेताओं की उत्साहित प्रतिक्रिया इसी ओर इशारा करती है। अपना राजनीतिक भविष्य बचाने में कांग्रेस की बुजुर्ग पीढ़ी कामयाब दिख रही है। मगर पार्टी की दीर्घकालिक सियासत को अंधकार के लंबे दौर से बचाने के लिए नई पीढ़ी के जमीनी नेतृत्व की अनदेखी महंगी पड़ सकती है।

अयोध्या सिर्फ जमीन का विवाद नहीं, आस्था का मामला

माला दीक्षित, नई दिल्ली

▸ फैजाबाद अदालत ने इसे रिप्रजेंटेटिव सूट किया था घोषित
▸ अदालत ने पब्लिक नोटिस जारी कर दोनों समुदायों को बनाया था पक्षकार

सुप्रीम कोर्ट में आजकल अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई चल रही है। कहने को तो यह विवादित जमीन पर मालिकाना हक का मुकदमा है, लेकिन असल में यह हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच आस्था से जुड़ा मुद्दा है। कानून की निगाह में यह रिप्रजेंटेटिव सूट है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की ओर से प्रतिनिधि पक्षकार हैं। फैजाबाद की जिला अदालत ने आदेश जारी कर इसे रिप्रजेंटेटिव सूट (प्रतिनिधि वाद) घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई का पांचवा दिन होगा। आजकल भगवान रामलला की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 1961 में फैजाबाद की जिला अदालत में मुकदमा दाखिल कर मांग की थी कि उसे संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए और कब्जा दिलाया जाए। बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी बताते हैं कि बोर्ड ने अन्य आठ याचिकाकर्ताओं के साथ पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए (रिप्रजेंटेटिव) की हैसियत से पूरे हिंदू समुदाय के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। बोर्ड की अर्जी पर ही अदालत ने मुकदमें को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच रिप्रजेंटेटिव सूट बनाने का आदेश दिया था। किसी मुकदमे को दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश एक नियम आठ के तहत रिप्रजेंटेटिव सूट बनाया जाता है।

कोर्ट के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व और मुकदमें में हिंदू पक्षकार को हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व बनाया था। हिंदू पक्षकार ने कहा कि वह पूरे हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है। इसके बाद 20 मार्च, 1963 को कोर्ट के आदेश पर हिंदू महासभा, सनातन सभा और आर्यसमाज को हिंदुओं की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर मुकदमें में शामिल करने का अखबार में नोटिस जारी हुआ। हालांकि, सनातन सभा और आर्यसमाज पक्षकार बनने के लिए आगे नहीं आए। इस तरह अयोध्या राम जन्मभूमि मामला महज जमीन पर मालिकाना हक का मुकदमा नहीं रह गया, बल्कि दो समुदायों के बीच मुकदमा बन गया है और जो भी फैसला आएगा वह दोनों समुदायों पर बाध्यकारी होगा। जिला अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि चारों मुकदमें एक साथ सुने जाएंगे और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुकदमा लीडिंग केस होगा।

स्वामी परमात्मानंद बोले मुसलमान करें राममंदिर निर्माण की पहल

बिजेंद्र बंसल, लंदन: अखिल भारतीय हिंदू धर्मचार्य महासभा के संयोजक एवं महामंत्री स्वामी परमात्मानंदजी महाराज का कहना है कि मुस्लिम समाज स्वयं आगे आकर अयोध्या में राममंदिर निर्माण की पहल करे।

लंदन में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हिस्सा लेने के पहुंचे परमात्मानंद जी दैनिक जागरण से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय चमत्कारिक है। वर्षों पुरानी समस्या का एक झटके में समाधान करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह में संत समाज का विश्वास बढ़ा है। संत समाज जानता है कि कश्मीर मुद्दे का हल यही है कि वहां के लोगों खासतौर पर युवाओं को हम भारत दर्शन कराएं। उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करें। एक साल के अंदर कश्मीर घाटी का भटका युवक भी देश की मुख्यधारा से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि राममंदिर निर्माण में जो अड़चनें आ रही थीं, वे राजनीतिक थीं। मोदी सरकार में राममंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हमें विश्वास है कि शीघ्र ही राम मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सवाल पर उन्होंने कहा कि संत समाज का भी कोर्ट पर भरोसा है। हम मानते हैं कि जिस तरह के तथ्य हिंदू समाज के पास हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट भी राममंदिर बनाने के हक में फैसला देगा। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के पक्ष से आहत हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा।

कालेश्वरम प्रोजेक्ट का भूमिगत पंपिंग स्टेशन बनकर तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : तेलंगाना में विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम प्रोजेक्ट (केएलआइपी) के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन लक्ष्मीपुर भूमिगत पंपिंग स्टेशन (एलयूपीएस) का निर्माण पूरा हो गया है। इसके चालू होने पर राज्य के भूजल स्तर में वृद्धि होने से खेतीबाड़ी के अलावा मत्स्यपालन और पर्यटन संबंधी गतिविधियों का विस्तार होगा जिससे राज्य के लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।

केएलआइपी का महत्वपूर्ण अंग माना जाने वाला ये विशाल पंप हाउस किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया का ये सबसे बड़ा भूमिगत पंपिंग स्टेशन है, जिसे पृथ्वी की सतह से 470 फीट नीचे बनाया गया है। करीमनगर जिले के लक्ष्मीपुर गांव के रामादुगु में निर्मित ये भूमिगत पंपिंग स्टेशन गोदावरी रिवर बेल्ट में पूरे साल कई जलाशयों में पानी का भंडारण करेगा। परियोजना में तेलंगाना की पूरी रूपरेखा बदल देने की क्षमता है। अनोखे पंप हाउस के जरिए गोदावरी के पानी की पंपिंग होने से सूखे इलाके जीवंत होकर हरे-भरे हो जाएंगे। इसके निर्माण से जुड़ी कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआइएल) के निदेशक श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पंप हाउस में 139 मेगावाट क्षमता वाली सात मोटर हैं जो प्रतिदिन तीन टीएमसी पानी उठा सकती हैं।

एनआइए को मिले और अधिक अधिकार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और अधिक अधिकार देने वाला एनआइए संशोधन विधेयक 15 जुलाई को लोकसभा से और 17 जुलाई को राज्यसभा से पारित हो गया है। इस नये कानून के तहत एनआइए को साइबर अपराधों और मानव तस्करी के मामलों की जांच का अधिकार और विदेशों में किसी भारतीय या भारतीय हितों पर हमलों की जांच का अधिकार भी मिल गया है।

बढ़ा जांच का दायरा

एनआइए एक्ट 2008 में संशोधन किया गया है ताकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सूचीबद्ध अपराधों की जांच करने और केस चलाने के अधिकार मिल सके। नये कानून के तहत एनआइए को मानव तस्करी, नकली नोट चलाने, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण और बिक्री, एक्सप्लोसिव्स सब्सटेंसेज एक्ट, 1908 के तहत अपराधों और साइबर आतंकवाद से जुड़े विषयों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। यहीं नहीं एनआइए एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 जैसे कानूनों के तहत अपराधों की जांच भी कर सकेगी।

विदेश में भी कर सकेगी जांच

इस नये कानून के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआइए को भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जांच करने का अधिकार मिल गया है। वह अब आतंकवाद से जुड़े मामलों के अलावा दूसरे तमाम तरह के अपराधों की जांच भी कर सकेगी।

विशेष अदालतें होंगी गठित : इस नये कानून में केंद्र सरकार को विशेष अदालतें गठित करने का भी अधिकार मिला है ताकि अनुसूचित अपराधों के मामलों पर केस चलाया जा सके। केंद्र सरकार विशेष अदालत बनाने से पहले उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करेगी।

मुंबई हमले के बाद हुई स्थापना

26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद एनआइए एक्ट 2008 के तहत 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली आतंकी गतिविधियों जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की जांच करना है।

इन राज्यों में है शाखाएं

एनआइए की देश के कई राज्यों में शाखाएं हैं। इनमें लखनऊ, हैदराबाद, कोच्चि, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू राज्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़, श्रीनगर, चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, भरूच, जगदलपुर, पटना, सिलीगुड़ी, मालदा, रांची, विजयवाड़ा और इंफाल में इसके कैंप ऑफिस हैं। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है।

देश को तकनीकी तौर पर समृद्ध बनाने में साराभाई का विशेष योगदान : पीएम

अहमदाबाद, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रणेता रहे विक्रम साराभाई को 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा कि उनके विजन की बदौलत ही भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विश्व में अपना स्थान बनाने में सफल रहा है। बता दें कि साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था।

साराभाई के जन्मशती वर्ष पर सालभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की शृंखला में से एक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, 'हम एक खास मौके पर साराभाई की जन्मशती मना रहे हैं। यह ऐसे समय पड़ी है जब भारत कुछ दिनों बाद चांद पर फिर से कदम रखने वाला है। जब अगले महीने विक्रम लैंडर (चंद्रयान-2) चांद पर पहुंचेगा तो यह 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से साराभाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।' साराभाई के शुरुआती दिनों को याद करते हुए मोदी ने कहा कि किस तरह केरल के थुंबा से लांच किया गया पहला रॉकेट आज की रॉकेट तकनीक का आधार बन गया। इनका उपयोग चंद्रमा और मंगल मिशनों को लांच करने के लिए किया जा रहा है। डॉ. साराभाई ने हमारे अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम को एक नई दिशा दी। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतरिक्ष विभाग, साराभाई द्वारा स्थापित अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और परमाणु ऊर्जा विभाग ने किया था।

दुष्कर्म मामलों के लिए गठित होंगी 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : देशभर में दुष्कर्म से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे के लिए 1,023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की प्रक्रिया दो अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। कानून मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। कानून मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने 767.25 करोड़ के बजट से इन अदालतों के गठन का प्रस्ताव किया था। एक साल के लिए केंद्र सरकार निर्भया कोष से इसमें 474 करोड़ रुपये की मदद देगी। इस कोष की स्थापना केंद्र सरकार ने 2013 में दिल्ली की छात्रा के साथ 16 दिसंबर, 2012 को हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद की थी। इस कोष का मकसद महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में किए जाने वाले सरकार और गैरसरकारी संगठनों के कार्यों में मदद करना है।

▸ दो अक्टूबर से गठन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना
▸ 767.25 करोड़ के बजट से हैं इनके गठन का प्रस्ताव

न्याय विभाग की ओर से आठ अगस्त को कैबिनेट सचिवालय को लिखे पत्र में कहा गया है कि 11 जुलाई को व्यय वित्त समिति की सिफारिश और कानून मंत्रालय के अनुमोदन के बाद यह मामला मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। विभाग ने लिखा है, 'साथ ही साथ इसे जुड़ी अन्य कार्रवाइयां भी की जा रही हैं क्योंकि फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन का कार्य दो अक्टूबर, 2019 से शुरू करने की योजना है।' महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि पहले चरण में नौ राज्यों में ऐसी 777 अदालतें गठित की जा सकती हैं और दूसरे चरण में 246 अदालतों का गठन किया जाएगा। मालूम हो कि संसद ने हाल ही में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है। इन संशोधनों में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने पर मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है।

कांट्रैक्ट वाले वैज्ञानिकों के भरोसे होंगे कृषि अनुसंधान

नई व्यवस्था

निश्चित अवधि के लिए होगी नियुक्ति और मिलेगा एकमुश्त वेतन, कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों में स्थायी नियुक्तियों पर रोक

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

कृषि और संबद्ध उद्यम के भरोसे किसानों की आमदनी बढ़ाने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए कांट्रैक्ट (संविदा) पर कृषि वैज्ञानिकों की तलाश की जा रही है। कृषि अनुसंधान संस्थानों और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में इसके तहत भर्ती होने वाले वैज्ञानिकों और प्राध्यापकों को वेतन एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। कई संस्थानों के विज्ञापनों के बाद भी अस्थाई नौकरी के लिए वैज्ञानिक नहीं मिल रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपने सभी अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में पहले से नियुक्त प्रोफेसर और वैज्ञानिकों के रिटायर होने के बाद रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति न करने को कहा है। इन सभी पदों पर अस्थायी समयबद्ध नियुक्तियों करने का निर्देश दिया है। ज्यादातर संस्थानों व विश्वविद्यालयों में खाली पदों के विपरीत अस्थायी नियुक्तियां की जा रही हैं। हालांकि इसे लेकर कृषि क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान के प्रभावित होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुल ऐसे 35 पदों में से 25 प्राध्यापक रिटायर हो चुके हैं। इन खाली पदों पर स्थायी नियुक्तियां करने से आईसीएआर ने मना कर दिया है। इन पदों पर केवल अस्थायी यानी कांट्रैक्ट पर नियुक्तियां की जा सकेंगी। कमोबेश यही हाल सभी संस्थानों का है, जहां स्थायी भर्तियां नहीं हो रही है।

इसी तरह का दूसरा नमूना कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) की वेबसाइट पर झांसी के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का एक विज्ञापन दर्ज है। इस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा पाये छह साल होने को हैं, लेकिन अभी तक यहां प्राध्यापकों व अन्य कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती तक नहीं हो सकी है। बताया गया कि इसकी राह में आईसीएआर की अधिसूचना आड़े रही है, जिसमें केवल कांट्रैक्ट पर निश्चित समय के लिए नियुक्ति की अनुमति दी गई है।

विज्ञापन के मुताबिक स्वायल साइंस, एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, एग्रोफॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट विभाग में प्राध्यापक और रिसर्च एसोसिएट की जरूरत है। यानी सभी विभागों में शिक्षकों व वैज्ञानिकों की सख्त कमी है। सारे पद विशुद्ध रूप से कांट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएंगे। वह भी वर्ष 2019-20 के शिक्षा सत्र के लिए ही होंगे। इसके लिए एकमुश्त 40 हजार रुपये का वेतन दिया जाएगा। पीएचडी के साथ अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिये जाने की बात कही गई है।

एसजीआरसी का निर्देश नहीं मानने पर खत्म हो सकती है इंजीनियरिंग कॉलेजों की संबद्धता

नई दिल्ली, प्रेट्र : छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) की सिफारिश का पालन करने में विफल रहने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी संस्थानों की मान्यता और संबद्धता वापस ली जा सकती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के नए नियमों के मसौदे के अनुसार, ऐसे कॉलेजों और संस्थानों का अनुदान भी रोका जा सकता है।

तकनीकी शिक्षा नियामक ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (छात्रों की शिकायतों का निवारण) नियम 2019 का मसौदा तैयार किया है। इसका लक्ष्य एआइसीटीई मंजूर तकनीकी संस्थानों से संबंधित छात्रों की शिकायतों का समाधान करना है। मसौदे पर लोगों से 20 अगस्त से पहले राय और सुझाव मांगे गए हैं।

मसौदे में कहा गया है, 'कोई तकनीकी शिक्षण संस्थान जानबूझकर अवहेलना या लगातार अध्यक्ष या छात्र शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों का पालन करने में विफल रहता है तो परिषद कार्रवाई करेगा। संस्थान को दी गई मंजूरी, सक्षम होने की घोषणा या परिषद से अनुदान या वित्तीय सहायता लेने की योग्यता वापस लेने और संस्थान को आवंटित अनुदान रोकने की कार्रवाई की जा सकती है।'

नियम के मुताबिक, एआइसीटीई से मंजूर हर संस्थान को छात्र शिकायत निवारण समिति का गठन करना है। यह समिति संस्थान से संबंधित छात्र की शिकायत का निपटारा करेगी और अपनी सिफारिशों के साथ 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

134 साल की कांग्रेस में अब तक 88 अध्यक्ष चुने गए हैं। 1885 में गठित कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। सोनिया गांधी सबसे ज्यादा 19 वर्ष तक पार्टी की अध्यक्ष रहीं।

बिहार में महागठबंधन लेगा सोनिया की असली परीक्षा

अरविंद शर्मा, पटना

- राज्य में अलग-अलग पगडंडियों पर चल रहे महागठबंधन के घटक दलों को एकजुट करना बड़ी चुनौती
- लोकसभा चुनाव में राहुल और तेजस्वी नहीं दिखा पाए थे कमाल

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। फाइल फोटो

भाजपा विरोधी दलों के लिए सियासी रूप से मुश्किल घड़ी में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की दोबारा कमान संभाल तो ली है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के साथी दल ही उनका असली इम्तिहान लेंगे। फिलहाल सोनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार में अलग-अलग पगडंडियों पर चल रहे महागठबंधन के घटक दलों को दोबारा इकट्ठा करना है।

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में लोकसभा चुनाव की शिकस्त ने पहले से ही विपक्ष की सियासत को अस्त-व्यस्त कर रखा है। तीन तलाक और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर मिली मात ने भी उन्हें रास्ते से भी भटका दिया है। आपस में कोई समन्वय और संवाद नहीं है। केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के शांत माहौल ने भी गठबंधन के नेताओं को बेचैन कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस में भी कलह खुलकर सामने आ रही है। कई नेता छोड़कर जाने के रास्ते पर हैं। पूर्व प्रदेश सचिव देवेंद्र प्रसाद सिंह ने पी. चिदंबरम और दिग्विजय सिंह के बयान को सांप्रदायिक और देश विरोधी करार दिया है।

बिखरे कुनबे को एक करना आसान नहीं : हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) प्रमुख जीतनराम मांझी गठबंधन के अस्तित्व को नकार रहे हैं। उनके बयानों में राजद-कांग्रेस से बढ़ रही दूरी साफ झलक रही है। तेजस्वी यादव की गतिविधियों से लगता है कि राजनीति से उन्हें ज्यादा वास्ता नहीं रह गया है। नई दिल्ली में नया बसेरा बना लिया है। राजद के कार्यक्रमों से भी खास मतलब नहीं रह गया है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी का बयान विपक्ष में उम्मीद जगाता है। बकौल कादरी, सोनिया के आने से निराशा का भाव खत्म हो जाएगा। विपक्ष को संजीवनी मिल जाएगी। लालू प्रसाद के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। सबको साथ लेकर चलना बेहतर जानती हैं। कादरी के बयान से राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि सोनिया का असर बिहार में कांग्रेस पर पड़ सकता है, किंतु गठबंधन पर कुछ खास नहीं।

राहुल के वक्त भी एक नहीं था विपक्ष : बिहार की विपक्षी सियासत को राहुल गांधी से भी ज्यादा संबल नहीं मिल सका था। कांग्रेस की कमान 19 महीने राहुल के पास रही है। लगभग इसी दौरान बिहार की सत्ता से भाजपा-जदयू गठबंधन को बेदखल करने के मकसद से लोकसभा चुनाव के पहले पांच दलों ने मोर्चा बनाया। बड़े-बड़े दावे किए। सियासी जोड़-तोड़ कर कुछ छोटे दलों को भी साथ लाए। मजबूत विकल्प के इरादे जताए, लेकिन सपने सच नहीं हुए। न तो महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र बना, न समन्वय समिति बनी और न ही कोई संयुक्त बैठक हुई। प्रचार के दौरान भी दरार, तकरार और दूरियां सामने आने लगीं। यहां तक कि लोकसभा की नौ सीटें लेने में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। भाजपा छोड़कर कांग्रेस की शरण में गए कीर्ति झा आजाद को दरभंगा से बेदखल होना पड़ा। सुपौल सीट के लिए राजद मचल गया। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ राजद के स्थानीय नेताओं ने बगावत कर दी।

अनुच्छेद 370 ने बिगाड़ा सियासी दलों का सुर-ताल

राज्य ब्यूरो, पटना

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बिहार के सियासी दलों के सुर-ताल बिगड़ गए हैं। कुछ ने गहरी चुप्पी ओढ़ ली है, तो कुछ मुखर हैं। किसी-किसी दल के सिर्फ प्रवक्ता बोल रहे हैं, जबकि शीर्ष नेताओं ने खुद को किनारा कर लिया है। सबसे आश्चर्यजनक स्थिति जनाधिकार पार्टी (जाप) के मुखिया राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की है। घर में ही दो तरह की विचारधारा है। पति ने पहले खुलकर विरोध किया, तो पत्नी रंजीत रंजन ने समर्थन।

हालांकि, हालात के हिसाब से बाद में पप्पू यादव के स्वर बनते-बिगड़ते रहे। आठ अगस्त को केंद्र सरकार के फैसले को हिटलरशाही करार देने के महज दो दिन बाद ही उन्होंने भरपाई करने की कोशिश की और कहा कि वह अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तरीके का विरोध किया है। सबसे ज्यादा चर्चा पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रंजीत रंजन के बयान की हुई। उन्हें सोनिया गांधी की करीबी माना जाता है, लेकिन उन्होंने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनार्दन द्विवेदी की तरह पार्टी लाइन से अलग बयान दिया और 370 हटाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसे तो हटना ही था, क्योंकि यह व्यवस्था देश हित में नहीं थी। रंजीत का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है कि विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा को छोड़कर प्रदेश कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने मुंह खोलना उचित नहीं समझा। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी नहीं। राजद में लालू परिवार के स्टैंड की भी कम चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी, विधायक भाई वीरेंद्र एवं शक्ति सिंह यादव ने विरोध में बयान जारी किया, लेकिन लालू परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से न बयान आया, न ही ट्वीट किया गया। असमंजस की स्थिति सिर्फ विपक्षी खेमे में ही नहीं रही, सत्तारूढ़ जदयू ने भी वक्त की नजाकत को समझते हुए मुख्यधारा की सियासत को स्वीकार कर लिया।

बंगाल में बुजुर्ग नेताओं के बदले युवाओं को तरजीह देगी माकपा

जासं, कोलकाता : लोकसभा चुनाव में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन से चिंतित माकपा बंगाल में बड़ा सांगठनिक बदलाव करने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने अंततः बुजुर्ग नेताओं के बदले युवाओं को तरजीह देने का मन बनाया है। मई के बाद से अब तक माकपा की राज्य कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं। इनमें तय किया गया कि पार्टी में बदलाव सिर्फ जमीनी व मध्यम स्तर पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि शीर्ष स्तर पर भी फेरबदल की जरूरत है। माकपा ने दूसरे राजनीतिक दलों की तरह सोशल मीडिया के जरिए भी जनता से जुड़ने की योजना बनाई है। माकपा पोलितब्यूरो के सदस्य हन्नान मोल्ला ने कहा, 'पार्टी असाधारण परिस्थितियों से गुजर रही है इसलिए इससे निकलने के लिए उपाय भी असाधारण ही करने होंगे। पहले पार्टी के लिए सिर्फ तृणमूल खतरा थी, अब भाजपा के साथ उसे दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।' मोल्ला ने आगे कहा, 'हमें पार्टी में युवाओं को नेतृत्व सौंपना होगा, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ जन आंदोलन की अगुआई कर संगठन का कायाकल्प कर सके।'

न्यूज गैलरी

मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए आज करेंगे नामांकन

जयपुर : पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह मंगलवार को राज्यसभा के लिए नामांकन-पत्र दाखिल करेंगे। वह इस बार असम के बजाय राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे। मनमोहन सिंह अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। राजस्थान में भाजपा के मदनलाल सैनी के निधन के बाद खाली हुई सीट से कांग्रेस उनको राज्यसभा भेजना चाहती है। राजस्थान विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के लिहाज से भाजपा पर कांग्रेस भारी है। हालांकि, उनकी जीत पक्की करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को बसपा विधायकों से चर्चा की। गहलोत ने निर्दलीय विधायकों से भी फोन पर बात की है। (जासं)

प्रियंका के सोनभद्र दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट

सोनभद्र : उप्र के सोनभद्र स्थित उभ्भा में हुए नरसंहार के 27 दिन बाद मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यक्रम यहां लगा है। इससे नरसंहार का मामला फिर गरमाने की बात कही जा रही है। वह दोपहर एक बजे नरसंहार के पीड़ितों से मिलने के लिए उभ्भा गांव पहुंचेंगी। प्रियंका के आने को लेकर वाराणसी के साथ ही सोनभद्र का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट है। वह लगातार शासन के संपर्क में है। वाराणसी, सोनभद्र, मीरजापुर और भदोही के साथ ही पूरे पूर्वांचल के कांग्रेसजन मुस्तैद हो गए हैं। पुलिस-प्रशासन भी पूरी तरह से चौकन्ना है। सोमवार को एसपीजी के साथ ही अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल देखा। गौरतलब है कि घटना के दो दिन बाद ही 19 जुलाई को प्रियंका पीड़ितों से मिलने के लिए आ रही थीं लेकिन उन्हें नारायणपुर में रोक दिया गया था। इस दौरान वह वहीं धरने पर बैठ गईं। इसके बाद उन्हें नारायणपुर से चुनार स्थित अतिथि गृह ले जाया गया। जहां उन्होंने रात गुजारी। वहीं पहुंची उभ्भा गांव की पीड़ित चार महिलाओं से मिलकर वापस चली गई थीं। (जासं)

थरूर ने जेटली के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

नई दिल्ली, : कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि उन्हें अपने विश्वविद्यालय समकालिक और मित्र अरुण जेटली के स्वास्थ्य की स्थिति से राहत मिली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हालत स्थिर बताई है। ट्विटर पर तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ वह फिर से राजनीतिक बयान देते नजर आएंगे। थरूर ने ट्वीट किया, 'एम्स से तीसरे दिन विश्वविद्यालय समकालिक और अपने मित्र अरुण जेटली का स्वास्थ्य स्थिर रहने की रिपोर्ट से राहत मिली है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने और उनके खिलाफ राजनीतिक बयान देते नजर आने की कामना करता हूं।' (एएनआइ)

पलटवार ▶ दुर्गा पूजा समितियों को आयकर नोटिस भेजने पर बंगाल में सियासी उबाल

चिटफंड के पैसों से नहीं होगी दुर्गा पूजा सभी को मानना होगा कानून : बाबुल

दुर्गा पूजा बंद करवाने के तृणमूल के आरोपों का केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बाबुल सुप्रियो फाइल फोटो

ममता बनर्जी फाइल फोटो

दुर्गा पूजा समितियों को आयकर नोटिस भेजे जाने को लेकर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए सोमवार को कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार राज्य में दुर्गा पूजा बंद करना चाहती है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि अब तक चिटफंड के पैसों से दुर्गा पूजा होती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सभी को कानून का पालन करना होगा।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का एक तबका चिटफंड घोटालों से अर्जित काले धन को पूजा समितियों के जरिये सफेद करने में लगा है। ममता ने कहा था कि त्योहारों को कर के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। तृणमूल केंद्र के इस कदम के खिलाफ 13 अगस्त को महानगर में धरना देगी। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि अगर आयकर विभाग दुर्गा पूजा समितियों में धन का प्रवाह संबंधी मामले को देख रहा है तो इसमें नुकसान क्या है? कुछ पूजा समितियों में तृणमूल के वरिष्ठ नेता और मंत्री अहम पदों पर हैं तथा वे इसका इस्तेमाल चिटफंड घोटालों और कट मनी से बनाए गए काले धन को सफेद करने में कर रहे हैं। तृणमूल को भय है कि नोटिस से उनका यह खेल कहीं सामने न आ जाए।

भाजपा नेता ने दुर्गा पूजा समितियों को लेकर ममता की चिंता को घड़ियाली आंसू करार देते हुए कहा कि अगर उन्हें इन समितियों की इतनी ही चिंता है तो उनकी सरकार ने अनेक बार राज्य में मोहर्रम के लिए दुर्गा पूजा से जुड़े आयोजनों को रोकने की कोशिश क्यों की?

ममता ने की थी आलोचना

रविवार को दुर्गा पूजा समितियों को आयकर नोटिस भेजे जाने पर ऐतराज जताते हुए ममता बनर्जी ने इसकी आलोचना की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि आयकर विभाग ने कई समितियों को नोटिस जारी कर उन्हें कर चुकाने को कहा है। यह त्योहार सबके लिए है और हम नहीं चाहते कि किसी भी पूजा महोत्सव पर कर लगे।

अमित शाह के पत्र में गोरखालैंड शब्द के इस्तेमाल पर छिड़ा विवाद

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- तृणमूल ने केंद्रीय गृह मंत्री के पत्र में गोरखालैंड लिखने पर उठाया सवाल

दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट के पत्र के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भेजे गए पत्र में 'गोरखालैंड' शब्द के उल्लेख से विवाद पैदा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को इसमें राज्य को बांटने की साजिश नजर आ रही है। हालांकि, भाजपा ने इस आरोप को 'बेबुनियाद' करार दिया है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, बिष्ट ने जुलाई में शाह को पत्र भेज कर दिल्ली में खासतौर पर पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले नस्ली भेदभाव का मुकाबला करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई विशेष शाखा के दायरे से गोरखाओं को बाहर रखने को लेकर चिंता प्रकट की थी। शाह ने बिष्ट के पत्र के जवाब में कहा कि 'गोरखालैंड और लद्दाख' के लोगों को लेकर उनकी चिंता पर गौर किया जा रहा है।

शाह द्वारा 'गोरखालैंड' शब्द का इस्तेमाल किए जाने की तृणमूल कांग्रेस ने आलोचना की है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री गौतम देब ने कहा, 'उन्होंने गोरखालैंड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। पूरे क्षेत्र में गोरखालैंड नाम की कोई जगह नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि जम्मू-कश्मीर को बांटने के बाद भाजपा बंगाल को विभाजित करने की योजना बना रही है, लेकिन जब तक यहां तृणमूल कांग्रेस है, राज्य को कोई बांट नहीं सकता।'

वहीं, बिष्ट ने कहा कि गोरखालैंड शब्द के इस्तेमाल का पृथक राज्य के गठन से कोई लेना-देना नहीं है। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) 2011 में तृणमूल कांग्रेस सरकार, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद बना था। ऐसे में यदि वे लोग गोरखालैंड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इस क्षेत्र के बाशिंदों को संबोधित करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं।

अब राजनीति के दंगल में उतरीं कुश्ती खिलाड़ी बबीता फौगाट

अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फौगाट और उनके पिता महावीर फौगाट ने सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फौगाट और उनके पिता द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर फौगाट सोमवार को भगवा रंग में रंग गए। बबीता फौगाट ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा, जबकि उनके पिता ने जननायक जनता पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर भाजपा में आस्था जताई। फौगाट परिवार कई मोर्चों पर प्रदेश सरकार से टक्कर लेते रहा है। कई सार्वजनिक मंचों पर मनोहर सरकार की आलोचना की, लेकिन सोमवार को बदले घटनाक्रम में दोनों पिता-पुत्री ने सरकार की जमकर तारीफ की।

दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, भाजपा के हरियाणा प्रभारी डॉ. अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में फौगाट पिता-पुत्री ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बबीता के दादरी या बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के आसार हैं। फौगाट परिवार शुरू से ही इनेलो के साथ जुड़ा रहा है। इनेलो के दोफाड़ होने के बाद यह परिवार दुष्यंत चौटाला के समर्थन में जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गया था, लेकिन अब उसे भी छोड़ दिया। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि महावीर सिंह देश के लिए मिसाल हैं। बबीता भाजपा में आकर भी मैरी कॉम की तरह खेल सकती हैं। 29 वर्षीय बबीता ने वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। वर्ष 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता।

अनुच्छेद 370 खत्म करने की तारीफ, मुख्यमंत्री का किया बचाव : बबीता ने हाल ही में ट्वीट कर मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 खत्म करने का स्वागत किया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि देश की आजादी देखने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने हरियाणवी में कहा था कि लठ गाड़ दिया, धुम्मा ठा दिया। बबीता ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कश्मीरी लड़कियों के संबंध में दिए गए बयान पर लिखा था कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जिसमें हमारी बहन-बेटियों के बारे में गलत बोला गया हो।

एक-एक इंच जमीन खरीदकर बनाया जौहर विवि : आजम

जागरण संवाददाता, रामपुर

उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा सांसद आजम खां एक माह के बाद नजर आए। सोमवार को वह ईदगाह में विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ ईद की नमाज पढ़ने पहुंचे। जागरण

किसानों की जमीन कब्जाने के आरोपों में फंसे सपा सांसद आजम खां ने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। हमने यूनिवर्सिटी के लिए एक-एक इंच जमीन खरीदी है। वह सोमवार को बकरीद पर ईदगाह में नमाज के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। बोले, कुर्बानी का मौका है, जिसकी जितनी कुर्बानी हो जाए अच्छा है।

उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है। सारे मुकदमे यूनिवर्सिटी पर हैं, बच्चों के स्कूलों पर हैं। प्रशासन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में डाका मारा गया था। हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की 40 से ज्यादा रूलिंग दी है, जिसमें यह बात कही है कि तीन साल के बाद किसी भी जमीन को लेकर ऐसी शिकायतें नहीं की जाती हैं और न ही ऐसी कार्रवाई होती है। सैकड़ों बीघा जमीन खरीदने वाला ट्रस्ट पौने चार बीघा जमीन की बेईमानी भला क्यों करेगा?

उपचुनाव में हराने की कोशिश की जा रही : उन्होंने कहा कि प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में हमें हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अब विधानसभा उपचुनाव में हमें हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम पर जुल्म कर हमें हरा नहीं सकेंगे।

अब छत्तीसगढ़ में उठी साहूकारी कर्ज माफ करने की मांग

नईदुनिया, रायपुर

मध्य प्रदेश सरकार के आदिवासियों के साहूकारी कर्ज माफी की घोषणा से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाने लगी है। यहां भी किसानों के साहूकारी कर्ज माफ करने की मांग उठने लगी है। किसान सभा के अनुसार राज्य का लगभग हर किसान करीब 50 हजार रुपये का कर्जदार है। किसान सभा ने मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से भी यहां के किसानों के साहूकारी कर्ज को माफ करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार राज्य के 19 लाख किसानों का 11 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन कृषि ऋण और 15 लाख किसानों का 207 करोड़ रुपये का सिंचाई कर माफ करने का दावा कर रही है। इस बीच विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा ने यहां नया मुद्दा खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में सभी आदिवासियों पर चढ़े साहूकारी कर्जे को माफ करने, उनकी गिरवी रखी जमीन और जेवर वापस करवाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि ने कहा है कि नाबार्ड के अनुसार, प्रदेश में भूमिहीन आदिवासियों सहित लगभग 37 लाख परिवार सरकारी ऋण योजना के दायरे से बाहर हैं, जो खुले बाजार या साहूकारों से कर्ज लेते हैं। ऐसे में केरल की तर्ज पर किसान ऋण मुक्ति आयोग बनाकर उन्हें इन कर्ज से छुटकारा दिलाया जा सकता है।

मौसम को देखते हुए तत्काल राहत देने की मांग : किसान नेताओं ने इस वर्ष देरी से हुई वर्षा और अल्पवर्षा से पैदा अकाल की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आधा राज्य और तीन-चौथाई किसानों की फसल सूखे से प्रभावित है। इसके मद्देनजर किसानों को राहत देने के हर संभव उपाय किए जाने की जरूरत है।

'आय से अधिक संपत्ति में मुलायम को क्लीन चिट देना बड़ी साजिश'

नई दिल्ली, प्रेट्र: आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उनके पुत्र अखिलेश यादव और अन्य को क्लीन चिट देना एक बड़ी साजिश है। यह आरोप कांग्रेस कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया। चतुर्वेदी ने कहा कि आपराधिक मामले को छिपाने और 2009 से 2013 तक उन्हें क्लीन चिट देना एक बड़ी साजिश है। ऐसे में शीर्ष अदालत को मामले को बंद करने की साजिश की जांच करनी चाहिए।

दरअसल, चतुर्वेदी ने शीर्ष अदालत में एक नई याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने मांग की है कि शीर्ष अदालत सीबीआइ को निर्देश दे कि वह इस मामले में की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट को शीर्ष अदालत में या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करे। 2005 में भी इनके खिलाफ याचिका दायर करने वाले चतुर्वेदी ने अब आरोप लगाया है कि सीबीआइ ने न केवल अदालत को गुमराह किया, बल्कि तथ्यों को दबा दिया गया।

विकास

देश के लिए नजीर बनी राज्य की पंचायतें, सामाजिक मानदंडों पर आगे निकलने की होड़, 3604 पंचायतों में आठवीं कक्षा तक हर बच्चा जा रहा स्कूल, 2312 गांवों में झगड़े हुए खत्म

बदलने लगी हरियाणा की पंचायतों की तस्वीर

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

465 पंचायतों में बेटों से अधिक जन्मी बेटियां

1108 ग्राम पंचायतों ने पर्यावरण संरक्षण में किया शानदार काम

पंचायत समिति व जिला परिषदों के चेयरमैन का सीधा चुनाव नहीं

पंचायत मंत्री धनखड़ ने कहा कि मेयर की तर्ज पर नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चेयरमैन के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए भले ही विधानसभा में विधेयक पारित हो गया है, लेकिन पंचायत समिति व जिला परिषदों के चेयरमैन का चुनाव सीधे कराने की अभी कोई योजना नहीं है।

84 करोड़ के पुरस्कार

धनखड़ के अनुसार स्टार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को 84 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। अगले साल रेटिंग के लिए डिजिटलाइजेशन और ड्रॉप आउट में आठवीं कक्षा की बजाय दसवीं कक्षा तक के आकलन को शामिल किया जाएगा।

सामाजिक सद्भाव का मामला हो या फिर लिंग अनुपात में सुधार या बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की समस्या, हरियाणा की ग्राम पंचायतें सामाजिक मामलों में देशभर में नजीर बनती जा रही हैं। गांवों में लोगों का जीवनस्तर सुधारने में 'सेवन स्टार इंद्रधनुष योजना' का अहम योगदान रहा है। 'सेवन स्टार इंद्रधनुष' योजना की सफलता से उत्साहित प्रदेश सरकार अब सेवन स्टार रेनबो कमेटी बनाएगी, जिसकी नियमित बैठकें होंगी। इसके अलावा सभी पंचायतों में ग्रामीणों की स्थायी कमेटियां बनाई जाएंगी, जो स्टार जीतने से मिली धनराशि से निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगी।

प्रदेश की कुल 6197 पंचायतों में से 3604 पंचायतों में ड्राप आउट की समस्या खत्म हो गई है। इन पंचायतों में आठवीं कक्षा तक का कोई बच्चा ऐसा नहीं, जो स्कूल नहीं जाता। 2312 गांव ऐसे हैं, जहां बीते एक साल में कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, जबकि 1108 ग्राम पंचायतों ने पर्यावरण संरक्षण में बेहतरीन काम किया है। 465 पंचायतें ऐसी हैं, जहां बेटों से अधिक बेटियों ने जन्म लिया अथवा लिंगानुपात पूरी तरह बराबर रहा। 240 ग्राम पंचायतें स्वच्छता की कसौटी पर खरी उतरी हैं। 203 पंचायतों ने गुड गवर्नेंस और 103 पंचायतों ने सामाजिक भागीदारी में मिसाल कायम की।

हरियाणा में अब तक 1853 गांवों में ग्राम सचिवालय बनाए जा चुके, जबकि 2200 पंचायतों में जल्द ही ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे। 3500 गांवों में गौरव पट्ट पर गांव की गौरव गाथा लिखी गई है। जल संरक्षण की मुहिम में 15 हजार तरुण युवा एक लाख से अधिक टोंटी लगवा चुके हैं।

राज्य के हर गांव में गोबरधन योजना, 126 गांवों में सीवरेज सिस्टम : पंचायत एवं विकास मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के अनुसार सभी गांवों में गोबरधन योजना शुरू होगी, जिससे गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो-सीएनजी में बदला जा सकेगा। महाग्राम योजना के तहत 10 हजार से अधिक आबादी वाले 126 गांवों में सीवरेज सिस्टम शुरू किया जाएगा। इनमें से 20 गांवों में सीवरेज बिछाने का काम शुरू हो चुका है।

कर्ज माफी का असर खजाने पर, मप्र सरकार ने फिर लिया एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज

नईदुनिया, भोपाल

कर्ज माफी से गड़बड़ाई मध्य प्रदेश की माली हालत को पटरी पर लाने के लिए सरकार बाजार से लगातार कर्ज ले रही है। इसी महीने सरकार ने फिर एक हजार करोड़ रुपये उधार लिए हैं। वर्ष 2019 में ऐसा कोई महीना नहीं बीता, जब सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से कर्ज न लिया हो। जनवरी से अगस्त तक सरकार 12 हजार 600 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल से अब तक) में छह हजार करोड़ रुपये लिए गए हैं। हालांकि, अभी सरकार 18 हजार करोड़ रुपये तक और कर्ज ले सकती है।

कमलनाथ सरकार ने 50 लाख किसानों की दो लाख रुपये तक कर्ज माफी करने का जो फैसला लिया है, उसकी वजह से खर्च का हिसाब गड़बड़ा गया है। इसे पटरी पर लाने और दूसरे कामों के लिए बजट का इंतजाम करने मुख्यमंत्री कमलनाथ और वित्त मंत्री तरण भनोत ने वित्तीय प्रबंधन के सूत्र अपने हाथ में ले लिए हैं। इसके तहत पहली बार आठ प्रमुख विभागों (लोक निर्माण, जल संसाधन, नगरीय विकास, पंचायत, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण सहित अन्य) को विशेष दर्जा देकर मासिक खर्च की सीमा तय कर दी है।

कमलनाथ फाइल फोटो

बाजार से एकमुश्त बड़ी राशि का कर्ज लेने की जगह विकास परियोजनाओं की जरूरत के हिसाब से राशि लेने की रणनीति बनाई गई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का साढ़े तीन फीसद तक कर्ज लिया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग से राज्य ने इस सीमा को चार प्रतिशत तक करने की मांग भी रखी है।

कब-कब कितना लिया कर्ज

तारीख	राशि
11 जनवरी	1000
एक फरवरी	1000
आठ फरवरी	1000
22 फरवरी	1000
28 फरवरी	1000
आठ मार्च	1000
25 मार्च	600
पांच अप्रैल	500
30 अप्रैल	500
तीन मई	1000
30 मई	1000
सात जून	1000
पांच जुलाई	1000
दो अगस्त	1000

नोट- राशि करोड़ रुपये में।

2769 लोगों पर एक अस्पताल और तीन डॉक्टर उपलब्ध हैं जम्मू-कश्मीर में। 2016-17 तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अस्पताल में प्रति 855 लोगों पर एक बेड है।

कश्मीर मामले में पाकिस्तान का निकला दम

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ लगभग सारे द्विपक्षीय संबंध तोड़ दिए और सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए हैं। पाक इसकी शिकायत चीन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, रूस, यूएई सहित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन लेकर गया। लेकिन सभी देशों से उसको मुंह की खानी पड़ी है।

संयुक्त राष्ट्र से मिली ठंडी प्रतिक्रिया

भारत के खिलाफ शिकायत करते हुए पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद करने के संबंध में एक पत्र लिखा था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने पत्र पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर दावा किया कि जम्मू-कश्मीर पर भारत ने 1949 के यूएनएससी प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। इसके जवाब में गुटेरेस ने पाकिस्तान को 1972 में हुए शिमला समझौते का हवाला दिया। 1971 भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद शिमला समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अपने सभी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाएंगे।

अमेरिका से कोई समर्थन नहीं

जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने के भारत के फैसले को पलटने के लिए पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए अमेरिका से भी अपील की। लेकिन अमेरिका ने मामले पर तटस्थ भूमिका निभाई है। जम्मू और कश्मीर के विकास और पाकिस्तान की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टागस ने कहा कि कश्मीर पर देश की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका ने संयम बरतने का आह्वान किया और भारत और पाकिस्तान दोनों से इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की। कश्मीर को लेकर अमेरिका की हमेशा से यह नीति रही है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है।

चीन ने आशाओं को किया धराशायी

जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के कदम पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने कहा कि इस कदम ने चीन की संप्रभुता को कमजोर किया है। लेकिन, उसकी यह प्रतिक्रिया लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने तक सीमित थी। शाह महमूद कुरैशी ने चीनी नेताओं के साथ वार्ता के लिए बीजिंग के लिए उड़ान भरी। कुरैशी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक बैठक के बाद चीन ने एक बयान जारी कर कहा, कश्मीर मुद्दा औपनिवेशिक इतिहास से बचा हुआ विवाद है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और द्विपक्षीय समझौते के प्रस्तावों के आधार पर ठीक से और शांति से हल किया जाना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री के बयान में द्विपक्षीय समझौते ने कुरैशी की आशाओं को धराशायी कर दिया कि उसके हर मौसम का मित्र चीन उसके साथ अधिक मजबूती से खड़ा होगा।

ओआइसी ने दिया झटका

पाकिस्तान को सबसे तगड़ा झटका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआइसी) से लगा। 57 इस्लामिक देशों वाले संगठन ओआइसी ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की। लेकिन जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने को लेकर भारत के साथ पाकिस्तान की कूटनीतिक लड़ाई में शामिल होने से इन्कार कर दिया। शक्तिशाली ओआइसी सदस्य देश सऊदी अरब और तुर्की ने कश्मीर मुद्दे के निपटारे के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता का आह्वान किया है। वहीं यूएई ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। ओआइसी के सदस्य देश आर्थिक भागीदारी और रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत को अधिक महत्व देते हैं। वहीं भारत ने सभी ओआइसी सदस्यों के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत किया है।

भारत को रूस का मिला खुला समर्थन

मुश्किल की घड़ी में भारत का साथ देने वाले रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का फैसला संवैधानिक दायरे में लिया गया है। रूस के इस बयान के बाद पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है।

तालिबान की फटकार

अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन तालिबान ने भी पाकिस्तान को फटकार लगाई है। तालिबान ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि कश्मीर पर ताजा फैसले के बाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को अफगानिस्तान के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

कंगाली की कगार पर पाक : पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट में है और उसने इस साल सऊदी अरब और चीन से दो अरब डॉलर का कर्ज लिया है। इसकी अर्थव्यवस्था 3.5 फीसद से कम की दर से बढ़ रही है। मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 6.5-7.0 फीसद की दर से बढ़ रही है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के आकार की लगभग नौ गुना है।

बौखलाए पाक ने लद्दाख के पास तैनात किए लड़ाकू विमान

बढ़ा रहा तनाव ▶ तीन सी-130 ट्रांसपोर्ट विमानों से रक्षा उपकरण सीमा के पास भेजे, जेएफ-17 भी कर सकता है तैनात

पाक की हरकतों पर भारतीय फौज और खुफिया एजेंसियों की नजर

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने से बौखलाया पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वह लद्दाख के पास अपने अग्रणी वायु सैन्य अड्डे स्कर्दू में लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ ही सैन्य उपकरण भी जमा कर रहा है। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां पाक की नापाक हरकतों पर चौकस निगाह रख रही हैं।

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने तीन सी-130 ट्रांसपोर्ट विमानों से शनिवार को रक्षा उपकरण स्कर्दू एयरबेस पर पहुंचाया। वह सीमा के पास जेएफ-17 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी वायु सेना अपनी सेना के साथ युद्धाभ्यास की योजना बना रही है और अग्रणी अड्डे पर विमानों की तैनाती उसका हिस्सा भी हो सकता है।

कश्मीर मसले पर विपक्ष के निशाने से परेशान पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सभी दलों से साथ आने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को कश्मीरियों के समर्थन में पाकिस्तान से एक आवाज उठनी चाहिए।

पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर गुलाम कश्मीर के लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए ईद का इस्तेमाल भी करना चाहा। विदेश मंत्री कुरैशी ने मुजफ्फराबाद में कश्मीर के लोगों के प्रति घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा कि सरकार ने लोगों से सादे तरीके से ईद मनाने को कहा था।

हर मोर्चे पर लड़ रहा पाक : शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। कुरैशी ने कहा कि कश्मीरियों की लड़ाई अब नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन बुधवार को प्रधानमंत्री इमरान खान मुजफ्फराबाद आएंगे।

इमरान ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बात की : कश्मीर मुद्दे पर दुनिया के नेताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश में इमरान खान ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से फोन पर बात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खान ने विडोडो को बताया कि कश्मीर में निर्दोष लोगों को मारे जाने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि इमरान खान इससे पहले ब्रिटेन, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और बहरीन के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर चुके हैं। किसी ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है।

बकरीद पर पाक रेंजरों ने नहीं दी मिठाई

जागरण संवाददाता, अटारी (अमृतसर)

▶ बीएसएफ अधिकारी जीरो लाइन पर करते रहे इंतजार

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव का असर बकरीद पर भी दिखा। अटारी सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को पाकिस्तानी रेंजरों ने इस बार मिठाई नहीं दी। जम्मू-कश्मीर और गुजरात में भी सीमा पर भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इस परंपरा का निर्वाह नहीं किया।

हर साल ईद, होली, दीपावली जैसे त्योहारों पर पर दोनों देशों के सुरक्षा बल एक-दूसरे को मिठाई भेंट करते हैं। बीएसएफ अधिकारी सोमवार सुबह जेसीपी अटारी जीरो लाइन पर पहुंचे गए, लेकिन पड़ोसी देश से कोई संदेश नहीं आया तो लौट आए।

जून 2018 में नहीं हुआ था मिठाई का आदान-प्रदान : इससे पहले जून 2018 में भी मिठाई का आदान-प्रदान नहीं हुआ था। तब रमजान माह के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सुरक्षा बलों पर 42 बार हमले किए थे। तब भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को ईद के मौके पर मिठाई भेंट नहीं की थी।

डीटीसी ने सदा-ए-सरहद बस को किया निलंबित

नई दिल्ली : दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने सोमवार को दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली सदा-ए-सरहद बस सेवा को स्थगित कर दिया। बस को सोमवार सुबह 6 बजे लाहौर के लिए प्रस्थान करना था।

समझौता के बाद दिल्ली-अटारी स्पेशल ट्रेन भी रद : पाकिस्तान सरकार द्वारा समझौता एक्सप्रेस रद किए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने दिल्ली-अटारी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को रद कर दिया है। इस ट्रेन को सोमवार सुबह 6.30 बजे अंतरराष्ट्रीय अटारी रेलवे स्टेशन पहुंचना था। इसमें सवार यात्रियों को समझौता एक्सप्रेस से वाघा (लाहौर) तक जाना था, लेकिन 8 अगस्त को पाकिस्तान सरकार ने इस ट्रेन को भेजने से इन्कार कर दिया था। दिल्ली-अटारी ट्रेन के यात्रियों के पास रेलवे के जरिए ही पाकिस्तान जाने का वीजा था। वे सड़क मार्ग से पाकिस्तान नहीं जा सकते थे। भारतीय रेलवे बोर्ड ने दिल्ली-अटारी स्पेशल ट्रेन (14001) और अटारी-पुरानी दिल्ली ट्रेन (14002) को रद कर दिया। अटारी-वाघा के बीच चलने वाली ट्रेन (14608) और वाघा-अटारी के बीच चलने वाली ट्रेन (14607) भी रद रही।

जम्मू-कश्मीर में यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, जम्मू : स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे पुलिस और एंटी हाईजेकिंग पुलिस (हवाई अड्डे पर तैनात पुलिस) ने यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। रेल यात्रियों को ट्रेन चलने से एक घंटे पूर्व और हवाई यात्रियों को दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने को कहा है। रेलवे स्टेशन पर तैनात सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनिता पवार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के चलते स्टेशन परिसर के भीतर और रेलवे ट्रैक पर गश्त को बढ़ा दी है।

सुरक्षा बंदोबस्त को पुख्ता करने के लिए रेलवे पुलिस के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को तैनात किया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक एक्शन टीम (क्यूआरटी) का गठन किया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाले यात्रियों के सामान की गहनता से जांच की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के चलते यात्रियों के सामान की गहनता से जांच की जा रही है, जिसमें अतिरिक्त समय लग सकता है। यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

न्यूज गैलरी

कश्मीर में साथ मिलकर काम कर रहे सभी बल : सीआरपीएफ

नई दिल्ली : सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) ने उन खबरों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों में दरार आ गई है। सीआरपीएफ ने कहा है कि सभी सुरक्षा बल साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी वर्दी का रंग भले ही अलग है, लेकिन सभी के दिलों में तिरंगा है। दरअसल, अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर हर मोर्चे पर पस्त हो चुका पाकिस्तान अब फर्जी खबरों का सहारा ले रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ट्वीट कर दावा किया, 'एक कश्मीरी पुलिसकर्मी ने सीआरपीएफ के पांच जवानों को गोली मार दी, क्योंकि उन्होंने एक गर्भवती महिला को कर्फ्यू पास न होने की वजह से जाने से रोक दिया था।' सीआरपीएफ ने इन खबरों का खंडन करते हुए ट्वीट किया, 'इस ट्वीट की दुर्भावनापूर्ण सामग्री पूरी तरह निराधार और सच्चाई से परे है। हमेशा की तरह भारत के सभी सुरक्षाबल समन्वय और सद्भाव से काम कर रहे हैं। भले ही हमारी वर्दी के रंग अलग-अलग हों, लेकिन देशभक्ति और तिरंगा हमारे दिलों में बसता है।' (एएनआइ)

कश्मीरी लड़कियों की सुरक्षा करेगी एसजीपीसी

अमृतसर : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने कहा है कि कश्मीर की जो भी लड़कियां एसजीपीसी प्रबंधन के अधीन गुरुद्वारों और शिक्षण संस्थानों में आएंगी उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। उन्हें घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का प्रबंध होगा। एसजीपीसी के मुख्य सचिव डॉ. रूप सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। डॉ. सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अलग-अलग स्थानों पर रह रहीं कश्मीरी लड़कियों में डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि बेटियां और बहनें सभी की साझी होती हैं। गुरुद्वारों और अन्य संस्थानों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि जो भी लड़कियां आएं उनकी रिहायश, लंगर और सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के संबंध में गलत भाषा इस्तेमाल करने वाले मानवता के नाम पर कलंक हैं। (जासं)

एएमयू में राज्यपाल का भोज रद कश्मीरी छात्रों ने निकाला मार्च

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में बकरीद पर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से कश्मीरी छात्रों के लिए प्रस्तावित भोज नहीं हो सका। विरोध के चलते भोज रद करना पड़ा। सोमवार को बकरीद की नमाज के बाद कश्मीरी छात्रों ने कैंपस में विरोध मार्च निकाला। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की ओर से दोपहर के भोज के लिए एक लाख रुपये दिए गए थे। यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस नंबर एक में भोज की व्यवस्था की गई थी। जहां तैयारियां भी शुरू हो गईं। राज्यपाल मलिक ने इसके लिए संजय पंडिता को लाइजनिंग ऑफिसर बनाकर भेजा था। रविवार शाम छात्रों ने यह कहते हुए भोज का बहिष्कार कर दिया था कि घर वालों का अता-पता नहीं है। उनसे बात हो नहीं पा रही। संपर्क का कोई साधन नहीं है। ऐसे में हम कैसे खुशियां मना सकते हैं? इसके चलते भोज को रद कर दिया गया। बकरीद की नमाज के बाद कश्मीरी छात्रों ने विरोध मार्च निकाला और मांग की कि केंद्र सरकार जल्द अनुच्छेद 370 बहाल करे। (जासं)

राहुल के लिए एयरक्राफ्ट भेजूंगा : राज्यपाल मलिक

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्यपाल सत्यपाल मलिक सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वह राहुल के लिए एयरक्राफ्ट भेजेंगे ताकि वह कश्मीर की वास्तविक स्थिति का जायजा ले सकें। उन्होंने शनिवार बयान दिया था कि कश्मीर से हिंसा की रिपोर्ट आ रही हैं। प्रधानमंत्री को पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए।

मलिक ने कहा कि उन जैसे नेता को इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। राज्यपाल पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। मलिक ने यह भी कहा कि राज्य से 370 हटाने के पीछे कोई भी धार्मिक कारण नहीं था। 370 और 35-ए सभी के लिए हटाया गया है। कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी पत्रकारों ने भी गलत रिपोर्टिंग की। उन्हें भी चेतावनी दी गई है। सभी अस्पताल सभी के लिए खुले हैं। अगर किसी भी अस्पताल में बुलेट लगने से कोई घायल भर्ती है तो इसे साबित करें।

शांति का संदेश...

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद राज्य में पहली बकरीद सोमवार को उल्लासपूर्वक मनाई गई। इस मौके पर पाबंदियों में छूट दी गई और लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए। श्रीनगर में लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की और अमन चैन का संदेश दिया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद देता पुलिसकर्मी। एएनआइ

उपजेल में उमर और महबूबा में झगड़ा, मारपीट की आई नौबत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

महबूबा मुफ्ती फाइल फोटो

उमर अब्दुल्ला फाइल फोटो

अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में खानदानी सियासत समाप्त होने से हताश नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती उपजेल हरि निवास में एक-दूसरे से उलझ पड़े। संबंधित अधिकारियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को बिगड़ने से बचाया। इसके तुरंत बाद उमर को वन विभाग के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया।

उमर और महबूबा को चार अगस्त की रात को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया था। दोनों को हरि निवास में रखा गया, जिसे उपजेल का दर्जा दिया गया। महबूबा को हरि निवास के प्रथम तल और उमर को भूतल पर रखा गया था। सूत्रों ने बताया कि उमर और महबूबा के बीच बातचीत पर पहले किसी तरह की रोक-टोक नहीं थी। बीती शाम दोनों में राज्य की मौजूदा स्थिति पर लेकर बहस हो गई। उमर ने महबूबा को राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर वह भाजपा के साथ हाथ न मिलातीं तो यह स्थिति न होती। उन्होंने महबूबा पर चिल्लाते हुए कहा कि उनके पिता ने मुफ्ती मुहम्मद सईद ने 2015 में मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा से समझौता किया। महबूबा ने उमर पर भाजपा से मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह कश्मीर में भाजपा के एजेंडे के साथ है। सबसे पहले नेकां ने भाजपा से नाता जोड़ा। उन्होंने उमर से कहा कि डॉ. फारूक ने ही वाजपेयी से सबसे पहले हाथ मिलाया और उमर को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनवाया। उन्होंने उमर के दादा दिवंगत शेख मुहम्मद अब्दुल्ला का भी नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने कई बार कश्मीरियों से धोखा किया।

उमर और महबूबा के बीच मामले को तूल पकड़ते देख अधिकारियों ने दोनों को अलग किया। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई थी। हालांकि, किसी ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। इस घटना के बाद महबूबा को हरि निवास की पहली मंजिल से नीचे उतरने से मना कर दिया है। वहीं, उमर को हरि निवास से हटाकर वन विभाग के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है।

महबूबा को चाहिए ब्राउन ब्रेड : हरि निवास में तैनात हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकाल विभाग से जुड़े अधिकारी ने बताया कि पीडीपी अध्यक्षा महबूबा ने अपने लिए ब्राउन ब्रेड की मांग की थी, लेकिन मैन्यू में इसका कोई जिक्र नहीं था। इसलिए उन्हें ब्राउन ब्रेड नहीं दी है। अलबत्ता, उन्हें उनकी पसंद फल उपलब्ध कराए गए हैं।

आधा दर्जन से ज्यादा ट्विटर अकाउंट पर लगेगी रोक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम

▶ गृह मंत्रालय की सिफारिश पर आइटी मंत्रालय ने ट्विटर इंडिया को दिया निर्देश

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद वहां की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार बेहद सतर्क हो गई है। सरकार ने कश्मीर से संबंधित अलगाववादियों की तरफ से सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार और हालात बिगाड़ने की कोशिशों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत करते हुए ट्विटर इंडिया से आधा दर्जन से अधिक अकाउंट पर रोक लगाने को कहा गया है। इनमें पाक परस्त हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी और वॉयस ऑफ कश्मीर के ट्विटर अकाउंट भी शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर में संभावित हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए थे। इन उपायों में कश्मीर में इंटरनेट की उपलब्धता को सीमित करने जैसे उपाय भी शामिल थे। सूत्र बताते हैं, इसके बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ ट्विटर अकाउंट से तरह-तरह की बयानबाजी की जा रही है। ये न सिर्फ कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को हवा दे रहे हैं बल्कि झूठी सूचनाओं का प्रसार करके समूचे राज्य में शांति-व्यवस्था को भंग करने में जुटे हैं। जांच एजेंसियां कई दिनों से ट्विटर पर ऐसे अकाउंट पर नजर रखे हुए थीं। अभी सिर्फ सात अकाउंट को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। एजेंसियों की सूचना के आधार पर गृह मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इन अकाउंट की जानकारी देकर इन पर कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर इंडिया से इन सभी अकाउंट पर रोक लगाने को कहा है। मंत्रालय की तरफ से ट्विटर इंडिया को इस संबंध में नोटिस भेज दिया गया है। इन अकाउंट्स में मदिहा शकील, अरशद शरीफ, मैरी स्कली और रियाज खान के ट्विटर अकाउंट भी शामिल हैं।

अलगाववादियों के एक साल तक बाहर आने की उम्मीद नहीं

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर का विशेषाधिकार समाप्त कर दो केंद्र शासित राज्य बनाने के मद्देनजर हिरासत में लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, अलगाववादियों और अन्य लोगों की जल्द रिहाई की उम्मीद नहीं है। संबंधित अधिकारियों की मानें तो इन्हें एक साल तक बंद रखा जा सकता है। गौरतलब है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और किसी भी तरह के राष्ट्रविरोधी प्रदर्शनों की संभावना को टालने के लिए राज्य प्रशासन ने बीते आठ दिनों के दौरान करीब 700 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से करीब 150 लोगों को देश के विभिन्न राज्यों की जेलों में स्थानांतरित किया गया है। इनमें अलगाववादियों के अलावा नेकां के महासचिव अली मोहम्मद सागर भी हैं।

बयानबाजी जारी

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने सांप्रदायिक रंग दिया तो मणिशंकर अय्यर ने की फलस्तीन से तुलना

370 पर थम नहीं रहे कांग्रेसियों के विवादित बोल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस भ्रम से निकलती दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी नेताओं का एक बड़ा वर्ग जहां इस फैसले का खुला समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ा न सिर्फ सरकार का विरोध कर रहा है बल्कि अपने विवादित बयानों से पार्टी की किरकिरी भी करा रहा है। कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के बाद मणिशंकर अय्यर ने इसकी तुलना भारत में फलस्तीन से कर दी।

कांग्रेस कार्यसमिति में जम्मू-कश्मीर के विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित कराने के सूत्रधार रहे चिदंबरम ने रविवार को कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो सरकार अनुच्छेद 370 खत्म नहीं करती। सरकार को कोसने की कोशिश में अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित रहे अय्यर अब चिदंबरम से भी एक कदम आगे निकल गए।

अय्यर ने अंग्रेजी अखबार में अपने लेख में अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले को अनुचित ठहराते हुए इस देश में फलस्तीन बनाने जैसा कदम बताया है। अय्यर ने लिखा है, 'नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हमारी उत्तरी सीमा पर हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर एक फलस्तीन बना दिया है।' 400 से अधिक स्थानीय राजनीतिक नेताओं-कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर और हजारों हजार अमरनाथ यात्रियों को वापस भेज कर यह कदम उठाया गया।

पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए अय्यर ने लिखा है कि इन दोनों ने इजरायली नेता बेंजामिन नेतन्याहू सरीखे लोगों से यह पाठ पढ़ा है। उनके अनुसार इन दोनों ने सीखा है कि किस तरह कश्मीर के लोगों की आजादी, गरिमा और आत्मसम्मान को कुचलना है। कांग्रेस नेता अय्यर ने यह भी कहा है कि सात दशक से इजरायल ने फलस्तीन के लोगों इसी अवधारणा के साथ निर्ममता से कुचलने का प्रयास किया है, मगर फलस्तीनी लगातार इसका जवाब देते रहे हैं।

यूएन प्रस्ताव लागू करने की मांग मूर्खतापूर्ण : थरूर

नई दिल्ली, एएनआइ : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रस्ताव लागू करने की मांग का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि 72 साल और चार युद्धों और गुलाम कश्मीर में जनसंख्या एवं क्षेत्रीय सीमा में हुए बदलाव के बाद यूएन प्रस्ताव को जिंदा करना मूर्खतापूर्ण है। थरूर ने ट्वीट किया है, 'चाहे पाकिस्तान या ब्रिटेन के जो लोग कश्मीर पर यूएन प्रस्ताव लागू करने की मांग कर रहे हैं वह 1948 के रेस 457 की वास्तविक जरूरत को देख लें। इसे पूरी तरह नहीं पैरा दर पैरा अपनाने की जरूरत थी। घोषणा की गई थी कि समयबद्ध जवाबदेही क्रम से लागू होगी।' एक अन्य ट्वीट में थरूर ने कहा है, 'पहले पाकिस्तान को सभी कबायली और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेना था। उसने कहा था कि उसकी सेना शामिल नहीं थी। दूसरा भारत गुलाम कश्मीर में आगे बढ़ेगा और जम्मू एवं कश्मीर में अपनी सेना कम करेगा।'

शेखर कपूर ने बीबीसी से पूछा, ब्रिटिश अधिकृत आयरलैंड क्यों नहीं कहते

नई दिल्ली, आइएएनएस : फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने बीबीसी द्वारा भारत अधिकृत कश्मीर कहे जाने की निंदा की है। फिल्म निर्माता ने बीबीसी से यह बताने की मांग की है कि आखिर उत्तरी आयरलैंड को 'ब्रिटिश अधिकृत आयरलैंड' क्यों नहीं कहा जाता है। शेखर कपूर ने ट्वीट किया, 'बीबीसी वर्ल्ड हर बार आप कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर कहते हैं। मुझे हैरत है कि आप उत्तरी आयरलैंड को 'ब्रिटिश अधिकृत आयरलैंड' कहने से क्यों बचते हैं।'

बीबीसी ने दी है सफाई : बीबीसी की एक न्यूज प्रेस टीम ने ट्वीट कर कहा है, 'बीबीसी अपनी पत्रकारिता के साथ खड़ा है और हम मजबूती से ऐसे किसी दावे का खंडन करते हैं कि हमने कश्मीर में घटनाओं की गलत प्रस्तुति दी है। हम निष्पक्षता पूर्वक और सटीकता से स्थिति की रिपोर्ट करते हैं। अन्य प्रसारकों की भांति हम वर्तमान में कश्मीर में कठोर प्रतिबंधों के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग जारी रखेंगे।'

फारूक, उमर और महबूबा मुफ्ती ने अकेले मनाई ईद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर का सबसे पॉश और वीआइपी इलाका गुपकार। यहां की सड़क पहली बार ईद के मुबारक मौके पर सुनसान रही। सड़क पर ईद की बधाई देने वालों का तांता नजर नहीं आया। डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, शेख मुस्तफा कमाल और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इसी मार्ग पर अलग-अलग कोठियों में रहते हैं। ईद के मुबारक मौके पर विभिन्न सियासी दलों के नेता, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, नामी बिजनेसमैन और सभी नेकां और पीडीपी के शीर्ष नेतृत्व को उपहारों संग ईद मुबारक देने जाते थे।

गुपकार जिस तरह सुनसान था, उसी तरह आज डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी अकेले ही बिना दोस्तों और परिजनों के चुपचाप ईद मनाई। डॉ. फारूक अब्दुल्ला तो अपने पुत्र उमर अब्दुल्ला को भी ईद की मुबारक नहीं कह पाए। महबूबा मुफ्ती अपनी दोनों बेटियों और परिवार के अन्य सदस्यों से पूरी तरह कटी रहीं। हालांकि, उन्हें जहां रखा गया है, वह उनके निवास से करीब 150 मीटर ही दूर है, लेकिन न वह फोन कर सकते हैं न कोई उनसे मिलने आ सकता है। अलबत्ता फारूक, उमर और महबूबा ने अकेले-अकेले ही ईद मनाई। इस बीच, गत रविवार रात को हिरासत में लेकर सेंतूर होटल में रखे गए नेकां, पीडीपी, पीपुल्स कांफ्रेंस और माकपा सहित विभिन्न सियासी नेताओं ने होटल में ही मनाई। उन्हें नमाज-ए-ईद के लिए एक मौलवी प्रशासन की तरफ से उपलब्ध करवाया गया था।

4 परियोजनाओं में बिजली उत्पादन ठप पड़ा है हिमाचल प्रदेश में नदियों में सिल्ट आने के कारण। इससे प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। 1500 मेगावाट नाथपा झाखड़ी परियोजना, 330 मेगावाट की बासपा और दो अन्य प्रोजेक्टों में बिजली उत्पादन शून्य रहा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 13 अगस्त 2019

रेलवे महात्मा गांधी की जयंती सामुदायिक दिवस के तौर पर मनाएगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेलवे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को सामुदायिक दिवस के रूप में मनाएगा। इस दौरान कर्मचारी और अधिकारी जहां श्रमदान करेंगे, वहीं 'मोहनदास से महात्मा' शीर्षक से संबंधित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।

बता दें कि 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को महात्मा गांधी की विरासत से अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया था। समिति ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता शामिल थे।

सभी जोन को भेजे गए पत्र के मुताबिक, 'रेलवे दो अक्टूबर 2019 के दिन को सामुदायिक दिवस के तौर पर मनाएगा। इस दौरान रेलकर्मी श्रमदान भी करेंगे। साथ ही 'मोहनदास से महात्मा' के शीर्षक से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। यह एक सप्ताह तक चलेगी।' मेट्रो शहरों के ट्रैक के किनारे खाली पड़ी जमीन पर 150 छोटी नर्सरी भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सभी संभागीय मुख्यालयों की उत्पादन इकाइयों और कार्यशालाओं की दीवारों पर महात्मा गांधी से संबंधित चित्र बनाने और उनके प्रेरक वाक्य लिखने का भी निर्देश दिया गया है।

तैयारी ▸ चुनौतीपूर्ण रूट अपनाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन होगी

उत्तरी ध्रुव होकर सैन फ्रांसिस्को की उड़ान भरेगी एयर इंडिया

डेढ़ घंटे का समय बचेगा, चार हजार किमी की दूरी होगी कम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एयर इंडिया का विमान फाइल फोटो

पहली बार कोई भारतीय एयरलाइन उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरेगी। इसी 15 अगस्त को एयर इंडिया की दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर जाएगी। यह रास्ता सामान्य रास्ते के मुकाबले छोटा किंतु चुनौतीपूर्ण है। भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

इसके लिए एयर इंडिया का विमान दिल्ली से किर्गिस्तान, कजाखिस्तान, रूस होकर अटलांटिक महासागर को पार करके कनाडा होते हुए अमेरिका में प्रवेश करेगा। इस रास्ते की दूरी आठ हजार किलोमीटर है जिसे पूरा करने में एयर इंडिया को सिर्फ 13 घंटे लगेंगे। जबकि 12 हजार किलोमीटर लंबे सामान्य रास्ते में 14.5 घंटे का समय लगता है। सामान्य रास्ता दिल्ली से बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और जापान होकर जाता है और विमान को प्रशांत महासागर पार करने के बाद अमेरिका में प्रवेश मिलता है।

कैप्टन रजनीश शर्मा और दिग्विजय की जोड़ी होगी पायलट : एयर इंडिया के एक अधिकारी के अनुसार, इस ऐतिहासिक उड़ान को कैप्टन रजनीश शर्मा और कैप्टन दिग्विजय सिंह की जोड़ी उड़ाएगी। तड़के 3:30 बजे रवाना होने वाली फ्लाइट में चालक दल के 12 सदस्य व300 यात्री सवार होंगे। एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी ने बताया कि इन यात्रियों को स्मारक प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

अमेरिका के तीनों रूटों का इस्तेमाल करने वाली होगी पहली एयरलाइन: इस उड़ान के साथ एयर इंडिया अमेरिका के लिए तीनों रूटों का इस्तेमाल करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बन जाएगी। तीसरा रूट वाया यूरोप है जिसका इस्तेमाल एयर इंडिया अमेरिका से लौटने वाली उड़ानों के लिए करती है। अभी मध्य पूर्व में सिर्फ एतिहाद एयरलाइन ही अमेरिका जाने के लिए उत्तरी ध्रुव के रास्ते का इस्तेमाल करती है।

बेहद चुनौतीपूर्ण है मार्ग: उत्तरी ध्रुव होकर जाने वाली उड़ान को काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि एक तो इस इलाके के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा, आपात स्थिति में डायवर्जन के लिए एयरपोर्ट के सीमित विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा सौर विकिरण और शून्य से नीचे 50 डिग्री तापमान होने के कारण विमान ईंधन के जमने का खतरा रहता है।

ईंधन की भी होगी बचत: उत्तरी ध्रुव के छोटे रास्ते से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान में दूरी और समय की बचत के साथ ईंधन की भी बचत होगी। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। एयर इंडिया सूत्रों के अनुसार, उत्तरी ध्रुव के रास्ते उड़ान भरने पर विमान के आकार और क्षमता के अनुसार प्रति उड़ान 2000-7000 किलोग्राम तक ईंधन की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन में 6000-21000 किलोग्राम तक की कमी आने की संभावना है।

डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को दी थी चुनौती: उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने की चुनौती उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश की सभी एयरलाइनों के समक्ष रखी थी। इस संबंध में उसने छह अगस्त को सर्कुलर जारी किया था। लेकिन एयर इंडिया के अलावा किसी निजी एयरलाइन ने हिम्मत नहीं दिखाई।

फिल्मों का अवैध प्रसारण करने वाली वेबसाइटों को करें ब्लाक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आइएसपी) को निर्देश दिया है कि वे तमिल रॉकर्स, ईजेडटीवी, कैट-मूवीज, और लाइम-टॉरेंट्स जैसी वेबसाइटों को ब्लाक करें। इन वेबसाइट्स पर नेटफ्लिक्स, वॉर्नर ब्रॉस जैसे प्रोडक्शन हाउसों की फिल्में और सीरियलों को अवैध तरीके से प्रसारित करने का आरोप है।

वार्नर ब्रॉस की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने अंतरिम आदेश में कहा कि इन सभी वेबसाइट से सभी यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) और आइपी एड्रेस को ब्लाक कर दिया जाए। पीठ ने दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे प्रोडक्शन हाउसों के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों के डोमेन पंजीकरण को निलंबित करें। साथ ही ऐसी वेबसाइटों को ब्लाक करने के लिए इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी करें।

वार्नर ब्रॉस की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि इन वेबसाइटों पर यूटीवी, पैरामाउंट, यूनिवर्सल और नेटफ्लिक्स की फिल्में, व सीरियलों को बगैर अनुमति के प्रसारित किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि इन वेबसाइट को ब्लाक करने का आदेश नहीं दिया गया तो इससे कंपनी को अपूरणीय क्षति या चोट होगी।

कैलास मानसरोवर के यात्रियों के लिए चीन खोलेगा ऑक्सीजन बूथ

नीलू रंजन, कैलास मानसरोवर

यात्रा मार्ग पर ऑक्सीजन बूथ लगाने की तैयारी शुरू। एक बूथ में एक साथ तीन से पांच यात्री ऑक्सीजन ले सकेंगे। जागरण

कैलास मानसरोवर की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह एक खुशखबरी है। अब उन्हें अत्यधिक उंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। चीन सरकार अब यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए यात्रा मार्ग पर ऑक्सीजन बूथ लगाने जा रही है। इसके साथ ही यात्रियों के विश्राम के लिए अत्याधुनिक शिविरों का निर्माण भी किया जा रहा है। ऐसे दो शिविर बनकर तैयार हैं और उन्हें यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। वही अन्य दो शिविर अगली यात्रा तक बन कर तैयार हो जाएंगे।

दरअसल, भारत से आनेवाले अधिकांश यात्री मैदानी इलाके से होते हैं और कैलास पर्वत की परिक्रमा का पथ समुद्र तल से 15 हजार फीट से भी अधिक की उंचाई पर होने के कारण उन्हें थकान, सिरदर्द जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी वाले इस उंचाई पर कैलास पर्वत की लगभग 50 किलोमीटर की परिक्रमा उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। इस परिक्रमा में लगभग तीन दिन लग जाते हैं। जाहिर है ऑक्सीजन की कमी यात्रियों की मुश्किलों को और बढ़ा देती है। यात्रा के दौरान ऑक्सीजन बूथ की जरूरत को इस बात से समझा जा सकता है कि भारत से हर साल विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित यात्रा में करीब डेढ़ हजार यात्री भगवान शंकर के धाम आते हैं जबकि नेपाल के निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से ल्हासा या हिल्सा सिमीकोट के रास्ते भी हजारों यात्री आते हैं। अधिकांश यात्री मैदानी इलाकों के होते हैं और समुद्रतल से करीब 15 हजार फुट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण उनमें से कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं।

कैलास मानसरोवर की यात्रा में यात्री सुविधाओं के विस्तार का जायजा लेने आये भारतीय पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में अली प्रीफैक्चर के विदेश विभाग के महानिदेशक आवांग ने कहा कि यात्रा के मार्ग में कुछ स्थानों पर ऑक्सीजन बूथ लगाने का फैसला हुआ है। लगभग एक दर्जन ऑक्सीजन बूथ खरीदे भी जा चुके हैं , लेकिन अभी तक उन्हें लगाया नहीं गया है। फिलहाल यात्रा के रूट और यात्रियों की जरूरतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह तय किया जाएगा कि 50 किलोमीटर के परिक्रमापथ पर कहाँ-कहाँ और कितने ऑक्सीजन बूथ की जरूरत है। माना जा रहा है कि अगले साल तीर्थयात्रियों को ऑक्सीजन बूथ की सुविधा मिलने लगेगी। एक बूथ में एक साथ तीन से पाँच यात्री आक्सीजन ले सकेंगे। फिलहाल कुछ होटलों में यात्रियों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत परिक्रमा मार्ग पर है, जहां पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है।

ऑक्सीजन बूथ के अलावा चीन सरकार और तिब्बत प्रशासन अन्य अत्याधुनिक सुविधाएँ मुहैया कराने कराने की तैयारी में जुटा है। इसके तहत परिक्रमा पथ पर दारचेन, डेरापुक, जुटुरपुक और मानसरोवर के निकट चार अतिथिगृह बनाये जा रहे है हैं, जिनमें आधुनिक शौचालय एवं रसोईघर भी है।

इनमें डेरापुक तथा जुटुरपुक में यात्री विश्राम गृहों को खोल दिया गया है, जबकि मानसरोवर का यात्री विश्राम गृह बनकर तैयार है, उसे अगले साल से खोला जाएगा। इन यात्री विश्रामगृहों में एक समय में 160 यात्री ठहर सकते हैं। हर कमरे में रजाई व बिस्तर सहित तीन बेड हैं। उनके लिए अलग से शौचालय भी बनाए गए है। जाहिर है इसके लिए उन्हें बाहर खुले में या गंदे शौचालय में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही विश्रामगृह के भीतर ही एक बड़ा किचन भी बनाया गया है, जिसमें 150 लोगों के लिए खाना बनाने का पर्याप्त इंतज़ाम है।

पिछले कुछ सालों से यात्री सुविधाओं के विस्तार की चीन सरकार की कोशिशों का असर भी दिख रहा है। यात्रा पूरी करने के बाद लिपुलेख दर्रे से लौट रहे 13वें दल का तकरीबन हर यात्री चीन सरकार के इंतजामों से संतुष्ट नजर आया।

पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के दौरान भी डॉक्टरों को मिलेगा एनपीए

कमल जोशी, चंडीगढ़

▸ हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के 2015 के आदेश को किया खारिज

पंजाब के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने वाले पीसीएमएस (पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज) के डॉक्टरों को भी नॉन-प्रैक्टिस भत्ता (एनपीए) मिलेगा। पंजाब सरकार ने 26 मार्च, 2015 से सरकारी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने वालों को नॉन-प्रैक्टिस भत्ता बंद कर दिया था। इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। एनपीए का बकाया छह सप्ताह में अदा करना होगा।

पंजाब सरकार के आदेशों से पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स कर रहे डॉक्टरों को एनपीए मिलना बंद हो गया था। इन कॉलेजों में 2015, 2016 और 2017 से आरंभ हुए चार वर्षीय कोर्स करने वाले डॉक्टर प्रभावित हो रहे थे।

सरकार के खिलाफ डॉ. गुरप्रीत सिंह माहल और अन्यों द्वारा दायर याचिकाओं में कहा गया था कि उन्हें दिया जाने वाला एनपीए पीसीएस नियमों के तहत उनके विशेष वेतन का हिस्सा है और सरकार इसे बंद नहीं कर सकती।याचिकाओं के विरोध में पंजाब सरकार ने कहा कि अस्पतालों में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को एनपीए दिया जाता है कि वे अपनी ड्यूटी के बाद निजी प्रैक्टिस न करें। सरकार के वकील ने कहा कि जून 2014 को सोच-समझ कर यह फैसला लिया गया कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स का लाभ लेने वालों को एनपीए का लाभ न दिया जाए।

एनपीए विशेष वेतन का हिस्सा

प्रदेश सरकार के फैसले को खारिज करते हुए जस्टिस जितेन्द्र चौहान ने कहा कि एनपीए याचिकाकर्ताओं को मिलने वाले विशेष वेतन का हिस्सा है। सरकार इसे वापस लेने का कोई वैध कारण साबित नहीं कर पाई।

हेरोइन तस्करी में पंजाब पुलिस के दो एएसआइ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर: भारत-पाक सीमा के पास घरिंडा थाने में तैनात पंजाब पुलिस के दो एएसआइ को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने दस ग्राम हेरोइन बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स और अमृतसर देहाती पुलिस ने ज्वाइंट आपरेशन के तहत सोमवार रात दोनों को गिरफ्तार किया।

एसएसपी देहाती विक्रमजीत दुग्गल ने बताया कि एएसआइ जोरावर सिंह और एएसआइ अवतार सिंह से हेरोइन बरामद की गई है। पता चला है कि उक्त दोनों मुलाजिम सीमा के साथ सटे किसी गांव में रहने वाले तस्कर से हेरोइन की खेप लेकर सप्लाई करते थे। यह बात भी सामने आई है कि दोनों खुद भी नशे का सेवन करते हैं और दोनों का मेडिकल करवाया जा रहा है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि दोनों के पुराने और कुख्यात तस्करों से भी संबंध हैं। इसके साथ ही उन तस्करों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है जिनसे वह नशा लेते थे। वहीं स्पेशल टास्क फोर्स और अमृतसर देहाती पुलिस द्वारा सीमावर्ती गांवों में छापामारी शुरू कर दी है। संभावना जताई गई है कि कुछ और लोगों को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी।

उत्तर प्रदेश में बकरीद पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश

जेएनएन, लखनऊ

सावन का अंतिम सोमवार और बकरीद एक ही दिन होना पुलिस-प्रशासन के लिए चुनौती भरा रहा। अराजक तत्वों ने खासकर पश्चिमी उप्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि अधिकारियों की सतर्कता से स्थिति बिगड़ने से बच गई। एहतियातन ऐसे स्थानों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। बिजनौर, बुलंदशहर, फीरोजाबाद और आगरा में माहौल बिगड़ने से बचा। आगरा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर हनुमान चालीसा पढ़ा। पूर्वी और मध्य पूर्वी उप्र में किसी भी स्थान से बकरीद पर तनाव की कोई खबर नहीं है। बिजनौर में शेखूपुरा लाला गांव में संप्रदाय विशेष के व्यक्ति ने कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेष मंदिर के पास फेंक दिए। इससे तनाव हो गया। बुलंदशहर के कुरैना गांव में बकरीद पर सोमवार सुबह सड़क किनारे गोवंश के अवशेष मिलने से हिंदू संगठन और क्षेत्र के लोगों ने हंगामा किया। बजरंग दल के जिला गोरक्षा प्रमुख यतेंद्र छोटे गहना की तहरीर पर अज्ञात गोकशों के खिलाफ गोवध अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगरा के खंदौली में ईदगाह में नमाज के दौरान पुलिस द्वारा हाईवे पर रोके गए ट्रैफिक के विरोध में बजरंग दल के लोगों ने आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर हनुमान चालीसा पढ़ा।

बदायूं में कावंड़ियों के जत्थे पर हमला, तनाव

जासं, बदायूं : जलाभिषेक करके लौट रहे कांवड़ियों के एक जत्थे पर सोमवार सुबह संप्रदाय विशेष के लोगों ने हमला कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पथराव कर कांवड़ियों को दौड़ाकर पीटा, जिससे छह कांवड़िये घायल हो गए। तनाव फैल गया। विरोध में कांवड़ियों ने बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। इससे चार घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। डीएम और एसएसपी ने समय रहते मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। सांप्रदायिक बवाल होने से टल गया। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमलावरों को चिह्नित किया जा रहा है। शांति व्यवस्था कायम है।

दंतेवाड़ा जिले के चार ग्रामीण लापता, नक्सली अपहरण की आशंका

नईदुनिया, दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में किरंदुल थाना क्षेत्र के ग्राम गुमियापाल के चार ग्रामीणों के लापता होने की सूचना आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया है। हालांकि दहशत की वजह से परिजनों और ग्रामीणों ने इस बात की सूचना अब तक पुलिस को नहीं दी है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गुमियापाल की युवती किरण कुंजाम, हुंगा मिडियामी, लालू मिडियामी और हुंगा मंडावी को रविवार की रात अज्ञात लोग गांव से उठाकर ले गए। उनके साथ पारंपरिक वेशभूषा में 20-25 अन्य लोग आधुनिक हथियारों से लैस होकर आए थे। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सली उन्हें जंगल की ओर ले गए हैं। इसके बाद से गांव में दहशत है। एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि अब तक परिजनों या किसी ग्रामीण ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई है। बावजूद फोर्स को गांव और क्षेत्र की सर्चिंग के लिए भेजा गया है। बता दें कि इलाके के जंगल में पांच-पांच लाख रपये के दो नक्सली लीडर मुठभेड़ में मारे गए थे। इसमें एक नक्सली लीडर विनोद की बेटी थी। इससे नक्सली लीडर बौखलाए हुए हैं और ग्रामीणों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं।

नक्सलियों ने किया 15 अगस्त को 'काला दिवस' मनाने का एलान

बलराम मिश्र, भागलपुर

▸ आइजी मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों के एसएसपी/एसपी (रेल सहित) को किया अलर्ट

भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने बिहार में 15 अगस्त को 'काला दिवस' मनाने की घोषणा की है। इस दौरान वे अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसे लेकर आइजी अभियान ने बिहार के सभी जिलों के एसएसपी/एसपी (रेल सहित) को अलर्ट करते हुए पत्र लिखा है। जिसमें इस खतरे से निपटने की तैयारी करने को कहा है।

मुख्यालय ने नक्सलियों के संभावित हमले को लेकर आठ रेल रूट को 15 अगस्त तक के लिए अति संवेदनशील घोषित किया है। इसमें किउल- जसीडीह, किउल-जमालपुर, भागलपुर-बांका, पटना-गया, गया-मुगलसराय, गया-कोडरमा, हाजीपुर-मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेल रूट शामिल है। नक्सली रेल मार्ग के अलावा अपने प्रभाव वाले इलाकों में सड़क मार्ग को भी प्रभावित कर सकते हैं। सड़क यातायात बाधित करने के उद्देश्य से नक्सली जीटी रोड को भी निशाना बना सकते हैं। इसे भी अति संवेदनशील घोषित कर सुरक्षा के बेहतर उपाय का निर्देश दिया गया है।

थानों, पुलिस पिकेट व गश्ती दलों को बना सकते निशाना : स्वतंत्रता दिवस के पूर्व नक्सली अपने क्षेत्रों में पुलिस थानों, चौकी, पिकेट, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों, पुलिस केंद्र, शस्त्रागार, बैंक, एटीएम, मोबाइल टावर को भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे मे पुलिस मुख्यालय ने पुलिस को क्षेत्र में गश्त, छापेमारी को भी लेकर सतर्क किया है।

दो हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

राज्य ब्यूरो, पटना : वैशाली के जिले के दो हार्डकोर नक्सलियों ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को लंबे समय से दोनों की तलाश थी। पुलिस मुख्यालय में समर्पण करने वाला नक्सली अमरनाथ सहनी बुचैली गांव, थाना जनदाहा करने वाला है। जबकि राकेश सहनी भी वैशाली जिले मोहम्मदपुर गांव के जनदाहा थाना क्षेत्र का रहने वाला हैं।

भाजपा की महिला विधायक को युवक ने जड़ा थप्पड़

थप्पड़ की घटना पर मीडिया से बात करतीं मुलाना विधायक संतोष सारवान। जागरण

जासं, अंबाला : अज मैं तैनुं छडांगा नी, मैं तैनुं जान तो मारांगा... इतना कहकर एक युवक ने मुलाना से भाजपा की विधायक संतोष चौहान सारवान को थप्पड़ जड़ दिया। लोगों ने पकड़ कर उसकी धुनाई की और पुलिस को सौंप दिया।

संतोष सारवान गांव सरदेहड़ी में एक कार्यक्रम के बाद लोगों की समस्याएं सुन रही थीं। तभी गांव का तलविंदर वहां पहुंचा। उसने अपनी समस्या के समाधान की बात कही। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ ही देर में तलविंदर ने अचानक विधायक को थप्पड़ मार दिया। यह पता नहीं चला कि वह क्या समस्या लेकर आया था।

घर में घुसे तेंदुए को साढ़े छह घंटे में किया पिंजरे में कैद

जागरण संवाददाता, चंबा

पिंजड़े में कैद किया गया तेंदुआ। जागरण

जिला चंबा की पंचायत बैली के गांव चुकरा में रविवार रात एक तेंदुआ एक घर में बनी आटा चक्की में घुस गया। तेंदुए को पारिवारिक सदस्यों ने बंद कर वन विभाग की टीम को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए के घर में घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। विभाग ने तेंदुए को स्वास्थ्य जांचने के लिए कड़ी निगरानी में रखा है।

कर्म चंद व्यक्ति के घर में रविवार रात तेंदुआ घुस आया। घर के आंगन में घूम रहे तेंदुए को कर्मचंद के पुत्र विपन ने देखा और वन विभाग को सूचित किया और सूझबूझ का परिचय देते हुए तेंदुए को घर के आंगन में मौजूद आटा चक्की में कैद कर दिया। वहीं, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम में आरओ कुलदीप कालिया, बीओ अब्दुल हमीद व सलीम खान, वनरक्षक सतीश कुमार, रोहित कुमार व संजीव कुमार मौके पर पहुंचे और तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में जुट गए। करीब साढ़े छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को सुबह करीब साढ़े पांच बजे पिंजरे में कैद किया जा सका। उधर, वन मंडलाधिकारी निशांत मंढोत्रा ने बताया कि विभागीय टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घर में घुसे तेंदुए को पिंजरे में कैद किया है। यदि तेंदुआ स्वस्थ पाया गया तो उसे गोपालपुर चिड़ियाघर या जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया जाएगा।

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने बच्ची को दिया जन्म, मिल रही धमकी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा शहर के एक सेक्टर में रहने वाली सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया है। पीड़िता का आरोप है कि उसको कोर्ट में गवाही देने से रोकने के लिए धमकी मिल रही है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती गर्भवती हुई थी। घटना में शामिल एक आरोपित को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दूसरा अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसको तलाश कर रही है। दुष्कर्म के कुछ दिनों बाद पीड़िता को जान से मारने का प्रयास भी हुआ था। मामले में दो मुकदमे दर्ज हैं।

शहर के एक सेक्टर की रहने वाली युवती के साथ नौ महीने पहले डाढ़ा गांव के रहने वाले चाचा व भतीजे ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मुकदमा वापस नहीं लेने पर कुछ दिन पहले आरोपितों ने पीड़िता पर जानलेवा हमला किया था। आरोपितों ने पीड़िता को कार से टक्कर मारकर घायल किया था। इस मामले में भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने एक आरोपित को तो गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अभी फरार है। फरार आरोपित पीड़िता को धमकी दे रहा है कि वह कोर्ट में गवाही न दे।

धरोहर

खंडेह के राम जानकी मंदिर का पुरातत्व विभाग करेगा संरक्षण, 17वीं सदी में निर्मित किलेनुमा मंदिर की वास्तुकला आकर्षण का केंद्र, एक ही पत्थर पर बना प्रतीत होता है पूरा मंदिर, बाहर दिखता है किलेनुमा

दीवारें कहतीं रामायण-महाभारत की कहानी

राजीव त्रिवेदी, हमीरपुर

हमीरपुर के खंडेह गांव स्थित राम जानकी मंदिर की दीवारों पर बने चित्र। जागरण

खंडेह गांव का राम जानकी मंदिर। जागरण

जिले के खंडेह गांव स्थित राम जानकी मंदिर की दीवारें रामायण और महाभारत की कहानियां कहती हैं। भारतीय वास्तुकला के अनूठे उदाहरण इस मंदिर में पत्थरों पर शिल्पकारी का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। यहां पत्थरों पर उकेर कर रामायण, महाभारत समेत कई पौराणिक प्रसंग जीवंत किए गए हैं। पुरातत्व विभाग अब इसका संरक्षण करेगा।

हमीरपुर को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी जिले की मौदहा तहसील में 10 हजार आबादी वाले खंडेह में 17वीं शताब्दी में बना राम जानकी मंदिर है। इस गांव का जिक्र अबुल फजल की आइन-ए-अकबरी में भी है। तब यह इलाका कालिंजर शासकों के अधीन था। उस समय यहां के जमींदार चंडीदीन दुबे ने एक एकड़ क्षेत्रफल में मंदिर बनवाया था। इसमें भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और सीता की अष्टधातु की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। यहां दक्षिणमुखी हनुमान प्रतिमा भी है।

कन्नड़ और राजस्थानी शैली का मेल : यह मंदिर कन्नड़ और राजस्थानी वास्तुकला का अनूठा नमूना है। एक ही पत्थर पर पूरा बना प्रतीत होने वाला यह मंदिर किलेनुमा दिखता है। ग्रेनाइट से बना बुंदेलखंड का इकलौता मंदिर है, जहां त्रेता और द्वापर युग का सजीव चित्रण साथ है। भारत में ऐसी कलाकृतियां कर्नाटक और राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, अजमेर के मंदिर में देखी जाती है। मंदिर निर्माण के लिए चित्रकूट के खोह गांव के पहाड़ों से बैलगाड़ियों से पत्थर लाए गए थे।

चांदी के साठ रुपये रोज मजदूरी : संरक्षक लालू दुबे ने बताया कि मंदिर के निर्माण के लिए कर्नाटक और राजस्थान से कारीगर आए थे। तब शिल्पकारों ने न्यूनतम मजदूरी चांदी के 20 रुपये और अधिकतम 60 रुपये रोज का मेहनताना लिया था। पूरे मंदिर में लगी देव प्रतिमाएं तराश कर बनाई गई हैं। प्रमुख त्योहार के अलावा सावन में यहां काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

संरक्षण का प्रस्ताव पास : पुरातत्वविद एसके दुबे ने बताया कि खंडेह का यह मंदिर अद्भुत है। ऐसा मंदिर उत्तर प्रदेश में संभवतः कहीं और नहीं है। इसके पुरातात्विक संरक्षण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। विभाग ने संरक्षण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द घोषणा होने की उम्मीद है।

सोशल साइट पर हिंदू समुदाय पर अभद्र टिप्पणी से तनाव

जागरण संवाददाता, रुड़की : सोशल साइट पर रुड़की के एक युवक ने कश्मीर मामले में हिंदू समुदाय को लेकर एक अभद्र टिप्पणी कर दी। इससे हिंदू संगठन के लोगों में उबाल है। इसे लेकर रविवार देर रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

रुड़की निवासी एक युवक ने रविवार को कश्मीर के हिंदू समुदाय को निशाना बनाते हुए एक पोस्ट डाली थी। इसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। जब फेसबुक पर डाली गई इस पोस्ट का हिंदू संगठन के लोगों को पता चला तो वह आक्रोशित हो गए। फेसबुक पर डाली गई इस पोस्ट का स्क्रीन शॉट लेकर बजरंग दल के मंत्री शिव प्रसाद त्यागी के नेतृत्व में काफी संख्या में हिंदू संगठन के लोग कोतवाली सिविल लाइंस पहुंच गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस बावत पुलिस को बताया कि इस मामले को लेकर समुदाय के लोगों में आक्रोश है।

शूटिंग के दौरान हुई थी मोदी की ग्रिल्स से पहली मुलाकात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ पहली ही मुलाकात में मोदी ने मेजबान बेयर ग्रिल्स को बनाया मुरीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 'मैन वर्सेस वाइल्ड' के मेजबान बेयर ग्रिल्स के बीच का अद्भुत सामंजस्य देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि दोनों की पहली मुलाकात उसी दिन हुई थी। जानकारों के मुताबिक शूट से पहले दोनों के बीच न तो कोई मुलाकात हुई थी और न ही कोई बातचीत।

इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला एक-दो महीने के अंदर हुआ। खुद प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि जब डिस्कवरी की ओर से ऐसा प्रस्ताव आया तो इसके जरिये पर्यावरण और जानवरों के संरक्षण का संदेश देने के लिए इसमें शामिल होने का फैसला लिया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके जीवन का लंबा वक्त जंगलों और पहाड़ों में गुजरा है और उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा है।

शूट के निर्धारित दिन काफी बारिश हो रही थी। मौसम खराब था। प्रधानमंत्री ने जंगल में जाते वक्त अपने साथ अलग से कुछ भी नहीं लिया ताकि जंगल का अनुभव बिल्कुल प्राकृतिक हो। इस शो में जंगल के संसाधनों से खाने-पीने का कुछ सामान तैयार किया जाता है। चूंकि प्रधानमंत्री शाकाहारी हैं, इसीलिए ग्रिल्स ने उनके लिए चाय बनाई।

यूं तो पहली बार पता चलने के बाद से ही भारत में इस कार्यक्रम को देखने की चाहत लोगों के बीच थी लेकिन भाजपा और केंद्रीय मंत्रियों ने भी इसके प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प दुनिया को पता है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, आरके सिंह समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर लोगों से यह शो देखने की अपील की थी।

1 करोड़ रुपये की पुरानी करंसी के साथ मोहाली में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों से पिस्टल, तेजधार हथियार और जिंदा कारतूस भी मिले हैं।

बाढ़ का पानी कम होने के बाद पटरी पर लौटने लगी जिंदगी

आपदा ▶ बाढ़ प्रभावित चार राज्यों में मरने वालों की संख्या 200 हुई, 12 लाख से ज्यादा लोग आए बाढ़ की चपेट में, राहत एवं बचाव का कार्य जारी

राजमार्गों में शुरू हुई आंशिक रूप से आवाजाही, बरती जा रही सतर्कता

नई दिल्ली, प्रेट्र : केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में राहत एवं बचाव का काम जारी रहने के बीच इन राज्यों में मरने वालों की संख्या 200 हो गई है। बारिश थमने और बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो जाने के बाद यहां जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। अधिकारियों ने बताया 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं।

केरल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या सोमवार को 76 हो गई जबकि सरकारी आंकड़े के अनुसार कनार्टक, गुजरात और महाराष्ट्र में अभी तक 116 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के कच्छ जिले में सड़क पर फंसे 125 लोगों को वायुसेना ने बचा लिया। राज्य में पानी की टंकी ढह जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

सोमवार को राजमार्गों पर आंशिक रूप से आवाजाही शुरू हो गई। मुंबई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग-4 महाराष्ट्र के कोल्हापुर के समीप छह दिनों से बंद था जिससे हजारों ट्रक फंसे हुए थे। बाढ़ प्रभावित राज्यों में सतर्कता बरती जा रही है। अधिकांश नदियां उफन रही हैं और जलाशय खतरे के निशान के पार हैं।

केरल में करीब 2.87 लाख लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। अधिकारियों ने कहा कि मालापुरम में 50 लोग अभी भी लापता हैं। कर्नाटक में 70 जिलों के 80 तालुका बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने मरने वालों की संख्या 42 और लापता लोगों की संख्या 12 बताई है। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 43 हो गई है और 4.48 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य में 761 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ओडिशा, बंगाल, बिहार और झारखंड में भारी वर्षा होने के समाचार मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हुई है।

कर्नाटक में बाढ़ग्रस्त बेलगाम के एक रिहायशी इलाके में विशालकाय मगरमच्छ बाढ़ में डूबे घर की छत पर बैठा नजर आया। एएनआइ

केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के हालात का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बाढ़ राहत शिविर में पीड़ितों से उनकी व्यथा सुनी। इस दौरान उन्होंने एक बच्ची को गोद में उठा लिया। एएनआइ

कर्नाटक में छत पर पहुंचा मगरमच्छ

कर्नाटक के रैबाग कस्बे में एक मकान की छत पर 10 फीट लंबा मगरमच्छ पहुंच गया। कृष्णा नदी में उफान आने से यह मगरमच्छ बहकर पानी में पूरी तरह से डूबी एस्बेस्टस की छत तक पहुंच गया। मगरमच्छ को छत पर बैठे देखा गया।

मरने के बाद भी नवजात को सीने से लगाए हुई थी मां

केरल के कोट्टाक्कुन्नू में एक मां और उसके नवजात का शव मिला। मरने के बाद भी मां अपने नवजात को सीने लगाए हुए थी। मां गीतू और उसके डेढ़ साल के बच्चे को इस हालत में देख स्थानीय लोग और बचाव दल के लोगों की आंखें भर आईं। शुक्रवार दोपहर भूस्खलन में दोनों की मौत हो गई थी।

ओडिशा में भारी वर्षा की चेतावनी, बंगाल में 16 मरे

जेएनएन, नई दिल्ली

मौसम विभाग ने ओडिशा में आने वाले दो दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सोमवार को भी राज्य में तेज बारिश से आम जनजीवन प्रभावित रहा। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में मानसून फिर सक्रिय हुआ है। इस दौरान हुए वज्रपात में अब तक राज्य भर से 16 लोगों की मौत की सूचना है। लगातार बारिश होने से ओडिशा के कंधमाल जिले में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारी बारिश से कंधमाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 59 पर बालीगुड़ा के पास अस्थायी रूप से बनाया गया कलवर्ट पानी में बह गया। इससे कंधमाल-कालाहांडी-रायगड़ा के बीच आवागमन बंद हो गया है। लगातार बारिश से हीराकुद जलभंडार का जलस्तर भी बढ़ने लगा है।

बंगाल के पुरुलिया वज्रपात से नौ की मौत हो गई। सभी खेत में काम करते समय वज्रपात की चपेट में आ गए। दक्षिण 24 परगना में चार लोगों को मौत हो गई है झाड़ग्राम में दो लोग और हुगली में एक व्यक्ति की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। अगले 48 घंटे में दक्षिण बंगाल में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। इस अवधि में कोलकाता में मध्यम से तेज गति की बारिश दर्ज की जाएगी जबकि दक्षिण बंगाल के आठ जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

चमोली में बादल फटने से छह जिंदा दफन : उत्तराखंड के चमोली जिले के तीन गांवों में मौसम काल बनकर बरसा। यहां बादल फटने, आकाशीय बिजली गिरने और भूस्खलन की वजह से छह लोग मलबे में जिंदा दफन हो गए। प्रभावित गांवों में चार आवासीय भवन और पांच दुकानें धराशायी हो गईं। आपदा में 46 मवेशी भी मारे गए। चमोली में चार दिन के अंतराल में दूसरी बार मौसम का जानलेवा कहर बरपा है। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, काली नदी, गोरी और सरयू समेत अधिकांश नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं।

चमोली के घाट विकासखंड में चुफला गदेरे(बरसाती नाले) के उफान पर होने से सोमवार को सैकड़ों घर खतरे की जद में आ गए हैं। जागरण

पीवीसी पाइप में शीशे पर पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र सरकार से घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले पीवीसी पाइप में शीशे के मानक पर रिपोर्ट तलब की है। अधिकरण ने इसके इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर भी रिपोर्ट तलब किया है।

एनजीटी को बताया गया था कि अधिकतर भवनों में पानी की सप्लाई के लिए पोलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप का इस्तेमाल हो रहा है। इस पाइप के निर्माण में लैड (शीश) स्टैबलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस पाइक से गुजरने वाले पानी के जरिए लोगों के शरीर में जहरीला शीशा पहुंच रहा है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है।

एनजीटी ने इस मामले में अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी इसे तैयार ही नहीं किया गया है, इसको लेकर एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने नाराजगी जताई और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई के दिन इस पर रिपोर्ट देने को कहा। पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा, '21 मई की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रक्रिया अभी लंबित है। यद्यपि की वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है, लेकिन वह अभी कानून मंत्रालय के पास पड़ा है। अगली सुनवाई पर इस पर रिपोर्ट जमा करें।' एनजीटी ने इस साल मार्च में केंद्र सरकार को पीवीसी पाइप में शीशे के इस्तेमाल के लिए मानक तय करने का निर्देश दिया था। स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार सिंह ने हरित अधिकरण में याचिका दाखिल कर पीवीसी पाइप में शीशे के इस्तेमाल पर मानक तय करने की मांग की है। उन्होंने बाजार से पीवीसी पाइप को हटाने की मांग भी की है।

पीवीसी पाइप से पानी की सप्लाई से लोगों के शरीर में पहुंच रहा है शीशा

फाइल

राजस्थान के भीलवाड़ा मे तोड़ी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति

राज्य ब्यूरो, जयपुर : कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से राजस्थान में अलग-अलग जगह छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में रविवार रात कुछ अज्ञत लोगों ने भीलवाड़ा में शाहपुरा में उम्मेद सागर चौराहे पर लगी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को तोड़ दिया।

प्रतिमा का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। इस घटना की जानकारी सुबह लगी। यह प्रतिमा यहां 1995 में लगाई गई थी। प्रतिमा तोड़ने की घटना के बाद से भाजपाइयों में रोष है। भाजपा के नगर अध्यक्ष रघुनदंन सोनी का कहना है कि कुछ लोगों ने अनुच्छेद 370 हटाने की बौखलाहट मे यह हरकत की है। पुलिस को इन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए।

पुलिस चौराहे के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देख कर यह हरकत करने वालों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपित का पता लगाया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले कोटा के रामगंजमंडी में संघ के कार्यकर्ता पर हमला किए जाने की घटना भी सामने आ चुकी है। नया मामला सामना आने के बाद से तनाव बढ़ गया है।

विशाखापत्तनम में तटरक्षक बल के जहाज में लगी आग, 28 को बचाया गया, एक लापता

विशाखापत्तनम, आइएएनएस: सोमवार को विशाखापत्तनम में तटरक्षक बल के एक जहाज में भीषण आग लग गई। जहाज में सवार 29 क्रू मेंबर में से 28 को जहां बचा लिया गया है, वहीं एक लापता है।

पूर्वी नौसेना कमान के प्रवक्ता के मुताबिक सुबह 11:30 बजे के आसपास जहाज पर जोरदार धमाका हुआ और इसके बाद धुआं निकलने लगा। जान बचाने के लिए क्रू मेंबर को पानी में कूदना पड़ा। तटरक्षक बल का एक अन्य जहाज आइसीजीएस रानी राशमोनी उसी इलाके में गश्त कर रहा था, उसे तुरंत बचाव और राहत कार्यों के लिए घटनास्थल पर भेजा गया। रानी राशमोनी ने विशाखापत्तनम पोस्ट ट्रस्ट की नावों के माध्यम से बचाव अभियान शुरू किया और जहाज पर मौजूद 29 क्रू मेंबर में से 28 को बचा लिया।

एक लापता क्रू मेंबर की तलाश जारी है। अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। बचाव अभियान में आइसीजीएस समुद्र पहरेदार, आइसीजी हेलीकॉप्टर और आइसीजीएस सी-432 भी शामिल थे। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सोमवार को तटरक्षक बल के एक जहाज में भीषण आग लग गई। जान बचाने के लिए 29 क्रू मेंबर पानी में कूद गए। 28 को बचा लिया गया है और एक लापता है। प्रेट्र

दारोगा को निलंबित करने के डीएम के आदेश को एसपी ने किया रद

जागरण संवाददाता, हरदोई : उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिलाधिकारी द्वारा एक चौकी इंचार्ज को निलंबित किए जाने के आदेश को वहां के पुलिस अधीक्षक ने रद कर दिया है। पुलिस कर्मियों ने निलंबन आदेश का विरोध किया था। सोशल मीडिया पर मामला गरमाने के बाद एसपी ने यह कदम उठाया है।

लखनऊ मार्ग पर पुलिस चौकी के पास बेसहारा जानवरों का झुंड मिलने पर डीएम पुलकित खरे ने मंडी चौकी प्रभारी संजय शर्मा को रविवार रात निलंबित कर दिया था। सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों के साथ ही पुलिस अधिकारियों ने भी आदेश को गलत बताया। रविवार रात ही पुलिस अधिकारियों ने एसपी से मिलकर डीएम द्वारा निलंबन आदेश का विरोध किया। सेवानिवृत्त डीआइजी उमेश कुमार सिंह ने मामले में सोशल मीडिया पर एसपी को मजबूती से कदम उठाने की बात कही थी। सोमवार को एसपी आलोक प्रियदर्शी ने खुद को पुलिस का प्रशासनिक मुखिया बताते हुए डीएम द्वारा जारी आदेश को रद कर दिया। एसपी ने अपने आदेश में खुद को पुलिसकर्मियों के साथ बताया। मामला तूल पकड़ने पर दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से आदेश रद करने का पत्र जारी कर दिया।

गांधी के प्रभाव से शुरू में धन व यौन मुक्त रहीं हिंदी फिल्में

नई दिल्ली, प्रेट्र : क्या आपने कभी सोचा है कि 1980 के आस-पास तक हिंदी फिल्में पैसे की चकाचौंध और यौन आकर्षण से क्यों दूर रहीं ? उनके नायक गरीब से मध्यम वर्ग के क्यों हुआ करते थे? या फिल्में सामाजिकता की मशाल क्यों ऊंचा रखती थीं? फिल्मों के नायकों को अच्छे इंसान के रूप में क्यों दिखाया जाता था? दरअसल, यह सबकुछ शुरुआती हिंदी फिल्मों पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके आदर्शों के गहरे प्रभाव के चलते होता था।

फिल्म निर्माताओं से लेकर दर्शकों तक पर गांधी जी के व्यक्तित्व का गहरा असर हुआ करता था। आर्थिक उदारीकरण के बाद धीरे-धीरे समाज और फिल्मों में बदलाव आना शुरू हुआ। लंदन में रहने वाले लेखक और पत्रकार संजय सुरी ने अपनी किताब में हिंदी फिल्मों से जुड़े इस तरह के कई रोचक तथ्यों को उजागर किया है। 'ए गांधीवादी अफेयर : इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रायल ऑफ लव इन सिनेमा' नामक अपनी नई किताब में सुरी ने कहा है कि चाहें राज कपूर हों, शम्मी कपूर, देवानंद या फिर मनोज कुमार, इन सभी पर राष्ट्रपिता का गहरा असर था। उस जमाने की फिल्मों पूंजीवाद को एक अपराध के रूप में दिखाया जाता था।

हाथी मेरे साथी

हाथियों की रक्षा और उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित विश्व हाथी दिवस पर ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित प्रसिद्ध नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में हाथी को भोजन खिलाते पर्यायक। हाथियों को इंसानों का करीबी और वफादार माना जाता है। इंसानों से हाथियों की दोस्ती को लेकर कई फिल्में भी बनी हैं। इनमें राजेश खन्ना की 'हाथी मेरे साथी' जैसी सुपरहिट फिल्म भी शामिल है। प्रेट्र

टीवी अभिनेत्री ने पति के खिलाफ दर्ज कराया घरेलू हिंसा का मामला

मुंबई, आइएएनएस: एक लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री ने अपने दूसरे पति के खिलाफ कांदिवली के समता नगर पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। अभिनेत्री का आरोप है कि वर्ष 2017 से उसका दूसरा पति कथित तौर पर उसकी बेटी को पीटता है, गंदी-गंदी गालियां देता है, उस पर अश्लील टिप्पणी करता है और मोबाइल पर अश्लील तस्वीरें दिखाता है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

शिकायत पर पुलिस ने धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न के लिए सजा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के इरादे से सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) व धारा 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर दिलीप सावंत ने बताया कि फिलहाल आरोपित को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि पहली शादी से अभिनेत्री की एक बेटी है। इसके बाद रिश्ते बिगड़ने पर अभिनेत्री ने 2013 में दूसरी शादी की थी। 2016 में इनको एक बेटा भी हुआ था।

गीता प्रेस से अब नेपाली में भी उपलब्ध होगा तुलसी का साहित्य

गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर

- 2005 से नेपाली में प्रकाशित हो रहा श्रीरामचरितमानस
- विनय पत्रिका का अनुवाद पूरा, साल के अंत तक प्रकाशन संभव

गीताप्रेस ने नेपाली भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के समग्र साहित्य का अनुवाद कराना शुरू कर दिया है। श्रीरामचरितमानस का अनुवाद बहुत पहले हो चुका है, नेपाली में यह ग्रंथ 2005 से प्रकाशित हो रहा है। विनय पत्रिका का अनुवाद पूरा हो चुका है। साल के अंत तक विनय पत्रिका के प्रकाशन का लक्ष्य है।

हनुमान बाहुक, बरवै रामायण, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल का भी अनुवाद पूरा हो चुका है, शेष तुलसी साहित्य का अनुवाद नेपाल में चल रहा है। तीन संस्करणों में नेपाली में श्रीरामचरितमानस की अब तक 12,500 प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। तुलसी साहित्य के अलावा गीताप्रेस से नेपाली में गीता सहित कुल 36 पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। अब तक कुल 1,86,500 नेपाली भाषा में पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। धार्मिक पुस्तकों का नेपाली भाषा में अनुवाद कराने की जिम्मेदारी संपूर्ण तुलसी साहित्य को नेपाली भाषा में प्रकाशित करने का लक्ष्य लेकर गीताप्रेस चल रहा है। अनेक पुस्तकों का अनुवाद पूरा हो चुका है, कई का चल रहा है। विनय पत्रिका की प्रूफ रीडिंग चल रही है।

-लालमणि तिवारी, उत्पाद प्रबंधक, गीताप्रेस

तुलसी साहित्य सहित कुल 15 पुस्तकों का नेपाली में अनुवाद पूरा हो चुका है। 11 पुस्तकों का अनुवाद चल रहा है। गीताप्रेस के अनुवाद संयोजक राजकुमार भट्टराई दिन-रात इस कार्य में लगे हुए हैं।

-जयकिशन सारडा, व्यवस्थापक, काठमांडू केंद्र

गीताप्रेस के काठमांडू केंद्र के व्यवस्थापक जयकिशन सारडा को दी गई है।

परेशानी

खूंटी के तिलमा पंचायत में राशन की आस लेकर आए लोगों की रोज टूटती हैं उम्मीदें, लिंक आने के इंतजार में घंटों खड़े रहते हैं ग्रामीण, हाथ में एंटीना लेकर ढूंढते हैं नेटवर्क

झारखंड में राशन वितरण में नेटवर्क का रोड़ा

मनोज सिंह, खूंटी

योजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अब राशन वितरण की व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन खूंटी के तिलमा पंचायत के लिए यह व्यवस्था गले की फांस बन गई है। नेटवर्क न आने की वजह से राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से लोगों को घंटो इंतजार के बाद रोज खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

बारिश की वजह से कुछ दिनों से तिलमा गांव समेत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लगातार नेटवर्क गायब है और सर्वर डाउन हो गया है। इस कारण ग्रामीणों को राशन लेने में परेशानी हो रही है। तिलमा पंचायत की डीलर सुनीता पूर्ति ने कहा कि जब तक अंगूठा नहीं लगेगा तब तक राशन कैसे दिया जा सकता है। क्योंकि ऑनलाइन में यह प्रावधान किया गया है कि राशन लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को अंगूठा लगाना ही होगा, जो अनिवार्य है।

सड़क पर एंटीना लेकर टहलते हैं ग्रामीण: तिलमा के ग्रामीण रोज की तरह राशन की आस में रविवार को डीलर के पास पहुंचे। वहां कहा गया कि नेटवर्क नहीं है। ऐसे में ग्रामीण नेटवर्क के लिए अंगूठा लगाने वाली मशीन, तार और एंटीना लेकर सड़क पर इस उम्मीद में टहलते रहे कि कहीं आसपास नेटवर्क पकड़ ले, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लिंक के इंतजार में ग्रामीण घंटों दुकान के इर्द गिर्द मंडराते रहे। हां-हां लगता है नेटवर्क आ रहा है कि आवाज सुनते ही सभी मशीन के आसपास जुट जाते लेकिन फिर तितर-बितर। नेटवर्क के अभाव में एक भी ग्रामीण को रविवार को भी राशन नहीं मिल पाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा, बच्चे घर में बिलख रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो मैनुअल काम ही ठीक था। यहां आई महिलाओं ने कहा, बारिश हो रही है। खेती-बाड़ी का काम छोड़कर रोज राशन दुकान के चक्कर काटना पड़ता है, न जाने ऐसा कितने दिन चलेगा। गुहार लगाई कि अखबार में खबर छाप दीजिए प्रशासन शायद सुध ले ले।

नेटवर्क के इंतजार में हाथ में एंटीना लेकर खड़ा एक ग्रामीण साथ में गांव के अन्य लोग। जागरण

झारखंड में एक ही परिवार के चार सदस्यों ने की आत्महत्या

जेएनएन, गढ़वा

- घर के मुखिया की लाश पेड़ से लटकी मिली, पत्नी व दो बेटियों की लाश भी मिली
- मौके से मिला सुसाइड नोट, पूरे परिवार के साथ जान देने की लिखी है बात

झारखंड के गढ़वा जिले में सोमवार सुबह एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर सुसाइड नोट मिलने से पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। पुलिस हत्या के बिंदुओं पर भी तफ्तीश कर रही है।

बताया जा रहा है कि शिवकुमार रजक (30) गरीबी तथा बीमारी से परेशान थे। परिजन शिवकुमार के सिर पर कर्ज होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उसने किससे कर्ज लिया था इसकी जानकारी नहीं है। परिजनों का कहना है कि सोमवार सुबह शिवकुमार रजक को माधव बस से इलाज के लिए रांची जाना था, लेकिन इससे पहले ही यह घटना हो गई।

सोमवार सुबह शिवकुमार रजक का शव उसके घर के बगल में एक अमरूद के पेड़ से झूलता हुआ मिला। वहीं उसकी पत्नी बबीता देवी (26) व बेटी श्रेया (6) का शव पास के ही एक कुआं में मिला, जबकि 10 वर्षीय बेटी तान्या का शव उसी कुएं की मुंडेर पर मिला। पुलिस को घटनास्थल से सफेद कागज पर चार लाइन में लिखा शिवकुमार रजक का एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें शिवकुमार रजक ने स्वेच्छा से पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की बात लिखी है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

ग्रामीणों ने आशंका जताई कि शिवकुमार ने अपनी पत्नी और एक बेटी की किसी धारदार हथियार से हत्या कर शव को कुंआ में डाल दिया होगा। फिर दूसरी बेटी को भी वहीं कुएं के पास हत्या करने के बाद खुद अमरूद के पेड़ में फांसी लगाकर जान दे दी होगी। पुलिस दूसरे पहलू पर भी जांच कर रही है। कहना है कि जल्द ही स्थिति का पता लगाया जाएगा।

हाथी ने ट्रक से चालक को बाहर निकाला और ले ली जान

नईदुनिया, रायगढ़ : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में छाल वन परिक्षेत्र (धरमजयगढ़) में रविवार रात गणेश नाम के एक जंगली हाथी ने एक ट्रक चालक को मार डाला। उसने रोड पर खड़े खराब ट्रक का कांच तोड़ कर उसमें सवार चालक को सूंड से बाहर निकाल लिया और फिर पटक-पटक जान ले ली।

मामले में धरमजयगढ़ वन मंडल के डीएफओ प्रणय मिश्रा ने बताया कि औरंगाबाद जिले का चालक सनोसराम छाल से घरघोड़ा मुख्य मार्ग से जा रहा था। इस दौरान उसका ट्रक खराब हो गया। रात का वक्त था, इस वजह से वह अपने खलासी के साथ ट्रक में ही सो गया। इसी दौरान रात में जंगल से निकल कर गणेश हाथी आया और वाहन के कांच व अन्य हिस्से को अपनी सूंड से क्षतिग्रस्त करने लगा। इससे भयभीत सनोसराम ट्रक से निकलने की कोशिश कर रहा था कि हाथी ने सूंड से पकड़ लिया। इसके बाद उसे पटक कर मार दिया। उसका खलासी अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा।

Downloaded from: www.iascgl.com

दैनिक जागरण
दौड़ने से पहले हमें चलना सीखना चाहिए

नए कश्मीर की झलक

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में बकरीद का त्योहार जिस तरह लगभग शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया वह उल्लेखनीय भी है और हालात सुधरने का भरोसा बढ़ाने वाला भी। यह सही है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की वापसी के बाद इस राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं और यह स्वाभाविक भी है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि राज्य के लोग बदली हकीकत को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं और इस तथ्य के प्रति भी उनकी समझ बढ़ती जा रही है कि जो कुछ किया गया है वह इस राज्य और वहां के लोगों के हित में है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति न केवल जम्मू-कश्मीर के शेष देश के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक थी, बल्कि उसके तेज विकास के लिए भी ऐसा करना अनिवार्य था। यह हालात में आ रहे बदलाव का ही प्रमाण है कि पिछले तीस साल में कश्मीर में पहली बार बकरीद के मौके पर हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई।

कश्मीर की नई हकीकत पाकिस्तान को भी स्वीकार करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को भी। यह विचित्र है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग दशकों से कश्मीर के मामले में पाकिस्तानी प्रभाव से ग्रस्त है। उसे कश्मीर के सही इतिहास को भी समझना होगा और वर्तमान को भी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का जो वर्ग कश्मीर को पाकिस्तान के नजरिये से देख रहा है वह एक मुगालते में ही है। कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है-अनुच्छेद 370 के साथ भी और उसके बिना भी। अनुच्छेद 370 कश्मीर के भारत में एकीकरण को एक संवैधानिक-कानूनी रूप देने की कोशिश से अधिक नहीं था। इससे भी अधिक यह संवैधानिक प्रावधान कश्मीर के तत्कालीन नेताओं को तुष्ट करने के लिए लाया गया था। आश्चर्य नहीं कि इस प्रावधान से सबसे अधिक लाभ उन स्थानीय नेताओं और उनके परिवारों को ही हुआ जिन्होंने कश्मीर को हमेशा अपनी निजी जागीर की तरह देखा। कश्मीर के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मीडिया की आधी-अधूरी जानकारी का कारण यह है कि वह वास्तविक रिपोर्टिंग से दूर है। राज्य में अशांति की दो-चार घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर जिस तरह की तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है वह जमीनी हकीकत से कोसों दूर होती है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया को यह सच्चाई भी स्वीकार करनी होगी कि कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। यह उचित है कि केंद्र सरकार के स्तर पर यह संकेत दिए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

सोशल मीडिया पर नजर

बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर चलने वाले आपत्तिजनक वीडियो और अन्य सामग्रियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री की यह पहल निश्चित रूप से राहत देने वाली साबित होगी। दरअसल सोशल मीडिया पर मैसेज बेहद तेजी से फैलते हैं और इनका तुरंत असर होता है। जब तक पुलिस-प्रशासन कोई कदम उठाता है तब तक खासा नुकसान हो चुका होता है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इनका पालन कराना खासा मुश्किल है। अभी तक सरकारी मशीनरी के पास न तो पर्याप्त उपकरण हैं और न ही तकनीकी विशेषज्ञ। ऐसे में प्रशासन के सामने स्थिति पर नियंत्रण के विकल्प बहुत सीमित हैं। ईद, रक्षा बंधन और स्वतंत्रता दिवस इसी हफ्ते पड़ रहे हैं। सरकार के सामने विधि व्यवस्था बनाए रखने की गंभीर चुनौती है। इस चुनौती में सोशल मीडिया पर फैलने वाले आपत्तिजनक संदेश भी शामिल हैं। अभी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बकरीद के दौरान विधि-व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव एवं डीजीपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने का मसला विमर्श के केंद्र में रहा। मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि कहीं त्योहारों के दौरान शरारती तत्व सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बार त्योहार के पहले ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है जिससे सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग न किया जा सके। इसके लिए सभी जिलों में विशेष सेल बनाए जा रहे हैं। इसमें आइटी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा रहा है। एसटीएफ भी इसमें सहयोग देगी। यदि मामला ज्यादा गंभीर हो गया तो इलाके की इंटरनेट सेवा बंद करने का तत्काल निर्णय भी लिया जा सकेगा। इन सारी कवायद से यह उम्मीद की जा सकती है कि शरारती तत्व अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन आपत्तिजनक कंटेंट पर नजर रखने की यह व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए। ऐसा न हो कि त्योहारों के दौरान प्रशासन की सतर्कता से शरारती तत्व अपने मकसद में कामयाब न हों, लेकिन सामान्य दिनों में वे खुराफात कर गुजरें। ऐसे मामलों में आम जन को भी सचेत रहने की जरूरत है। किसी भी वीडियो पर चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लग रहा हो, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।

दरें घटाने से ही नहीं बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

डॉ. भरत झुनझुनवाला

कर्ज को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास वाली रणनीति की एक सीमा है। यह तभी उपयोगी होती है जब उपभोक्ता एवं निवेशक को भविष्य पर भरोसा हो

फिलहाल दुनिया भर में ब्याज दरें घटाने की होड़ चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर दबाव बना रखा है कि हाल में की गई कटौती को जारी रखते हुए आगे भी ब्याज दरें घटाने पर काम करें। न्यूजीलैंड, थाईलैंड और भारत के केंद्रीय बैंकों ने भी पिछले महीने ब्याज दरों में कटौती की है। चीन ने आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की, परंतु माना जा रहा है कि वहां भी अंदरखाने ब्याज दरों में कटौती की गई है। ब्याज दरों में कटौती के पीछे सोच है कि ब्याज दर कम होंगी तो उपभोक्ता कर्ज लेकर बाइक अथवा टीवी खरीदेंगे जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। इसके साथ ही ब्याज दर न्यून होने से निवेशकों के लिए कर्ज लेकर फैक्ट्री लगाना आसान हो जाएगा और वे बाइक एवं टीवी बनाने के कारखाने लगाएंगे। इस प्रकार उपभोक्ता की मांग और निवेशक की आपूर्ति के बीच एक सही चक्र स्थापित हो जाएगा, लेकिन प्रश्न है कि क्या वास्तव में ऐसा होगा? इसकी पड़ताल के लिए हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीतियों को ही दुनिया के तमाम देश अपनाते दिख रहे हैं।

अमेरिकन बैंक एसोसिएशन के अनुसार अमेरिका में श्रमिकों के वेतन दबाव में हैं और वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। हालांकि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग अब तक बेरोजगार थे उन्हें अब रोजगार मिल गया है, लेकिन रोजगार पाए हुए लोगों की तुलना में बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत कम है। बाजार में मांग की गति जानने के लिए, जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी खपत पर विचार करना होगा। वे दोहरा झटका झेल रहे हैं। एक तो उनके वेतन पर दबाव है और दूसरा वे कर्ज के बोझ तले दबे हैं। फिर भी वे भारी मात्रा में खपत कर रहे हैं। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर तीन प्रतिशत के मजबूत स्तर पर टिकी हुई है। इस बीच अहम प्रश्न यही है कि वेतन पर दबाव की स्थिति में भी वे कर्ज लेकर खपत क्यों कर रहे हैं?

प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आक्रामक स्वभाव और आत्मविश्वास से वह अमेरिकी जनता को भविष्य पर भरोसा दिला रहे हैं। उसी भविष्य पर भरोसे के चलते अमेरिकी नागरिक वेतन में गिरावट के बावजूद कर्ज लेकर खपत कर रहे हैं। इस खपत के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। जैसे मौसम विभाग भविष्यवाणी करे कि वर्षा अच्छी होगी तो किसान चारों तरफ सूखा दिखने के बावजूद खेत में बोआई करने लगते हैं। वैसे ही अमेरिकी उपभोक्ता खपत में जुटे हैं।

दूसरा प्रश्न है कि अमेरिका की विकास दर इतनी मजबूत क्यों है? खासतौर से तब जब चीन के साथ उसका ट्रेड वार जारी है। अमेरिकी निर्यात दबाव में हैं। उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में विकास का स्रोत कहां है? रोजगार कहां से बढ़ रहे हैं? इसके पीछ कहानी यह है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं द्वारा टैक्सी, और मसाज पार्लर जैसी तमाम सेवाओं की अधिकाधिक खपत की जा रही है। इन सेवाओं में रोजगार ज्यादा बनते हैं। इसलिए अमेरिका में उत्पादन स्थिर रहने और उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता भी सीमित रहने के बावजूद रोजगार बन रहे हैं। दरअसल अमेरिका में जो आर्थिक प्रगति हो रही है और रोजगार बन रहे हैं उसका आधार ब्याज दरों में कटौती नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जनता में आत्मविश्वास पैदा करना है।

अवधेश राजपूत

अमेरिकी सरकार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी कंपनियों पर और अमीरों पर आयकर में भारी कटौती की थी। इससे अमेरिकी सरकार के राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है। वर्ष 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप के सत्तारूढ़ होने के समय अमेरिकी सरकार का राजस्व 3320 अरब डॉलर था जो वर्ष 2019 में 3440 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इसमें बहुत ही मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन अमेरिकी सरकार के खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी अवधि में अमेरिकी सरकार के खर्च 3900 अरब डॉलर से बढ़कर 4500 अरब डॉलर होने का अनुमान है। राजस्व में 120 अरब डॉलर की वृद्धि के मुकाबले खर्चों में 600 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। इन खर्चों की पूर्ति के लिए अमेरिकी सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारी कर्ज ले रही है। ऐसे में अमेरिका के मौजूदा तीव्र विकास का असली स्रोत यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनता में भविष्य को लेकर आशा का संचार किया जिसके चलते अमेरिकी जनता वेतन के दबाव में होने के बावजूद कर्ज लेकर खपत कर रही है।

दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार ने टैक्स कटौती की है। इसके चलते अपने बढ़े हुए खर्चों की भरपाई के लिए भारी मात्रा में कर्ज लेना पड़ रहा है। यानी अमेरिकी उपभोक्ता और अमेरिकी सरकार दोनों कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इसके दम पर ही अमेरिकी आर्थिक विकास में तेजी कायम है। इस आर्थिक विकास की कुंजी ब्याज दरों की कटौती में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के कारण लिए जाने वाले ऋण में है। कर्ज लेकर आर्थिक विकास हासिल करने की रणनीति की अपनी एक सीमा है और यह ज्यादा दिनों तक कारगर नहीं रहती। एक समय निवेशक भी समझ जाते हैं कि कर्ज लेने वाले की स्थिति डांवाडोल है और वे या तो कर्ज देना बंद कर देते हैं या फिर ऊंचा ब्याज मांगते हैं। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वर्तमान में हो रहा आर्थिक विकास जोखिम भरा है और विश्लेषकों की राय है कि ब्याज दरें घटाकर हम देशों को आर्थिक संकट से नहीं उबार पाएंगे।

अब यदि भारत में रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटा भी दे आत्मविश्वास के अभाव में उपभोक्ता एवं निवेशक दोनों ही कर्ज लेने में कतराएंगे। ध्यान करें कि बीते समय में रिजर्व बैंक ने कई बार ब्याज दरों में कटौती की है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि भविष्य में आत्मविश्वास बढ़ने पर ही उपभोक्ता एवं निवेशक कर्ज लेते हैं। यानी सस्ता कर्ज स्वयं में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का मंत्र नहीं है। सस्ता कर्ज केवल उस समय उपयोगी होता है जब उपभोक्ता एवं निवेशक को भविष्य पर भरोसा होता है। बीते समय में तमाम उद्यमियों ने कहा है कि सरकारी अधिकारी उन्हें चोर की दृष्टि से देखते हैं। हाल में कैफे कॉफी डे के संस्थापक द्वारा आत्महत्या किए जाने के पीछे भी यही कारण बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह जनता और निवेशकों से वार्ता करे। निवेशकों को सम्मान दे और उनके मन में भविष्य के प्रति जो आशंका दिख रही है उसका निवारण करे जिससे कर्ज लेकर खपत एवं निवेश का आदर्श चक्र स्थापित हो सके।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

खेती को लाभकारी बनाने का समय

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और पंजाब सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा प्रदान करने पर विचार करने को कहा गया है। अदालत की इस टिप्पणी से एमएसपी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। न्यायालय ने वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को सख्ती से लागू करने संबंधी निर्देश भी राज्य सरकार को दिया है, ताकि किसान अपने अनाज को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर न रहें। भंडारण क्षमता के अभाव में करीब 20 फीसद खाद्यान्न सड़-गल जाते हैं। हालांकि यह पहला अवसर नहीं जब एमएसपी न मिलने तथा इनसे जुड़ी अनियमितताओं को लेकर न्यायालय ने टिप्पणी की हो। समय-समय पर सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों द्वारा कृषि और ग्रामीण दुर्दशा की ओर सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। दुर्भाग्यवश समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन किसानों के हालात नहीं बदलते।

विभिन्न राज्यों से निरंतर आती रही खबरों से स्पष्ट है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नसीब नहीं हो रहा है। कृषि मंत्रालय तथा नीति आयोग भी स्वीकार चुके हैं कि अधिकांश किसान घोषित एमएसपी तक से वंचित रह जाते हैं। कृषि उत्पादों के दाम तय करने वाले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा लागत मूल्य तय करने वाली प्रक्रिया लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। इसकी मुख्य वजह है लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया। पिछले बजट में केंद्र सरकार द्वारा फसलों के दाम डेढ़ गुना किए जाने का वादा जरूर निभाया गया है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, जिसमें सी-2 फॉर्मूले के तहत लागत मूल्य निर्धारित किए जाने की संस्तुति की गई थी, अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मौजूदा लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में ए2-एफएल को आधार बनाकर फसलों की लागत मूल्य के अनुपात में एमएसपी बढ़ाया गया है, जबकि सी-2 प्रणाली को आधार मानकर लागत के अतिरिक्त 50 फीसद का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान संगठनों की मांग रही है। प्रक्रिया ए2-एफएल के तहत खेती में प्रयुक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, मशीनों का किराया तथा पारिवारिक श्रम शामिल होते हैं, जबकि 'व्यापक लागत' यानी सी-2 व्यवस्था के तहत अन्य लागतों के साथ स्वयं की भूमि का किराया भी शामिल किया जाता है जो ए2-एफएल से अधिक व्यापक होता है। इस प्रक्रिया के तहत लागत मूल्य निर्धारण करने से किसानों को मिलने वाले दाम और मौजूदा व्यवस्था के तहत मिलने वाले दाम में बड़ा अंतर है। यही कारण है कि किसान लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं।

केसी त्यागी

सरकार को एमएसपी नीति में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि इससे सीमित मात्रा में ही किसान लाभान्वित हो पाते हैं

चूंकि किसानों से फसल खरीदने के लिए एक मूल्य नीति की आवश्यकता थी, इस दिशा में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई जो आज सीएसीपी के रूप में मौजूद है और मुख्य रूप से कृषि उत्पादों का दाम निर्धारित करता है। मूल्य समर्थन नीति के बाद ही किसानों को उनके उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकारी गारंटी मिल पाई, लेकिन लागत मूल्य के सही आकलन और सबको एमएसपी मिले, इसे सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने के कारण इसकी सार्थकता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। शांता कुमार की रिपोर्ट में वर्षों पहले यह बात कही जा चुकी है कि सरकार को अपनी एमएसपी नीति में बदलाव करने की जरूरत है। इसी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ चुका है कि देश के मात्र छह फीसद किसान ही किसी खरीद एजेंसी को अपना धान एवं गेहूं बेचकर एमएसपी से लाभान्वित हो पाते हैं। मौजूदा स्थिति में एमएसपी को लेकर इतना शोरगुल इसीलिए है, क्योंकि किसानों को एमएसपी के आसपास की कीमत भी नहीं मिल पा रही। इस दिशा में जरूरत है कि सरकार भंडारण एवं वेयरहाउसिंग की सुविधा को दुरुस्त करने के साथ एफसीआइ के कामकाज के तरीके को भी सुदृढ़ करने पर जोर दे।

समझना होगा कि कृषि सामग्री समेत उपभोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, परंतु उसके समानुपातिक कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नहीं हो पाई है। वर्ष 1994 से 2014 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्टील, सीमेंट, कपड़े, आवासीय व्यय, खाद्य पदार्थों, शिक्षा, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी लगभग 300 प्रतिशत तक का इजाफा देखा गया है। रासायनिक खादों के दाम 300 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये तक हो गए हैं, कीटनाशकों की कीमत में भी लगभग चार से पांच गुना तक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कृषि उत्पादों की कीमतों में औसतन 75 से 80 फीसद तक की ही बढ़ोतरी हो पाई है। यह बढ़ती महंगाई के समानांतर नाकाफी है। इस सूरत में ग्रामीण संरचना कमजोर होती जा रही है। प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि खेती के दायरे से घटती जा रही है। किसान बहुत तेजी से मजदूर बनते जा रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 86 प्रतिशत भू-मालिक किसान और लगभग 80 फीसद मजदूर किसान कर्ज में डूबे हैं। आत्महत्याओं पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में कृषि उद्योग की लाभकारी परिकल्पना के तहत खेतिहरों को संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार की सहायता राशि उत्साहवर्धक है। सीधे कृषकों के खाते में जाने से किसान लाभान्वित हुए हैं। ऐसा ही कुछ बीमा योजना के संबंध में भी किए जाने की जरूरत है। सख्त निगरानी में फसलों की क्षति का सही मूल्यांकन न हो पाने से बीमा किसानों के लिए घाटे का सौदा बन रहा है।

राहत की बात है कि बीते पांच वर्षों में किसानों से जुड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे हैं। इस दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हुआ, लेकिन लंबे समय से कृषि जगत के प्रति बरती गई उदासीनता पर विराम लगाने के लिए खेती-किसानी में उत्साह भरने की इस समय सख्त जरूरत है। पूर्ववर्ती सरकारों की मनोवृत्ति और रवैया इस सरकार में नहीं दिखना चाहिए, ऐसी किसानों की अपेक्षाएं हैं।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय

मानव जीवन परमात्मा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। यह परमात्मा की अद्भुत, सर्वोत्कृष्ट रचना है। जीवन की महत्ता समझना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। तात्विक रूप में जीवन का अर्थ है समय। अगर कोई समय का महत्व समझ ले तो उसका जीवन जग में वंदनीय बन जाता है। व्यक्ति समय की बर्बादी एवं दुरुपयोग पर ध्यान नहीं देते। समय नुकसान करने का अर्थ-जीवन को नष्ट करना है। मनुष्य अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को फिजूल आलस्य-प्रमाद-उन्माद में खो देते हैं। वह बीता समय पुनः वापस लौटकर नहीं आता।

समय पर ही सब सुंदर लगता है। समय बीतने पर वह महत्वहीन हो जाता है। इसी प्रकार जीवन घट से अमूल्य क्षणों के जितने बूंद गिर जाते हैं, घड़ा उतना ही खाली हो जाता है। घड़े की वह रिक्तता कभी भी किसी प्रकार से पुनः पूर्ण नहीं की जा सकती। मनुष्य जो अमूल्य क्षण आलस्य, प्रमाद, व्यसन में बर्बाद करता है, उतने ही समय में वह कोई सार्थक कार्य कर सकता है। मनुष्य के जीवन का पल-पल एक उज्ज्वल भविष्य की संभावना को अपने साथ लेकर इस धरती पर आता है। जीवन का हर पल मनुष्य के उत्थान के लिए महान मोड़ साबित हो सकता है। व्यक्ति जब समय गंवाता है तो उसे पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। जो जीवन में कुछ करने की तमन्ना, सपना मन में संजोए हैं, उन्हें चाहिए कि वे कभी भी अपने कर्म-कर्तव्य को भूल कर भी कल पर न छोड़ें। जो कार्य आज करना है, उसे कल पर नहीं छोड़कर आज ही करना चाहिए और कल के काम के लिए कल का दिन निर्धारित करना जरूरी है। इसे नजरअंदाज करना स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। यह अपने भविष्य को पतन के गर्त में गिराने जैसा है।

परमात्मा ने जीवन का यह अमूल्य समय मनुष्य को महानता का इतिहास रचने के लिए प्रदान किया है, पर वह समय की पहचान नहीं करने के कारण दर-दर ठोकर खाते नारकीय जीवन जीता है। विवेकानंद 32 वर्ष की आयु में देवसंस्कृति के पुरोधा बने। विश्व के क्षितिज पर सुनहरे अक्षरों में नाम अंकित करने में समर्थ हुए।

मुकेश ऋषि

संघ लोक सेवा आयोग और उसकी हिंदी

विनोद राठी

यूपीएससी हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ कोई भेदभाव करता ही नहीं है तो फिर वह क्यों सर्जिकल स्ट्राइक को 'शल्य प्रहार' लिखता है?

यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग इन दिनों में चर्चा में है। चर्चा का कारण है इस साल सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों की हिंदी। उदाहरण के लिए एक प्रश्न कुछ इस प्रकार है-'भारत में संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विस्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिरोध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है?' यह सवाल किसी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी में डर का भाव पैदा कर सकता है।

प्रश्न उठता है कि क्या आयोग नहीं चाहता कि हमारे देश की प्रशासनिक मशीनरी में अंग्रेजी माध्यम के अतिरिक्त हिंदी, गुजराती, तमिल इत्यादि भाषा के लोग प्रवेश करें? अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए। अगर संघ लोक सेवा आयोग चाहता कि हिंदी माध्यम के लोग सेवा में नहीं आने चाहिए तो 2013 में निशांत जैन की 13वीं रैंक कैसे आई? 2017 के परिणाम अनुसार साक्षात्कार में हिंदी माध्यम के एक परीक्षार्थी को 275 में से 198 नंबर कैसे दिए गए? इसका निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर संघ लोक सेवा आयोग किसी प्रकार का कोई भेदभाव करता ही नहीं है तो फिर वह क्यों सर्जिकल स्ट्राइक को 'शल्य प्रहार' के रूप में लिखता है? दरअसल यही वह बिंदु है जिस पर संघ लोक सेवा आयोग और हमारे जनप्रतिनिधियों को विचार करने की आवश्यकता है।

ध्यान रहे कि जब हम जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करते हैं तो उसमें केवल अंग्रेजी माध्यम के लोग ही नहीं, बल्कि हिंदी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के युवा भी शामिल होते हैं जो हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जज्बा रखते हैं। विडंबना देखिए एक ओर तो हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लिए हुए हैं और दूसरी ओर हमारे देश की मानव पूंजी अनुवाद के आगे घुटने टेक रही है!

आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो? दरअसल इस समस्या के निदान के लिए द्वि-आयामी नीति अपनाने की आवश्यकता है। पहला संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है और दूसरा उसकी तैयारी में जुटे विद्यार्थियों से। संघ लोक सेवा आयोग को चाहिए कि वह उन्हीं अनुवादकों का प्रयोग करे जो 2011 से पहले उससे जुड़े थे, क्योंकि पहले वाली उसकी हिंदी बेहतर थी। दूसरा आयाम विद्यार्थियों से है जिस पर मैं सर्वाधिक जोर देना चाहता हूं। सोचिए, आप इतने सारे विषय पढ़ते हैं। लगभग हर वह विषय जो समाज और देश को समझने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन अंग्रेजी जो देश-दुनिया को समझने के लिए वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनती जा रही है उसके आगे इतनी लाचारी क्यों? अगर आयोग और विद्यार्थी उपरोक्त आयामों पर गंभीरता से विचार करें तो इससे न सिर्फ क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थियों की क्षमता सुधरेगी, बल्कि अनुवाद की समस्या से निजात पाकर संघ लोक सेवा आयोग भी अपनी विश्वसनीयता को बनाए रख सकता है।

(लेखक एमडीयू विवि में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

अब खत्म होगा घाटी से आतंकवाद

देर से उठाया गया दुरुस्त कदम शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रकाश सिंह एवं प्रतिभा नैथानी ने अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले की सराहना की है। यह कहना बिल्कुल सही है कि जम्मू-कश्मीर में पूर्व से लागू अनुच्छेद 370 अस्थायी था, इसलिए बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब जबकि सरकार ने यह साहसिक निर्णय लिया ही है तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे पहली चुनौती यही है कि जम्मू-कश्मीर में आम जनमानस में विश्वास बहाली की जाए और यह तभी होगा जब वहां कई दशकों से चली आ रही आतंकवाद की विषबेल को नष्ट कर दिया जाए। बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर तेजी से उपलब्ध कराए जाएं। विकास की ओर प्रदेश को उन्मुख किया जाए। इन कदमों से प्रभावित प्रदेश का आम जनमानस अनुच्छेद 370 खात्मे से पहले और बाद के कश्मीर की तुलना कर जब बाद का प्रदेश बेहतर पाएगा तो सच मानिए विश्वास बहाली में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। अतः सरकार अब केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की गंगा बहाने की दिशा में कदम बढ़ाए और पाक अधिकृत कश्मीर को भी वापस लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक कदम उठाए, ताकि अलग-थलग पड़े उस क्षेत्र को विकास के मार्ग पर लाया जा सके।

सर्वजीत आर्या, प्रधानाचार्य, कन्नौज

श्रीराम के वंशज होने के सुबूत

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भगवान श्रीराम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है? इस पर जयपुर की राजकुमारी ने अपनी दिवंगत मां पद्मिनी देवी के निर्देश पर जयपुर स्थित सिटी पैलेस में रखे रामजन्म भूमि और अयोध्या के अति प्राचीन नक्शे को सुबूत के तौर पर पेश किया है और यह दावा किया है कि जयपुर का राजघराना ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के वंशज हैं। वे श्रीराम के पुत्र कुश के 309वीं पीढ़ी के राजा हैं। कुश के वंशज होने से वे कछवाहा वंश, संभवतः कुश का अपभ्रंश होकर यह शब्द हो गया है, कहलाते हैं। राज कुमारी के अनुसार उनका परिवार प्रभु श्रीराम की 309वीं पीढ़ी है। 25 वर्ष में प्रायः राजकुमारों की शादी के बाद उनका उत्तराधिकारी पैदा हो जाते हैं। इस तरह 25 गुणा 309 बराबर 7725 वर्ष हुआ। जबकि पुराणों और स्मृतियों की गणना के अनुसार प्रभु श्रीराम का जन्म आज से लगभग तैतालिस लाख, बीस हजार साल पूर्व इस धरती पर हुआ था, न कि मात्र 7725 वर्ष पूर्व। जैसा कि राज कुमारी दावा कर रही हैं, इसलिए उनका यह दावा पूर्णतः भ्रामक और गलत धारणाओं पर आधारित है और पूर्णतया मिथ्याचार है।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

गुलाम कश्मीर में दमन

यह सही है कि जब राजा हरि सिंह कश्मीर के शासक थे, तब पाकिस्तानी कबायलियों ने अचानक हमला करके कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया था। तभी से पाकिस्तान उसे अपना बताता आ रहा है। यह अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पीओके के संबंध में संसद में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर न केवल भारत का है, बल्कि वहां के लोग गुलाम कश्मीर को भारत में शामिल करने के पक्ष में भी आ रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं। इसकी वजह वहां हो रहे नागरिकों का शोषण और दमन है। पाकिस्तान ने 1947 में सेना के बूते गिलगित और बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा कर लिया था। तभी से यहां लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है।

ritesh01upadhyay@gmail.com

इंदिरा गांधी की भूल

वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध में भारत ने एक तरफा विजय हासिल की थी। पाकिस्तान के लगभग 15 हजार किमी जमीन पर कब्जा एवं 90 हजार सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था। भारत ने युद्ध में जो जमीन कब्जाई थी उसमें पाक अधिकृत कश्मीर का भी हिस्सा था और लाहौर का भी कुछ क्षेत्र था, लेकिन भारत सरकार ने वापस कर दिया। अगर उस समय भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया होता तो आज कश्मीर कोई मुद्दा नहीं होता और पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण होता।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1993 में भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे।

आजकल

अदालती भ्रष्टाचार मिटने की उम्मीद

देश भर के विभिन्न न्यायालयों में अक्सर सभी स्तरों पर विविध प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। इनसे निपटने के लिए विचार तो किया जाता है, लेकिन किसी ठोस नीति और उसके पालन के अभाव में इससे निपटने में मुकम्मल तौर पर कामयाबी नहीं मिल पाई है। ऐसे में हाल में देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कुछ नए कदम उठाने से एक नई उम्मीद जगी है कि न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर हो सकता है

अनंत मित्तल
वरिष्ठ पत्रकार

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ल की कारगुजारियों की जांच की सीबीआइ को इजाजत देकर देश की न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार की सफाई के लिए ऐतिहासिक पहल की है। यह देश अब तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर महाभियोग और उनके इस्तीफे तथा कलकत्ता हाई कोर्ट के पदस्थ न्यायाधीश सीएस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेल भेजे जाते देखने को ही कड़ी कार्रवाई मानता रहा है। अब देश को उच्च न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश के आपराधिक आचरण की जांच के परिणाम का इंतजार है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की शिकायत का अधिकार देकर अदालतों को जवाबदेह और नागरिकों को सशक्त बनाने की ठोस बुनियाद रखी है।

तो क्या यह माना जाए कि ये न्याय प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार की सफाई की निर्णायक शुरुआत है? क्या आगे इससे भी अधिक कड़ाई से न्याय प्रणाली में जमी भ्रष्टाचार और काहिली की काई को साफ किया जाएगा? क्या इसे सोशल मीडिया पर जुडिशियरी की खिंचाई से बने जनदबाव का नतीजा माना जाए कि प्रधान न्यायाधीश को अपने ही बिरादरी की सीबीआइ जांच जैसी प्रत्यक्ष प्रभाव पैदा करने वाली कार्रवाई करनी पड़ी? न्यायपालिका को दरअसल अब तक पवित्रता की ऐसी मूरत समझा गया कि विधान पालिका, कार्यपालिका और लोकतंत्र का प्रहरी प्रेस तक उस पर उंगली उठाने से कतराते हैं। शायद इसीलिए अदालतों में मुवक्किल की हाजिरी दर्ज करने से लेकर तमाम कार्यों के लिए वसूली जारी है।

हद तो तब हुई जब कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कलम से निकले फैसले को अदालत की वेबसाइट पर पोस्ट कर रहे रजिस्ट्री के दो अदना कर्मचारियों ने उसमें हेराफेरी कर दी। इससे साफ है कि देश की अन्य अदालतों की तरह अव्यवस्था और मनमानी से सुप्रीम कोर्ट भी अछूता नहीं है। जस्टिस गोगोई ने उन दो कर्मचारियों को तो बर्खास्त कर दिया, मगर बाकी अदालतों में भ्रष्टाचार पर नकेल कौन लगाएगा? इसके बाद जस्टिस गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की निगरानी के लिए सीबीआइ अधिकारियों की तैनाती की भी व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, हाल में उन्नाव रेप पीड़िता की न्याय की गुहार संबंधी चिट्ठी अदालत में पेश करने में हुई देरी पर भी चीफ जस्टिस गोगोई ने रजिस्ट्री से संबंधित जवाब मांगा है। यह बात दीगर है कि जस्टिस गोगोई खुद भी यौन उत्पीड़न के आरोपों को झेल कर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई में बरी हो चुके हैं।

प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी करके नामांकन की तारीख बढ़ाने के आरोपी जस्टिस एसएन शुक्ला को इनहाउस पैनल ने बदनीयत से अधिकारों के दुरुपयोग का दोषी करार दिया है। इनहाउस कमेटी द्वारा पद से हटाने की सिफारिश के मद्देनजर जस्टिस शुक्ला को जनवरी 2018 में सभी न्यायिक कार्यों से वंचित कर दिया गया था। जस्टिस शुक्ला के बहाने न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस नए सिरे से भले छिड़ी हो मगर यह है बहुत पुरानी। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस निर्मलजीत कौर की किसी अजनबी द्वारा अगस्त 2008 में 15 लाख रुपये अपने घर पर देने की शिकायत की जांच से हरियाणा में जिला अदालतों में भ्रष्टाचार का भंडा फूटा। सीबीआइ जांच में वह रकम जज निर्मल यादव के लिए होने का खुलासा हुआ।

देश के प्रधान न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा भी दुर्व्यवहार और पद के दुरुपयोग के आरोपों से अछूते नहीं हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस सहित सात विपक्षी दलों द्वारा अप्रैल 2018 में राज्यसभा में दाखिल महाभियोग याचिका को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था। महाभियोग की वजह 'मेडिकल कॉलेज घूसखोरी' और सीबीआइ जज बीएच लोया की मृत्यु के मामले थे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने भी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताने के लिए देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार प्रेस कांफ्रेंस की थी। देश ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पदस्थ न्यायाधीश जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का मंजर मई 1993 में देखा। उन पर 1990 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, मगर महाभियोग लोकसभा से ठुकराए जाने पर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही देश में पहली बार पिछले साल कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सीएस कर्णन को सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर छह माह के लिए जेल भेजा जा चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट के ही जस्टिस सौमित्र सेन को सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने गबन का दोषी पाया और राज्यसभा ने 2011 में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन पर भी पद के दुरुपयोग से संपत्ति जोड़ने के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग याचिका आई। वर्ष 2010 में सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने दिनाकरन ने जुलाई 2011 में इस्तीफा दे दिया। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला के खिलाफ भी राज्यसभा में महाभियोग याचिका 18 दिसंबर 2015 के उनके न्यायिक फैसले में आरक्षण संबंधी टिप्पणियों के खिलाफ आई। जस्टिस पारदीवाला ने अपने फैसले को 19 दिसंबर 2015 को संशोधित करके कुर्सी बचाई।

न्यायप्रणाली में सुधार की कोशिश चीफ जस्टिस गोगोई से पहले भी चीफ जस्टिस जेएस वर्मा और जस्टिस पीएन भगवती कर चुके हैं। उनके प्रयासों का असर आम लोगों को इंसाफ मिलने की प्रक्रिया पर हुआ। इस प्रकार उच्च अदालतों में तो समय-समय पर सफाई की प्रक्रिया दिखाई दी है, मगर निचली अदालतों के खराब हालात की राज्य सरकारों को सुध ही नहीं है। इसलिए न्यायपालिका में आमूल-चूल सुधार की जरूरत है। उत्साहजनक यह है कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने न्यायपालिका में सफाई की शुरुआत अपनी नाक के नीचे से ही की है। यदि उस पुरानी कहावत को मौजूं मानें कि 'खुद से की गई अच्छे काम की पहल से ही दूसरे प्रभावित होते हैं' तो जस्टिस गोगोई की कार्रवाई का देश की न्यायिक व्यवस्था में नीचे तक संदेश जाना लाजिमी है।

नई नौकरशाही से बनेगा न्यू इंडिया

सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाइएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक सामाजिक-आर्थिक प्रशासन में उद्घाटित किया था कि नौकरशाही प्रभुत्व स्थापित करने से जुड़ी एक व्यवस्था है। जबकि अन्य विचारकों की यह राय रही है कि यह सेवा की भावना से युक्त एक संगठन है। उक्त संदर्भ तब का है जब भारत औपनिवेशिक सत्ता में था। समय की मांग के अनुरूप नौकरशाही को परिवर्तित करके संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा और पारदर्शिता से ओतप्रोत करने का प्रयास किया गया पर सफलता दर मनमाफिक नहीं रही है। मौजूदा सरकार पुराने भारत की भ्रांति से बाहर आकर न्यू इंडिया की क्रांति लाना चाहती है जो बिना लोक सेवकों के मानस पटल को बदले संभव नहीं है। देश में नौकरशाही हठवादिता को बढ़ावा देने का भी काम करती रही है। साथ ही लालफीताशाही की जकड़न से विकास को भी बंधक बनाए हुए है। जिस नौकरशाही को नीतियों के क्रियान्वयन और जनता की खुशहाली का जिम्मा था, वही शोषणकारी और अकर्मण्य हो जाए, तो न तो अच्छी सरकार रहेगी और न ही जनता की भलाई होगी। मोदी शायद इस मर्म को समझते थे, और यही कारण है कि लालफीताशाही पर प्रहार करने के साथ उन्होंने लालबत्ती को भी पीछे छोड़ना जरूरी समझा।

वैसे 1991 के उदारीकरण के बाद से देश की प्रशासनिक आबोहवा में बदलाव आ चुका था। वर्ष 1992 में विश्व बैंक द्वारा सुशासन की गढ़ी गई नई परिभाषा में नए भारत की नींव रख दी गई थी। तभी से नई लोक सेवा का प्रवेश भारत में हो गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 21वीं सदी के शुरू में आई रिपोर्ट में भी लोक सेवकों को लेकर अच्छे-खासे सुधार सुझाए गए। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार लोक सेवकों पर लगाम लगाने वाला जनता को एक बड़ा हथियार मिल गया। प्रशासनिक अध्येता भी यह मानते हैं कि सूचना के अधिकार ने शासन-प्रशासन के कार्यों में झांकने की जो शक्ति दी, उससे भी लोक सेवकों में एक नई अवधारणा का सृजन हुआ और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ी।

नई लोक सेवा न्यू इंडिया को इसलिए चाहिए, क्योंकि समय सीमा के भीतर विकास और रोजमर्रा की समस्याओं पर सिंगल विंडो के तर्ज पर हल देना है। चुनौतियों से भरे देश, उम्मीदों से अटे लोग तथा वृहद् जवाबदेही के चलते मौजूदा मोदी सरकार के लिए विकास और सुशासन की राह पर चलने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। भूमंडलीकरण के दौर में लोक सेवा का परिदृश्य भी नया करना होगा, ताकि न्यू इंडिया में नए कवच से युक्त नई लोक सेवा नई चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कर सके। विकास की क्षमता पैदा करना, राजनीति का अपराधीकरण रोकना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और जनता का बकाया विकास उन तक पहुंचाना नई लोक सेवा की पहुंच में होना चाहिए।

देश का विकास यदि नागरिकों का विकास है तो न्यू इंडिया फायदे का सौदा होगा और यदि नागरिकों का विकास ही देश का विकास है तो सरकार के लिए सब कुछ जनता होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए सशक्त लोक नीति और सजग लोक सेवकों की आवश्यकता पड़ेगी, पर विकासशील देश भारत में इनकी कहानी विश्वास और मूल्यों के मामले में थोड़ी खोखली है। नौकरशाही में बड़ी मात्रा में व्याप्त भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो पाएगा जब नई लोक सेवा के आधार बिंदु को अपनाया जाय।

भारत में भ्रष्टाचार से संबंधित एक रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि नौकरशाही से काम निकलवाना सबसे मुश्किल है, लेकिन न्यू इंडिया की चाह है तो नागरिकों को नई सेवा देनी ही होगी। नई लोक सेवा जनसाधारण की महत्ता को समझती है, नागरिकों को वरीयता देती है और लोकहित को सर्वोपरि मानती है, जबकि पुरानी लोक सेवा भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और अकार्यकुशलता से ओत-प्रोत रहती है। महज विनिवेश, निजीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिककिरण तथा वैश्वीकरण के प्रसार मात्र से लोकतांत्रिक मूल्य नहीं संवरेंगे। जब तक नौकरशाहों की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी नहीं होगी और भ्रष्टाचार में कमी नहीं आएगी, तब तक न्यू इंडिया का सपना साकार नहीं हो पाएगा।

खरी-खरी

लोकतंत्र में राजतंत्र का कॉम्बो

सौरभ जैन

इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन इसके लोकतंत्र में भी एक अजीब विडंबना है। इसमें राजनीतिक दल तो हैं, किंतु राजनीतिक दल में लोकतंत्र नहीं है। हम तो नागरिक शास्त्र में अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र के बारे में दी गई जो परिभाषा पढ़कर बड़े हुए, उससे हमारा भरोसा ही उठ गया है। हम तो चाहते हैं कि लिंकन साहब के बाद कोई तो आए, जो उस परिभाषा को किसी अदालत में चुनौती दे।

हमारे पास अपना पर्सनल मोबाइल है। हमारे पड़ोसी के पास पर्सनल कार है। उनके पड़ोसी के पास पर्सनल नौकरी है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हम जनता हैं। हमारे पर्सनल का दायरा भी बड़ा पर्सनल होता है। लेकिन उनके तो ठाठ-बाट ही अलग हैं। उनकी तो पर्सनल पार्टी है और उस पार्टी का पर्सनल लोकतंत्र है। जनता का लोकतंत्र अलग होता है और उनके दल का लोकतंत्र अलग। जनता लोकतंत्र में सामूहिक भागीदार होती है, जबकि दल-दल में धंसते हुए दल के लोकतंत्र में उनके दल में इतना दल-दल है, तभी तो पूरे देश में कमल है।

कल तक अमित जी कहते थे- मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? फिर सारा देश शशि जी की तरफ देखता। उनका जवाब होता- मेरे पास मां है। यह सुनकर जनता भावनाओं के सागर में गोते लगाने लगती। लेकिन अब यह संवाद अर्थहीन साबित हो चुका है, क्योंकि इनके पास मां है और मां के पास अध्यक्ष की कुर्सी है। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी माताजी के पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस है। फेस्टिवल सीजन में जनता ऑफर वाले कॉम्बो पैक खरीदती है, पर इनके परिवार ने कॉम्बो ऑफर वाली पार्टी में अपनी दिलचस्पी दिखाई है- पार्टी के साथ अध्यक्ष पद फ्री।

राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा जैसी कहानी सुनने वाले बच्चे निराश न हों। क्योंकि राजतंत्र की उन कहानियों का मंचन उनका लोकतंत्र देश के रंगमंच पर करता दिख रहा है। अंतरिम जब तक अंतिम नहीं बन जाता, तब तक ये लोग राजा का बेटा राजा वाली कहानी को जीवंत बनाए रखेंगे। बच्चों को चाहिए कि वे नए केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद करने में अपना मन लगाएं, क्योंकि भूगोल कठिन होने वाला है। उनका आज का लोकतंत्र राजनीति विज्ञान से निकलकर कल का इतिहास बन जाएगा, इसलिए उसे आगे वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

ट्वीट-ट्वीट

चिदंबरम अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, क्योंकि इतने वर्षों में उन्होंने अनुच्छेद 370 यही सोचकर नहीं हटाया कि मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा, तीन तलाक पर महिलाओं के साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि वोट खिसक जाएगा। अब इतने साल की सियासत ही ऐसी रही तो सामने वाले का कदम भी तो वैसा ही दिखेगा।

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

सऊदी कंपनी अरैमको रिलायंस में बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है। इसका महत्व कारोबारी पैमानों से भी अधिक है। भारत को सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों के साथ अपने दोस्ताना संबंध और मजबूत बनाने चाहिए। इससे भारत-पाक संबंधों की तस्वीर भी सुधरेगी।

सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

मलाला कश्मीरी मुस्लिमों के प्रति फिक्रमंद हैं, पर उन्हें पाकिस्तानी हिंदुओं, बलूचिस्तान के लोगों की चिंता नहीं। लगता है उनका मार्गदर्शन करने वाले के लिए धर्म ही सर्वोपरि है। अगर आपका धर्म आपकी अंतरात्मा को नष्ट कर दे तो आप अच्छे इंसान नहीं।

तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

प्रगति के पथ पर बढ़ता भारत और सड़क संस्कृति

शैलेंद्र चौहान
स्वतंत्र टिप्पणीकार

विश्व में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। सड़क हादसों में जान गंवाने और घायल होने वालों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा भारत में ही है। भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में एक लाख सत्तर हजार लोग मारे जाते हैं और लगभग पांच लाख लोग जख्मी होते हैं। सरकार को हर साल इन दुर्घटनाओं से अरबों रुपयों का नुकसान होता है। इससे मानव संसाधन के नुकसान के अलावा देश की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है।

भारत के संदर्भ में बात करें तो सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है नागरिकों का लापरवाह होना। हम सड़क के नियमों का पालन नहीं करते यथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनना हम अपनी आजादी और बहादुरी समझते हैं, किंतु ये नहीं समझते कि अनियोजित घटना ही दुर्घटना का रूप ले लेती है। कोई हमें ओवर टेक करे तो हमारी शान पर बन आती है और हम उसे ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित गति के शिकार होते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। पैदल चलते समय भी हम अक्सर लापरवाही बरतते हैं। सड़क दुर्घटना एक ऐसी मानव निर्मित आपदा है जिसे सावधानी बरतने पर रोका जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं- सड़कों की इंजीनियरिंग एवं निर्माण में दोष, वाहन में तकनीकी खराबी, अप्रशिक्षित चालक और मानवीय भूल आदि। भारत में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यह भी है कि यहां वाहन चलाने का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा तेजी से वाहन चलाने से भी देश में सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। तेज गति से वाहन चलाने पर प्रतिक्रिया के लिए कम समय मिलता है, जिससे दुर्घटना होने पर गंभीर चोट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। गलत ओवरटेकिंग व गलत लेन में वाहन चलाना, बार-बार लेन बदलना, गलत तरीके से वाहन को ओवरटेक करना सड़क दुर्घटना का अन्य कारण है।

हमारे यहां सड़कों पर सभी तरह के वाहन एक साथ चलते हैं तथा पालतू व जंगली जानवर भी सड़क पर अचानक आ जाते हैं। इस तरह की विषम परिस्थितियों में दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद वाहन चलाना बेहद खतरनाक है तथा यह दंडनीय अपराध भी है। किसी दवा अथवा नींद आने की स्थिति में वाहन चलाना भी नशे में वाहन चलाने के समान है। नशे की हालत में स्थिति का अनुमान लगा पाना कठिन होता है। इससे नींद आती है, एकाग्रता भंग होती है, शरीर पर खुद का नियंत्रण नहीं रहता, दृष्टि भ्रमित हो जाती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, मैसेज पढ़ना या लिखना, हैडफोन अथवा तेज आवाज में संगीत सुनना, सहयोगियों से बातचीत करना आदि सभी ध्यान भटकाने वाले कारक हैं। इसके अलावा अनेक यातायात नियमों की अनदेखी करना दुर्घटना का कारण बन रहे हैं।

कभी-कभी दूसरे चालकों की लापरवाही से भी एक ही दुर्घटना में कई परिवारों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करने से दुर्घटना के समय चालक व अन्य सवारियों के जोखिम को बढ़ाता है।

हमारे समाज के एक खास वर्ग में कानून का सम्मान या उसका डर कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। कानून को तोड़ना लोग अपने सम्मान की बात समझते हैं। ट्रैफिक से लेकर अपराध तक यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कानून हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर किसी का पालन नहीं हो पा रहा है। प्रशासनिक असफलता और राजनीतिक अवसरवाद के कारण एक वर्ग में अपार समृद्धि आई है। यह समृद्धि आम आदमी को ललचाने वाली है। हमारे समाज में बड़ी तेजी से धनी हुआ यह वर्ग कानून और समाज से अपने को ऊपर समझ बैठा है। पैसा हो जाने पर भी यह वर्ग अभी उच्च संस्कारों को नहीं सीख पाया है। समाज के एक वर्ग के सामने कानून बेबस नजर आ रहा है।

आज का समाज न सिर्फ मानवीय संबंधों को भूलता जा रहा है, बल्कि वह जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण का शत्रु बन बैठा है। पुराने मूल्य तेजी से टूट रहे हैं। संस्कारों और आदर्शों का जीवन में कोई स्थान नहीं रहा है। पुराने संस्कारों के स्थान पर नए मूल्यों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। एक तरफ बड़े लोग सरकारी जमीन पर दौलत का प्रदर्शन करते हुए ऊंची इमारत बना रहे हैं तो दूसरी तरफ गरीब भी सिर छिपाने की नियत से ही सही, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में पीछे नहीं है।

भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण के बाद नैतिक मूल्यों का विचलन बहुत तेजी से हुआ है। घर से लेकर बाहर तक बाजार का दबदबा कायम हो चुका है। किसी भी व्यक्ति की कीमत लगाने को बाजार आतुर दिख रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में नैतिक मूल्य और अनुशासन की कराह तभी सुनाई देती है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। ट्रैफिक प्रणाली की अराजकता इन्हीं सामाजिक संदर्भों की उपज है।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा?

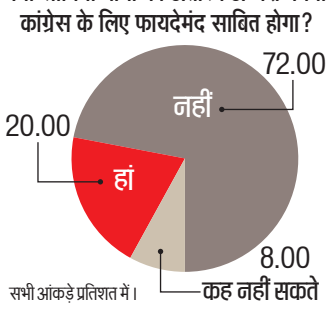

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या श्रेयस अय्यर एकदिवसीय मैचों में चौथे स्थान के लिए बेहतर विकल्प हैं?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

लेकर नाम अशांति का रोते रहिए आप,
साफ दिख रहा कट गया सब कश्मीरी पाप।
सब कश्मीरी पाप चलो अब बांटो ईदी,
खाकर दिखते मस्त सभी सिवईं बकरीदी।
बंधु आपके पास यही मुद्दा ले-देकर,
ढोते रहिए आप पुरानी बातें लेकर।

- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

बड़े फैसले के बाद परिपक्वता दिखाने का समय

अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर के संदर्भ में विशेष प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद सरकार के साथ ही हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि अति उत्साह में सार्वजनिक रूप से कोई बयान न दें और कश्मीर के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें

अनुराग सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनावी घोषणा पत्र कभी न पूरा होने वाले वादे के रूप में तब्दील होता जा रहा था। घोषणा पत्र का मजाक बनाना एक आम बात हो गई थी, फिर चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र क्यों न हो? भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्रों में अनुच्छेद 370 को हटाने का दावा पहले से करती आ रही है। लोगों को यह लगने लगा था कि कई अन्य वादों की तरह यह भी एक खोखला वादा साबित होगा, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस वादे को पूरा किया। इसी के साथ स्वतंत्रता के समय हमारे राजनीतिक पूर्वजों से जो गलती हुई थी उसको सुधारने का यह सफल प्रयास सिद्ध हुआ। लोगों को अभी भी यह बात मानों सच सी नहीं लगती हुई प्रतीत हो रही है। इस बड़े राजनीतिक कदम के फलस्वरूप पूरे देश में एक अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा है।

भारतीय युवाओं के अभिव्यक्ति के सबसे बड़े आधुनिक मंच सोशल मीडिया पर इसका खूब असर दिखाई दे रहा है। कश्मीर से संबंधित पुराने नारे जैसे 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है' या फिर 'कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी' फिर से एक बार दिखाई देने लगे। लेकिन अति उत्साह प्रदर्शित करने और गलती करने में महज एक बहुत महीन सा अंतर होता है। हम अति उत्साह में क्या गलती कर बैठते हैं इसका अंदाजा थोड़ी देर में लगता है, लेकिन तब तक गलती व उसके दुष्परिणाम हो सकता है कि सामने आ चुके हों।

सोशल मीडिया पर लगातार कश्मीर की लड़कियों से शादी करके उनके साथ वहां बस जाने के सुंदर सपने दिखाए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने तो स्वयं यह बात कही कि अब तो लोग वहां की गोरी लड़कियों से शादी कर सकेंगे। ऐसे बयानों का बाढ़ की तरह इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे नाजुक समय पर आना निश्चित रूप से चिंतित करने वाला है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें लगातार शेयर की जा रही हैं, चौराहों पर भी ऐसी बातें सुनने को मिल जा रही है।

ऐसे में वे कश्मीरी जो देश के विभिन्न हिस्सों में रहकर पठन-पाठन या नौकरी करते हैं, और जो सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स देख रहे हैं, अगर वो भारत सरकार के इस फैसले से खुश भी हो रहे होंगे तो क्या भारत के कुछ लोगों के ऐसे रवैये से इस देश में वो अपनापा महसूस कर रहे होंगे जैसे देश के अन्य सामान्य नागरिक वर्षों से करते आ रहे हैं? निश्चित रूप से इसका उत्तर हमें नकारात्मक ही मिलेगा और अगर हम अपने जश्न मनाने की शुरुआत इस तरीके से करते हैं तो यह हमारी बड़ी भूल होगी।

ऐसे में हम उन कश्मीरी लड़कियों का वस्तुकरण कर रहे हैं, वहां की जमीन को अपने सौंदर्य लिप्सा को पूर्ण करने का महज साधन प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा कर क्या उस जमीन को हम महज जमीन का टुकड़ा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम वहां रहने वाले लोगों के साथ अपनी संवेदनाओं को प्रकट नहीं कर रहे हैं? अपितु उसे महज एक जमीन का टुकड़ा मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कश्मीरी नेता यह बयान दे रहे हैं कि भारत इसे महज जमीन का टुकड़ा मानता है और बलपूर्वक इसे हथिया रहा है तो किस आधार पर सरकार के सही फैसले को भी हम नागरिक के तौर पर सही ठहरा पाएंगे? जब अलगाववादी नेताओं द्वारा बरगलाए गए कश्मीरियों से प्यार प्रदर्शित कर उन्हें अपना बंधु दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय हमारी ऐसी ओछी हरकत उन्हें हमारे करीब न ला कर उन्हें हमसे भावनात्मक रूप से बहुत दूर ले जाएगी और फिर से अलगाववादी अपने संदेश को प्रसारित करने में सफल हो पाएंगे कि भारतीय सरकार ने महज शक्ति के बल पर, बिना हमारी राय सुने, हम पर जबरदस्ती ये चीजें थोप रही है।

आज संवैधानिक रूप से हम इस विवादित मुद्दे का हल निकाल कर सामने खड़े हैं, संवैधानिक रूप से समूचा देश यह विवाद अपने पक्ष में जीत चुका है। बस अब एक चीज की आवश्यकता है कि हम उन्हें वैसा ही अपनापा दें जैसा देश के अन्य नागरिकों को देते हैं। हम उन्हें वैसी ही सामान्य नजरों से देखें जैसे हम किसी भी अन्य हिस्से के नागरिक को एक भारतीय के नजर से देखते हैं और मातृभूमि के नाम पर एकजुट होते हैं।

कश्मीर के लोग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की योजनाओं एवं नीतियों की प्रसंशा आज भी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कश्मीर के लोगों से संवाद कायम करने की बड़ी कोशिशें की। उन्हें अपने देश के एक अलग नागरिक के रूप में कभी महसूस नहीं होने दिया, उनकी भावनाओं से जुड़कर वो उनके साथ रहे। अब हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि जिस तरह से पूर्व में अपने दिल को बड़ा करके कश्मीरी भाई-बहनों के साथ दिल खोलकर प्यार दर्शाते आ रहे हैं, उसे और अधिक विस्तृत करने का प्रयास करें। ऐसा करने से उनका हम लोगों पर धीरे-धीरे भरोसा कायम होगा।

अनुच्छेद 370 को हटाना उन लोगों से कोई बदला लेना नहीं था, अपितु वहां पर अमन व शांति कायम कर, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुके कश्मीर को पुनः अन्य राज्यों की तरह ही मुख्य धारा अर्थात विकास के पथ पर लाने की ही एक कोशिश है। रोजगार व अन्य आर्थिक साधन मजबूत न होने के कारण ही वहां के युवा दिग्भ्रमित हुए जिन्हें अब विकास की धारा की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में एक सभ्य नागरिक का परिचय देते हुए हमें उन्हें खुले दिल से आगे बढ़कर स्वीकार करना होगा, उनका विश्वास जीतना केवल सरकार मात्र का कार्य नहीं, अपितु हमारी भी जिम्मेदारी है। ताकि घाटी में अमन कायम हो सके और सरकार ने जिस सकारात्मक मंशा से ऐसा कार्य किया है, वह सफल हो सके।

राष्ट्रीय संस्करण
मंगलवार 13 अगस्त 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

एसएंडपी ने टाटा मोटर्स का आउटलुक निगेटिव रखा

नई दिल्ली : रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने टाटा मोटर्स की लांग-टर्म इश्यूअर और इश्यू क्रेडिट रेटिंग 'भुगतान में विफल की ओर' रखते हुए उसका आउटलुक निगेटिव रखा है। एजेंसी ने कंपनी को क्रेडिट वाच की सूची से भी बाहर निकाल लिया है और कहा है कि भौगोलिक और राजनीतिक जोखिमों के चलते उसके वापस पटरी पर लौटने में उम्मीद से अधिक वक्त लग सकता है। (प्रेट्र)

सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के चलते कई कंपनियों ने आत्ममंथन शुरू किया है। यह पूरे उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है।

— इंजेती श्रीनिवास
सचिव, कॉरपोरेट मामले

कारपोरेट हलचल

राव बने नाबार्ड कंसल्टेंसी के एमडी

के वेंकटेश्वर राव ने नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नाबकॉन्स) के प्रबंध निदेशक पद का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने नरेश गुप्ता का स्थान लिया है, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए। राव इससे पहले नाबार्ड में ही फार्म सेक्टर पॉलिसी डिपार्टमेंट के प्रमुख थे।

ईएसआइ में रेफरल की प्रक्रिया जारी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइ) ने स्पष्ट किया है कि नोएडा स्थित उसके अस्पताल से दूसरे अस्पतालों में मरीजों को पहले की ही तरह रेफर किया जा रहा है। हाल में इस बात के समाचार आए थे कि ईएसआइ नोएडा में जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उनके मरीजों को पैनल में शामिल अन्य अस्पतालों को रेफर नहीं किया जा रहा है। ईएसआइ ने कहा है कि दिशानिर्देशों के मुताबिक मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने का काम बदस्तूर जारी है।

रिलायंस में एक लाख करोड़ रुपये लगाएगी अरैमको

बड़ा सौदा ▶ पेट्रो व केमिकल कारोबार में 20 फीसद हिस्सेदारी खरीदेगी सऊदी कंपनी

बीपी पहले ही रिलायंस के पेट्रोलियम रिटेलिंग कारोबार में खरीद चुकी है 49 फीसद हिस्सा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राजस्व के लिहाज से देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) ने कर्जमुक्त होने के लिए अपने ऑयल व केमिकल बिजनेस में 20 फीसद हिस्सेदारी सऊदी अरैमको के हाथों बेचने का एलान किया। एक लाख करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा के इस सौदे को भारत में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) कहा जा रहा है। इस सौदे के तहत आरआइएल के पेट्रोलियम और केमिकल कारोबार का मूल्य 75 अरब डॉलर (लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपये) लगाया गया है। इससे पहले कंपनी अपने पेट्रोलियम रिटेलिंग कारोबार की 49 फीसद हिस्सेदारी ब्रिटेन की बीपी पीएलसी के हाथों बेचने की घोषणा कर चुकी है। इन दोनों सौदों से कंपनी में कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। दोनों सौदे इसी वित्त वर्ष में पूरे हो जाने की उम्मीद है।

कंपनी की 42वीं सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए आरआइएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि ऐसा होने के बाद कंपनी अगले 18 महीनों में कर्ज मुक्त हो जाएगी। बीते वित्त वर्ष की समाप्ति (31 मार्च, 2019) पर कंपनी पर 1,54,478 करोड़ रुपये का कर्ज था। अंबानी ने बताया कि इसमें 13.60 लाख बैरल की क्षमता वाला गुजरात स्थित जामनगर रिफाइनरी परिसर भी शामिल है। इससे कंपनी में करीब एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा। गौरतलब है कि पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एंटरप्राइज वैल्यू 134 अरब डॉलर की है।

इस सौदे के तहत अरैमको हर दिन पांच लाख बैरल कच्चा तेल जामनगर रिफाइनरी को उपलब्ध कराएगी। इस तरह रिफाइनरी को हर साल करीब 250 लाख टन कच्चा तेल अरैमको से उपलब्ध होगा। कंपनी की योजना आगे चलते हुए इस रिफाइनरी की क्षमता को वर्ष 2030 तक 20 लाख बैरल प्रतिदिन करने की है। इसके अतिरिक्त बीपी रिलायंस के खुदरा पेट्रो कारोबार में 49 फीसद हिस्सेदारी खरीद रही है। इसमें 1400 पेट्रोल पंप और 31 एयरपोर्ट पर एविएशन फ्यूल की बिक्री की सुविधाएं शामिल हैं। मुकेश ने बाद में अपने एक ट्वीट में कहा कि इन सौदों के बाद कंपनी को अगले 18 महीने में कर्ज मुक्त कंपनी में तब्दील करना संभव हो सकेगा। कर्ज मुक्त कंपनी होने का अर्थ उसकी उधारी का स्तर कंपनी के नकद रिजर्व से नीचे आ जाना होता है। कंपनी की उधारी 2013 से उसके कैश रिजर्व से ऊपर चल रही है।

इन दोनों सौदों को कंपनी के भविष्य के लिए बेहतर बताते हुए अंबानी ने कहा कि जैसे जैसे भारत न्यू इंडिया में तब्दील हो रहा है, रिलायंस भी खुद को न्यू रिलायंस में बदल रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दुनिया अक्षय ऊर्जा स्रोतों और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, रिलायंस ने भी अपनी कमर कस ली है। उन्होंने बताया कि जियो का निवेश चक्र अब पूरा हो गया है। अब जियो के लिए सालाना 20,000 रुपये तक के राजस्व का अवसर है।

आरआइएल ने कंपनी के ग्रोथ इंजन में पेट्रोकेमिकल्स के साथ-साथ अन्य सेक्टरों की बड़ी भागीदारी के संकेत दिए। एएनआइ

जम्मू कश्मीर के विकास पर फोकस

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के बारे में की गई अपील पर अंबानी ने कहा, 'हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास और वहां के लोगों की जरूरतों के लिए प्रतिबद्ध हैं। रिलायंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकासात्मक गतिविधियों के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाएगी।' उन्होंने कहा कि वहां किए जाने वाले विकास से संबंधित कंपनी की योजनाओं का एलान आने वाले समय में होगा।

जियो, रिटेल की लिस्टिंग अगले पांच वर्षों में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) ने कहा है कि रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल शाखाओं को अगले पांच वर्षों में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराया जाएगा। ये दोनों ही शाखाएं आरआइएल के विकास को गति देने वाली प्रमुख शाखाओं में शामिल हो गई हैं।

इस वर्ष जून के हिसाब से जियो देश में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाली टेलीकॉम कंपनी बन गई और हर महीने इसके नेटवर्क में लगभग एक करोड़ ग्राहक शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ रिलायंस रिटेल का सालाना राजस्व भी एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। कंपनी की 42वीं सालाना आमसभा में सोमवार को अंबानी ने कहा कि रिलायंस के विकास के अगले चरण में रिटेल और जियो का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। हालांकि सऊदी अरैमको के साथ कंपनी की नवीनतम साझेदारी का मकसद भी पेट्रोलियम कारोबार को मजबूती देना और भविष्य में पेट्रोलियम सोर्सिंग के क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना है। अरैमको के साथ कंपनी की बातचीत पहले से चल रही थी। पिछले महीने ऐसी खबरें भी आई थीं कि वैल्यूएशन के मुद्दे को लेकर दोनों कंपनियों में बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि कंपनियों ने इस पर उस वक्त कोई टिप्पणी नहीं की थी।

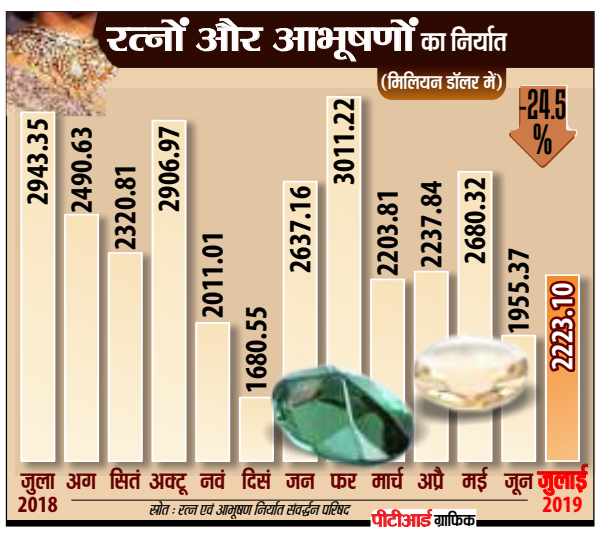

जुलाई में 9,685 करोड़ रुपये के एईपीएस लेनदेन

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) ने सोमवार को बताया कि इस साल जुलाई में आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) से लेनदेन की संख्या 20 करोड़ के स्तर को पार कर गई। एनपीसीआइ ने कहा कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली ने देश में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जुलाई, 2019 में आधार आधारित भुगतान प्रणाली से 22.01 करोड़ लेनदेन हुए। इनका मूल्य 9,685.35 करोड़ रुपये है। इससे एक साल पहले की इसी अवधि में 8,867.33 करोड़ रुपये मूल्य के 19.43 करोड़ लेनदेन हुए थे।

यह प्रणाली आधार सत्यापन के माध्यम से किसी बैंक के प्रतिनिधि द्वारा पीओएस या माइक्रोएटीएम से बैंकिंग लेनदेन की सुविधा देती है। जुलाई में एईपीएस प्लेटफॉर्म के जरिये कुल 6.65 करोड़ भारतीयों ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया। एनपीसीआई की सीओओ प्रवीना राय ने कहा कि एईपीएस आधारित लेनदेन 20 करोड़ के स्तर से ऊपर जाना एनपीसीआई के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सोना उच्च स्तर पर बरकरार चांदी 1,150 रुपये फिसली

▶ 50 रुपये की मजबूती के साथ 38,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना

▶ 1,150 रुपये गिरकर 43,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई चांदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले कुछ सत्रों से सोना निवेशकों की आंखों का तारा बना हुआ है। सोमवार को 50 रुपये की बढ़त के बाद सोना एक बार फिर 38,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के पिछले उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि चांदी में 1,150 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। सोमवार को कारोबार के आखिर में चांदी 43,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर थी।

पिछले सप्ताह गुरुवार को 38,470 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर जाने के बाद शुक्रवार को सोने में थोड़ी मुनाफावसूली हुई और यह 140 रुपये फिसल गया। लेकिन शनिवार को यह फिर 90 रुपये मजबूत हुआ। सराफा कारोबारियों का कहना था कि विदेशी बाजारों में सोने के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बरकरार रहने से घरेलू बाजार में भी पीली धातु को हाथोंहाथ लिया गया। हालांकि चांदी को सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक इकाईयों का समुचित साथ नहीं मिला।

जहां तक विदेशी बाजारों का सवाल है, तो न्यूयॉर्क में सोना मजबूती के साथ 1,503.30 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर कारोबार कर रहा था। पिछले सप्ताह शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि वे कारोबार के मामले में चीन से सुलह करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद निवेशकों ने एक बार फिर सुरक्षा के तौर पर सोने में निवेश बढ़ा दिया। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 38,470 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 38,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। सोने की आठ ग्राम गिन्नी का भाव 28,600 रुपये के पिछले स्तर पर बरकरार रहा। चांदी हाजिर 1,150 रुपये गिरकर 43,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई। चांदी का सप्ताह आधारित डिलिवरी भाव 43,324 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। चांदी के सिक्कों का भाव प्रति सैकड़ा 88,000 रुपये खरीद और 89,000 रुपये बिक्री के पिछले भाव पर स्थिर था।

वार्षिक रिटर्न फाइलिंग अनुपात बढ़ाने पर जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ सीबीआइसी के चेयरमैन ने अधिकारियों को दिया जरूरी उपाय करने का निर्देश

▶ कहा, करदाताओं को होने वाली परेशानियों की तत्काल सूचना बोर्ड को दें

प्रतीकात्मक

जीएसटी के सालाना रिटर्न फाइल करने का अनुपात अपेक्षा के अनुरूप न रहने पर सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने रिटर्न फाइलिंग का अनुपात बढ़ाने के लिए अधिकारियों से जरूरी उपाय करने को कहा है।

सूत्रों के अनुसार सीबीआइसी के चेयरमैन प्रणव के दास ने हाल में शीर्ष अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि जीएसटी के सालाना रिटर्न फॉर्म 'जीएससटीआर-9', 'जीएससटीआर-9ए' और 'जीएससटीआर-9सी' दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 थी। हालांकि उपलब्ध ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि इस रिटर्न को दाखिल करने की स्थिति अपेक्षानुरूप नहीं है। इसलिए टैक्स अधिकारी करदाताओं को उनका रिटर्न समय पर दाखिल करने में मदद करने को पहल करें और अगर कोई कठिनाई आए तो उसकी जानकारी तत्काल बोर्ड को दें। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा मौका है जब सीबीआइसी अध्यक्ष ने अधिकारियों से इस संबंध में आग्रह किया है।

जीएसटी में कुल 1.38 करोड़ असेसी पंजीकृत हैं जिनमें से 17.60 करोड़ असेसी ने कंपोजीशन स्कीम चुन रखी है। कारोबारियों को वित्त वर्ष 2017-18 का सालाना रिटर्न दाखिल करना है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अगस्त के शुरू तक बमुश्किल 20 फीसद असेसी ने ही जीएसटी का सालाना रिटर्न दाखिल किया है। यही वजह है कि सीबीआइसी अध्यक्ष को अधिकारियों को निर्देश देना पड़ा है।

आर एन मारवाह एंड कंपनी एलएलपी के एग्जीक्युटिव डाइरेक्टर (जीएसटी) नितिश शर्मा का कहना है कि सालाना रिटर्न दाखिल करने का अनुपात कम होने की मुख्य रूप से दो वजहें हैं। पहला कारण यह है कि व्यवसायी सालाना रिटर्न पहली बार दाखिल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसकी प्रक्रिया जटिल लगती है। दूसरी वजह यह है कि बड़ी संख्या में ऐसे कारोबारी हैं जिनके पास रिटर्न फाइल करने की समुचित जागरूकता नहीं है। ऐसे में उन्हें मदद करने की जरूरत है।

ऐसी स्थिति मे अगर सरकार चाहती है कि अधिकाधिक असेसी अपना सालाना रिटर्न दाखिल करें तो पहले ही बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 की गई अंतिम तिथि को कम से कम एक महीने और बढ़ाना चाहिए।

सिंडिकेट बैंक को 4,000 करोड़ रुपये की वसूली की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी स्वामित्व वाले सिंडिकेट बैंक को चालू वित्त वर्ष में फंसे हुए कर्ज की वसूली से 4,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति की उम्मीद है। सिंडिकेट बैंक के एमडी मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत चल रहे मामलों के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा निपटारे से कंपनी को बड़ी उम्मीद है। इसके अलावा बैंक अपने स्तर पर भी एकमुश्त समझौता सहित कई अन्य तरीकों से मामलों के समाधान में जुटा है, जिससे धन राशि की वसूली की उम्मीद है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान 4,000 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य है। बैंक को कर्ज वितरण को गति देने को लेकर सरकार से भी पूंजी निवेश की उम्मीद है। महापात्र ने कहा कि बैंक ने सरकार से पूंजी डालने का आग्रह किया है। सरकार को यह तय करना है कि बैंक को यह राशि कैसे देनी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए सरकारी बैंकों के अब तक आए नतीजों के लिहाज से अधिकतर बैंकों ने एनपीए को काबू में रखने में कामयाबी पाई है।

जीएसपी खत्म होने के बाद अमेरिका को 32 फीसद बढ़ा निर्यात

नई दिल्ली, प्रेट्र : जीएसपी के तहत विशेष कारोबारी तरजीह को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाल उलटी पड़ गई है। जीएसपी से बाहर होने के बाद जून में अमेरिका को किया जाने वाला भारतीय उत्पादों का निर्यात 32 फीसद बढ़ गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (टीपीसीआइ) ने यह जानकारी दी है। करीब डेढ़ महीने पहले अमेरिका ने भारत को दिया जाने वाला जीएसपी का लाभ हटा लिया था, जिसका भारत ने विरोध भी किया था।

टीपीसीआइ ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग (यूएसआइटीसी) के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन भारतीय वस्तुओं को जीएसपी का लाभ मिल रहा था, उनका निर्यात पिछले साल जून के 49.57 करोड़ डॉलर से बढ़कर इस साल जून में 65.74 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।

इन उत्पादों का बढ़ा निर्यात : प्लास्टिक रबर, एल्यूमीनियम, मशीन एवं उपकरण, परिवहन उपकरण, चमड़ा, मोती और कीमती पत्थर जैसी चीजें

प्रतीकात्मक

ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता

सिंगला ने कहा कि इससे पता चलता है कि भारतीय उत्पादों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है और मान्यता से इतर ये पूरी तरह से मदद पर निर्भर नहीं है। अमेरिका ने पांच जून से भारतीय उत्पादों को सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी) के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन सुविधा खत्म कर दी थी। यह सुविधा 1,900 भारतीय उत्पादों पर दी जाती रही है।

अधिकांश घाटे की भरपाई : टीपीसीआइ के चेयरमैन मोहित सिंगला ने एक बयान जारी करके कहा कि पिछले साल जून की तुलना में इस साल जून में जीएसपी सुविधा से हटाए गए भारतीय उत्पादों का अमेरिका को निर्यात 32 फीसद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण रुझान है, क्योंकि इससे पहले जीएसपी के तहत 19 करोड़ डॉलर के लाभ का दावा किया गया था। इसके हटने के बाद इस वृद्धि ने 16.17 करोड़ डॉलर के लाभ की भरपाई कर ली है। अब महज 2.83 करोड़ डॉलर का लाभ हासिल करना बाकी रह गया है।

जेट एयरवेज में और निवेश नहीं करेगी एतिहाद

▶ कहा- जेट पर कर्ज के अनसुलझे मुद्दों के बीच और निवेश व्यावहारिक नहीं होगा

▶ भारतीय बाजार के लिए एतिहाद की प्रतिबद्धता बरकरार रहने का दिया भरोसा

नई दिल्ली, प्रेट्र : खाड़ी क्षेत्र की विमानन कंपनी एतिहाद एयरवेज ने कहा है कि कर्ज के बोझ तले डूबी जेट एयरवेज में और निवेश करने का उसका कोई इरादा नहीं है। कंपनी का कहना है कि उसने जेट एयरवेज में देनदारियों से संबंधित अनसुलझे मुद्दों के चलते ही उसमें और निवेश नहीं करने का फैसला किया है। पिछले 18 अप्रैल को परिचालन से बाहर हुई जेट एयरवेज में एतिहाद की 24 फीसद हिस्सेदारी है।

जेट एयरवेज इस वक्त दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। कंपनी के लिए बोली लगाने की दूसरी आखिरी तिथि 10 अगस्त को खत्म हो गई। आखिरी तिथि तक तीन निवेशकों ने जेट एयरवेज के लिए शुरुआती बोली दाखिल की है। माना जा रहा था कि कंपनी में करीब एक-चौथाई हिस्सेदार एतिहाद एयरवेज उसके लिए बोली लगाएगी। लेकिन एक बयान में एतिहाद ने कहा कि उसने भारतीय विमानन कंपनी में और निवेश के लिए अभिरुचि (ईओआइ) दाखिल करने से इन्कार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि जेट एयरवेज की मौजूदा हालत में उसमें निवेश करना कंपनी के लिए ना तो व्यवहार्य, और ना ही समझदारी वाला कदम होता। एतिहाद का यह भी कहना था कि उसने जेट एयरवेज के मुद्दे सुलझाने की सभी कोशिशें कीं, लेकिन आंशिक शेयरधारक होने की वजह से उसके हाथ बंधे हुए थे। हालांकि एतिहाद ने यह भी स्पष्ट किया कि जेट एयरवेज में निवेश नहीं करने के उसके फैसले से भारतीय बाजार के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आएगी। उसने कहा कि वर्तमान में वह अबू धाबी से 10 भारतीय शहरों के लिए विमानों का परिचालन कर रही है और अपने विमानों की बारंबारता लगातार बढ़ोतरी कर रही है।

कंपनी के लिए खरीदार मिलने की चुनौतियां बरकरार हैं। फाइल

अनिल अग्रवाल ने भी किया मना

मुंबई, प्रेट्र : रविवार को जेट एयरवेज के लिए बोली लगाने की घोषणा करने वाली अनिल अग्रवाल की कंपनी भी सोमवार को इससे पलट गई। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के परिवार द्वारा ट्रस्ट के अधीन चलाई जाने वाली कंपनी वोल्कन इन्वेस्टमेंट्स ने जेट एयरवेज के लिए अभिरुचि (ईओआइ) दाखिल करने की बात कही थी।

लेकिन सोमवार को अग्रवाल ने एक बयान के माध्यम से कहा कि जेट एयरवेज के लिए वोल्कन की ईओआइ का मकसद संभावनाओं की पड़ताल करना था। इसके विस्तृत अध्ययन और अन्य प्राथमिकताओं के बाद हमने फैसला किया है कि कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बयान के मुताबिक वोल्कन ने ईओआइ इसलिए दाखिल किया था ताकि वह कंपनी की मौजूदा हालत समझ सके। इसके बाद जेट के लिए निवेशक मिलने पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

परसा कोल ब्लॉक के लिए अडानी को मिली पर्यावरण मंजूरी

विरोध भी

ओपनकास्ट माइनिंग कर कंपनी निकालेगी कोयला, एनजीटी में चुनौती देने की तैयारी में सामाजिक संगठन

रायपुर, नईदुनिया

छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा कोल ब्लॉक से उत्खनन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। इस कोल ब्लॉक से अडानी की कंपनी ओपनकास्ट माइनिंग के जरिये कोयला निकालेगी। 2,100 एकड़ में फैला यह कोल ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित हुआ है। इसका एमडीओ यानी खदान के विकास और ऑपरेशन का अधिकार अडानी के पास है। संरक्षित व सघन वन क्षेत्र होने के कारण इस कोल ब्लॉक के आवंटन का शुरू से विरोध हो रहा है। पर्यावरण मंत्रालय की इस अनुमति को भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है।

इस ब्लॉक को अब केवल वन मंत्रालय की अंतिम मंजूरी बाकी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फारेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने स्टेज वन का फॉरेस्ट क्लीयरेंस दिनांक 15 जनवरी, 2019 को जारी किया था। हालांकि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला के अनुसार मई-जून में केंद्रीय वन पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन समिति (सीबीए) की बैठक में राज्य सरकार ने किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं की। राज्य सरकार ने यदि आपत्ति की होती तो इस परियोजना को स्वीकृति नहीं मिल पाती। शुक्ला के अनुसार राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को कोल ब्लॉक को लेकर कई तरह की गलत जानकारी दी थी।

इस पर हमने सीबीए में तमाम दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसमें फर्जी ग्रामसभा कराने की भी शिकायत भी शामिल थी। प्रभावितों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मिलकर इसकी शिकायत की थी। शुक्ला ने बताया कि कोल ब्लॉक को मिली मंजूरी के खिलाफ एनजीटी में अपील की जाएगी।

कई संगठनों ने इस मामले में सरकार पर आपत्ति नहीं जताने का भी आरोप लगाया है। फाइल

क्यों महत्वपूर्ण हैं यह वन क्षेत्र

केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने परसा वन क्षेत्र को खनन के लिए नो गो क्षेत्र घोषित किया था। इस पूरे वन क्षेत्र में शेड्यूल- 1 के वन्यप्राणी हैं और हाथी का माईग्रेटरी कोरिडोर हैं। पूरा वन क्षेत्र बांगो बैराज का केचमेंट हैं जिससे जांजगीर जिले में चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। परसा कोल ब्लॉक के लिए 842 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लगभग एक लाख पेड़ कटेंगे। इस क्षेत्र में जंगली हाथी व भालू समेत कई तरह के वन्यजीव रहते हैं।

जेएलआर की बिक्री जुलाई में पांच फीसद बढ़ी

▶ अमेरिका में भी कंपनी की बिक्री में दर्ज की गई अच्छी बढ़ोतरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : कंपनी टाटा मोटर्स समूह की कंपनी जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की बिक्री जुलाई में पांच फीसद की वृद्धि के साथ 37,945 इकाई रही। टाटा मोटर्स ने शेयर बाजारों को जानकारी दी है कि जुलाई में जगुआर ब्रांड के वाहनों की बिक्री 11,386 इकाइयों की और लैंड रोवर ब्रांड के 26,559 वाहनों की रही। जगुआर की बिक्री में सालाना आधार पर 3.6 फीसद और लैंडरोवर की बिक्री में 5.6 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई। जेएलआर के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी फेलिक्स ब्रॉटिगम ने कहा, 'ब्रिटेन में जुलाई में अच्छी खुदरा बिक्री हुई। वहां हमने पूरे कार उद्योग के औसत से अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह अमेरिका में इस बार जुलाई माह की उसकी अब तक की सबसे अधिक बिक्री हुई। उन्होंने कहा कि चीन में बिक्री पिछले साल जुलाई की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर रही। गौरतलब है कि जेएलआर की पैरेंट कंपनी टाटा मोटर्स के लिए चालू वित्त वर्ष का अब तक का समय अच्छा नहीं गया है। पूरे ऑटो सेक्टर की मंदी के चलते टाटा मोटर्स की भी घरेलू बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार से भी लंबी अवधि की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने की मांग करती रही है।

फाइल

25 लाख हज यात्रियों ने सऊदी अरब के मीना में शैतान को पत्थर मारने की प्रथा में हिस्सा लिया इस साल। मीना में वर्ष 2015 में इस रस्म के दौरान भीषण भगदड़ की घटना हुई थी, जिसमें 2,400 से अधिक लोग मारे गए थे।

न्यूज गैलरी

अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र को बारूद का ढेर बनाया : ईरान

दुबई : ईरान के विदेश मंत्री मुहम्मद जवाद जरीफ ने सोमवार को कहा कि पूरा खाड़ी क्षेत्र बारूद का ढेर बन गया है। इस स्थिति के लिए उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। आधिकारिक दौरे पर कतर की राजधानी दोहा पहुंचे जरीफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश खाड़ी क्षेत्र में हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं। जरीफ ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी से भी मुलाकात की। कतर के ईरान के साथ ही अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं। कतर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी का प्रमुख सैन्य अड्डा है। कतर, ईरान के साथ हुए परमाणु करार से अमेरिका के निकलने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव को कम करने के प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने हाल में पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य तैनाती काफी बढ़ा दी है। (रायटर)

ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति होंगे अलेजांद्रो गियामाटेई

ग्वाटेमाला सिटी : ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में कंजरवेटिव उम्मीदवार अलेजांद्रो गियामाटेई ने जीत हासिल कर ली है। मध्य अमेरिकी देश की निर्वाचन अदालत ने यह जानकारी दी। अदालत की वेबसाइट पर मतगणना के पल-पल के नतीजे साझा किए गए। संस्थान के अध्यक्ष जुलियो सोलोजानो ने नतीजों की घोषणा की। वहीं गियामाटेई ने कहा कि लक्ष्य पूरा हुआ। गियामाटेई ने 58.5 प्रतिशत मत हासिल करने के साथ 5,50,000 मतों की बढ़त बना ली थी और मतों की गिनती पूरी होने से पहले ही अदालत ने उन्हें विजय घोषित कर दिया। चुनाव में उनकी करीबी प्रतिद्वंद्वी पूर्व प्रथम महिला एवं सोशल डेमोक्रेट सैंड्रा टोरेस उनसे काफी पीछे चल रही थीं। (एएफपी)

हांगकांग हवाई अड्डा बंद, चीन ने प्रदर्शन को आतंक से जोड़ा

बढ़ रहा बवाल ▶ लोकतंत्र समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी, कठोर कदम उठा सकता है प्रशासन

मंगलवार से उड़ान शुरू करने में जुटे हैं अधिकारी

हांगकांग, रायटर/एएफपी : प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ आने के कारण हांगकांग हवाई अड्डे को सोमवार को बंद करना पड़ा। दुनिया के व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक हांगकांग अड्डे से कोई विमान उड़ान नहीं भर सका। चीन ने कहा है कि पिछले दो महीने से शहर में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन ने आतंकवाद का रुख दिखाना शुरू कर दिया है। हवाई अड्डा अधिकारियों ने कहा है कि वे एयरलाइन के साथ मंगलवार सुबह छह बजे से उड़ान शुरू करने के प्रयास में जुटे हैं। हालिया प्रदर्शनों के दौरान हांगकांग की पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई के विरोध में पांच हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी हवाई अड्डे तक पहुंच गए। काले कपड़े पहने लोग हाथों में तख्तियां लेकर पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई के विरोध में नारे लगा रहे थे।

काला मास्क पहने एक 24 वर्षीय प्रदर्शनकारी ने कहा, 'यह हमारी आजादी के लिए है।' अपना नाम यू बताते हुए युवक ने कहा कि हम क्यों चले जाएं? हांगकांग के कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की गतिविधि को आतंकवाद कहे जाने से कठोर आतंकवाद निरोधक कानून और शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। चीन की पीपुल्स आर्म्ड पुलिस समीप के शेनझेन शहर में अभ्यास के लिए जुटी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ने कहा है कि पुलिस दंगा या आतंकी हमले जैसी घटनाओं में की जाने वाली कार्रवाई कर सकती है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को थानों को घेर कर खड़ी भीड़ भजन गा रही थी। सबवे की ओर लौटे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। हिंसक आंदोलन के कारण चीन शासित इस क्षेत्र में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। वर्ष 1997 में ब्रिटेन से चीन के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद स्वायत्तशासी हांगकांग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहीं, चीन ने सख्त कदम उठाते हुए विमानन कंपनी कैथे पैसिफिक एयरवेज के कर्मियों को अपने हवाई क्षेत्र में आने से प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि विरोध प्रदर्शन में कैथे पैसिफिक के कुछ कर्मियों ने भी हिस्सा लिया था।

हांगकांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को उड़ानें रद्द होने के बाद परेशान यात्रियों की भीड़। प्रस्तावित प्रत्यर्पण बिल का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के एयरपोर्ट में घुस आने की वजह से हवाई अड्डा प्राधिकरण ने सभी उड़ानें रद्द कर दी थी। यह दुनिया के सर्वाधिक व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक है। लगातार विरोध प्रदर्शनों की वजह से हांगकांग के पर्यटन उद्योग और व्यवसाय पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा है। एपी

'आंदोलनकारियों पर सख्त कार्रवाई पूरी तरह अस्वीकार्य'

वाशिंगटन, रायटर : हांगकांग में चल रहे आंदोलन से सख्ती से निपटने के चीन से मिल रहे संकेतों के बीच अमेरिकी सांसद मिच मैककोनेल ने चेताया है कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। ढाई महीने से जारी लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन से हांगकांग की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के सांसद मैककोनेल ने ट्वीट किया है- चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता विरोधी नीति के आगे हांगकांग के लोग बहादुरी से डटे हुए हैं। अगर उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई की गई तो वह पूरी तरह से अस्वीकार्य होगी। पूरी दुनिया की निगाह इस आंदोलन की ओर है। चीन के अंतर्गत आने के बाद हांगकांग में यह सबसे बड़ा और प्रभावशाली आंदोलन है।

चीन फिर दोहरा सकता है थ्येनआनमन संहार !

बीजिंग, एएफपी : चीन के नियंत्रण वाले हांगकांग में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए एक बार फिर इस तरह की आशंकाओं को बल मिलना शुरू हो गया है कि क्या चीन हांगकांग में भी थ्येनआनमन जैसे संहार को दोहरा सकता है? बता दें कि हांगकांग में चल रहा प्रदर्शन इन दिनों इतना तीव्र हो गया है कि उससे चीन बेहद परेशान हो गया है।

विश्लेषक मानते हैं कि हांगकांग को लेकर चीन निरंतर घिरता जा रहा है। विश्लेषकों को लगता है कि आज के दौर में जो आर्थिक और राजनीतिक हालात हैं उनमें ऐसा लगता नहीं कि चीन हांगकांग में प्रदर्शनकारियों का दमन करने के लिए थ्येनआनमन जैसी कार्रवाई कर सकता है।

चीन लगातार प्रदर्शनकारियों को धमका रहा है। उन्हें गंभीर परिणाम की चेतावनी दे रहा है। कह रहा है कि आग से मत खेलो, नहीं तो जल जाओगे। इसके बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहा। प्रदर्शनकारियों में खौफ पैदा करने के लिए चीन ने अपनी सेना को भी उतार दिया है। सेना ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में सेना को दंगा करते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का अभ्यास करते दिखाया

चीनी सेना ने दंगाइयों, प्रदर्शनकारियों से निपटने की तैयारी का जारी किया वीडियो

है। वे हथियारों से लैस सड़कों में मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर रहे हैं। चीनी सेना के शक्ति प्रदर्शन के अभ्यास के वीडियो जारी होने के बाद से ही चिंताएं बढ़ने लगी हैं कि क्या चीन बलपूर्वक हांगकांग के प्रदर्शन को भी कुचल सकता है। सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट के विश्लेषक बेन ब्लांड का कहना है कि हांगकांग के प्रदर्शनकारियों में भय पैदा करने के लिए ही सेना ने इस तरह के वीडियो जारी किए हैं। उनका कहना है कि आज के जो आर्थिक हालात हैं उनमें थ्येनआनमन जैसी कार्रवाई चीन के लिए घातक हो सकती है। चीन का वहां सड़कों पर सेना उतारना भी एक खतरनाक कदम हो सकता है।

बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग में वर्ष 1989 में थ्येनआनमन चौक पर लोकतंत्र समर्थकों को चीन ने बलपूर्वक कुचल दिया था। इस संहार की दुनियाभर में कड़ी निंदा की गई थी।

सरकारी सुविधाएं चाहने वालों को अब नहीं मिलेगा अमेरिकी वीजा

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिकी प्रशासन ने उन सभी लोगों को वीजा और ग्रीन कार्ड न देने का नियम बना दिया है जो गरीब हैं और सरकारी सुविधाओं का फायदा लेकर अमेरिका में बने हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की व्यवस्था के शुरू से पक्षधर हैं। आव्रजन मामले में ट्रंप के सहयोगी स्टीफन मिलर की सलाह पर बना यह नियम 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।

अमेरिका में खाद्यान्न, आवास, चिकित्सा और लोक कल्याण की कई सरकारी योजनाओं का लाभ वहां के निवासियों को मिलता है। इस कारण वहां जाने वाले विदेशियों और निवास की स्थायी अनुमति प्राप्त विदेशी मूल के लोगों को भी ये सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अब प्रशासन वीजा देने से पहले जांच लेगा कि अमेरिका आने वाला शख्स अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाने में सक्षम है या नहीं। वह अमेरिका आकर कहीं यहां की नागरिक सुविधाओं पर बोझ तो नहीं बन जाएगा। सरकारी सुविधाओं का फायदा तो नहीं उठाने लगेगा। फेडरल रजिस्ट्रार ने इस बाबत नोटिस जारी कर दिया है। अमेरिका की नागरिक और आव्रजन सेवा के कार्यकारी निदेशक केन कुसीनेली के अनुसार आत्मनिर्भर होना अमेरिका की पुरानी परंपरा है। हम उसी को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ समय के बाद इसका लाभ अमेरिका की कर देने वाली आबादी को मिलने लगेगा। उन्हें अपने धन के एवज में पूरी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।

ग्रीन कार्ड के लिए ट्रंप प्रशासन ने बनाया नियम, 15 अक्टूबर से होगा लागू

फेडरल रजिस्ट्रार ने इस संबंध में जारी किया नोटिस

अमेरिका में अब अपनी जिम्मेदारियां लोगों को खुद ही उठानी होंगी। फाइल

उल्लेखनीय है कि अमेरिका की आव्रजन व्यवस्था में बदलाव राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकताओं में शामिल है। वह वैध और अवैध आव्रजन को कम से कम करना चाहते हैं। वह आव्रजन को अमेरिका के हित के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आव्रजक के हित में नहीं। मेक्सिको सीमा पर दीवार का निर्माण भी ट्रंप की इसी नीति का हिस्सा है। इसके जरिये वह मेक्सिको से होने वाली घुसपैठ पर रोक लगाना चाहते हैं।

सऊदी गठबंधन ने की अदन में संघर्षविराम की घोषणा

काइरो, आइएएनएस : सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन फौज ने यमन के बंदरगाह शहर अदन में संघर्षविराम की घोषणा की है। रविवार को इस एलान के साथ ही गठबंधन सेना ने कहा कि संघर्षविराम का उल्लंघन करने वाले धड़ों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घोषणा से अदन में यमन सरकार समर्थक गठबंधन सेना और अलगाववादी गुटों के बीच छिड़ा संघर्ष खत्म होने के आसार दिखने लगे हैं। पिछले तीन दिनों में इस संघर्ष में 40 लोगों की मौत हो गई।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने इस संघर्ष को खत्म कराने के लिए बातचीत के संकेत दिए थे। सऊदी समर्थित यमन की सरकार का आरोप है कि यूएई के समर्थन वाले अलगाववादी धड़े सदर्न ट्रांजिसनल काउंसिल ने यमन सरकार का तख्तापलट करने की कोशिश की थी। सऊदी गठबंधन की सेना ने हवाई हमला कर इस कोशिश को नाकाम कर दिया था। यमन की राजधानी सना में हाउती विद्रोहियों के कब्जे के बाद से राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर की सरकार ने अदन को ही अपना मुख्य ठिकाना बना रखा है।

अफगानिस्तान में सम्मानजनक समझौता चाहता है अमेरिका : खलीलजाद

काबुल, आइएएनएस : करीब दो दशक से युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति के लिए अमेरिका और आतंकी संगठन तालिबान के बीच कतर में हो रही आठवें दौर की वार्ता सोमवार को पूरी हो गई। वार्ता खत्म होने से एक दिन पहले अफगान मसले पर अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद ने कहा कि अमेरिका दीर्घकालीन और सम्मानजनक समझौता चाहता है। ईद के मौके पर एक ट्वीट में उन्होंने कहा, 'उम्मीद करता हूं कि अफगानिस्तान में युद्ध के बीच यह मेरी आखिरी ईद है। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान अमन चाहता है। हम अफगानियों के साथ हैं और एक दीर्घकालीन, सम्मानजनक समझौते व संप्रभु अफगानिस्तान के लिए प्रयास कर रहे हैं।'

दोहा में चल रही आठवें दौर की वार्ता समाप्त होने की जानकारी देते हुए तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा, 'वार्ता सार्थक रही है। अब दोनों पक्ष अगला कदम उठाने से पहले अपने शीर्ष नेताओं से परामर्श करेंगे।' इस

अमेरिकी दूत ने जताई उम्मीद, जंग के बीच यह आखिरी ईद

अमेरिका व तालिबान के बीच दोहा में चल रही आठवें दौर की वार्ता खत्म

जालमे खलीलजाद फाइल

वार्ता के बाद दोनों पक्षों में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी को लेकर समझौता होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसके बदले में तालिबान वार्ता में अफगान सरकार को भी शामिल करने और आतंकी गतिविधियां समाप्त करने की गारंटी देगा। समझौते में हालांकि तालिबान और अफगान सरकार के बीच युद्धविराम की कोई बात अब तक नहीं की गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद आतंकी दोबारा सक्रिय हो जाएं। अफगानिस्तान में अभी करीब 14 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सैनिकों की तैनाती पर अमेरिका की ओर से अब तक एक लाख करोड़ डॉलर (करीब 70 लाख करोड़ रुपये) खर्च किए जा चुके हैं। इसी के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द उनकी वापसी चाहते हैं।

खलीलजाद के ताजा बयान से पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने किसी तरह का विदेशी दखल स्वीकार नहीं करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के भविष्य का फैसला उसकी सरजमीं पर ही होगा।

मुखौटा संगठनों के जरिये आतंकी गतिविधियां अंजाम दे रहा जेयूडी

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान में प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी हाफिज सईद का आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लश्कर-ए-तैयबा समर्थित जेयूडी अब अपने मुखौटा संगठनों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह संगठन आतंकियों की वित्तीय मदद और मनी लांड्रिंग जैसे अपराधों के लिए जिहादी तंजीम जैसे समूहों का इस्तेमाल कर रहा है। तंजीम को अभी कहीं भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसी का फायदा उठाकर जेयूडी अमेरिका के साथ ही आतंक विरोधी कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो रहा है।

जेयूडी के सरगना और 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के मास्टर माइंड सईद को हाल में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर आंतकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने का आरोप है। पेरिस स्थित आतंक रोधी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ओर से जारी किए गए सख्त दिशा-निर्देशों के बाद ही सईद की गिरफ्तारी हुई थी। एफएटीएफ ने पिछले साल जून में दूसरी बार पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में डाला था। साथ ही पाकिस्तान को आतंकियों की फंडिंग और मनी लांड्रिंग से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। एफएटीएफ ने पहली बार 2012 में पाकिस्तान को अपनी ग्रे यानी निगरानी सूची में डाला था। तीन साल बाद हालांकि उसे सूची से हटा दिया गया था।

अंतरराष्ट्रीय दबाव ने पाकिस्तान ने कर दिया था प्रतिबंधित

हाफिज सईद फाइल

अमेरिका में भारतीय पिता का हत्यारा बेटा पकड़ा गया

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : अमेरिका के फिलाडेल्फिया में असाल्ट राइफल से अपने पिता की हत्या करने वाले भारतीय मूल के सोहन पंजरोलिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिजोफ्रेनिया के मरीज सोहन ने अपने 66 वर्षीय पिता महेंद्र पंजरोलिया की हत्या अपने घर में तीन अगस्त को की थी और हथियार के साथ फरार हो गया था। सोहन को सोमवार को मेसाचुसेट्स से गिरफ्तार किया गया।

सोहन हार्वर्ड विश्वविद्यालय से बैचलर कोर्स की डिग्री लिए हुए है। घटना के बाद उसके वहां जाने की आशंका थी जिसके चलते प्रशासन ने विश्वविद्यालय को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। बाद में पुलिस को विश्वविद्यालय के नजदीक सोहन की कार मिली, जिसके बाद उसके वहां होने की पुष्टि हो गई। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय उसके पास राइफल नहीं थी, इसलिए पुलिस को बिना खूनखराबे के उसे पकड़ने में सफलता मिल गई। पुलिस ने सोहन को नशे का आदी बताया था और उसके पास राइफल होने को खतरनाक करार दिया था।

चीन में लेकिमा तूफान का कहर, 44 की मौत

बीजिंग, एएफपी : पूर्वी चीन में 'लेकिमा' तूफान से 11 और लोगों की मौत हो जाने के बाद सोमवार तक इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ कर 44 हो गई। तूफान के बाद लापता हुए लोगों की तलाश की जा रही है। इससे 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान शनिवार की दोपहर वेंलिंग शहर पहुंचा था। इस दौरान 187 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं और भीषण बारिश हुई। यह इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली तूफान है।

शिंहुआ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के दो प्रांतों में तूफान से 44 लोग मारे गए हैं और 16 लापता हैं। इसने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। रिपोर्ट में झेजियांग प्रांतीय बाढ़ नियंत्रण मुख्यालय ने बताया कि सोमवार को सुबह तक प्रांत में मरने वालों की संख्या बढ़ कर 39 हो गई थी, जबकि नौ लोग लापता हैं।

प्रांतीय बाढ़ नियंत्रक मुख्यालय के मुताबिक इस तूफान से प्रभावित 10 लाख 80 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इससे 65 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

चीन के झेजियांग और शेहडोंग प्रांतों में लेकिमा तूफान ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और अनेक लापता हैं। योंगजिया काउंटी में बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन के कारण नदियों का रास्ता बंद हो हो चुका है। यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। बाढ़ का पानी घरों में घुस आने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि तूफान और बाढ़ से करीब 65 लाख लोग प्रभावित हैं। झेजियांग के लिनहाई शहर में बाढ़ में अपना सामान ढूंढते लोग। रायटर

अमेरिकी डे केयर सेंटर में आग से पांच बच्चों की मौत

वाशिंगटन, एएफपी/एएनआइ : अमेरिका के पेंसिलवेनिया प्रांत के एरी शहर में रविवार देर रात एक डे केयर सेंटर में आग लगने से पांच बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वालों में चार सगे भाई-बहन थे। आठ माह से सात साल तक के इन बच्चों के माता-पिता रात में काम करने के चलते उन्हें सेंटर में छोड़ गए थे।

बताया जा रहा है कि यह सेंटर पहले रिहायशी मकान था। बाद में उसे डे केयर सेंटर में बदल दिया गया। कामकाजी माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें यहां छोड़ जाते थे। हादसे के समय बच्चों समेत आठ लोग सेंटर में मौजूद थे। सेंटर की मालकिन, दो किशोर और पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति भी इस आग से घायल हो गया। दोनों किशोर अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूद गए थे। दमकल विभाग के अधिकारी जॉन विंडोम्सकी के अनुसार, दमकलकर्मी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो सेंटर की पहली मंजिल की खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही थीं। माना जा रहा है कि आग पहली मंजिल के लिविंग रूम से शुरू हुई।

उठे सवाल

रूस की सरकार के हवाले से आए अलग-अलग बयानों से बढ़ा संदेह, हादसे के तीन दिन बाद स्वीकारी परमाणु ईंधन में विस्फोट की बात

रूस में हुए परमाणु हादसे पर है अमेरिका की निगाह

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : रूस के अहम मिसाइल परीक्षण केंद्र में पिछले हफ्ते हुए हादसे से कई सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिकी खुफिया अधिकारी विस्फोट के कारण और प्रकार को लेकर जानकारियां जुटाने में लगे हैं। हमले को लेकर रूस की ओर से आए अलग-अलग तरह के बयानों ने संदेह को और हवा दी है। अंदेशा यह भी है कि हादसा उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, जितना बताया जा रहा है।

रूस के मिसाइल परीक्षण केंद्र में विस्फोट गुरुवार को हुआ था। इसमें सात लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। हादसे के तुरंत बाद रूस की सेना के हवाले से बयान आया था कि परीक्षण के दौरान एक तरल ईंधन वाले रॉकेट इंजन में विस्फोट से आग लग गई। हालांकि परीक्षण केंद्र से करीब 25 मील दूर स्थित शहर सेवेरोविंस्क के स्थानीय प्रशासन ने इससे इतर बात बताई। अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट के बाद कुछ जगहों पर रेडिएशन की मात्रा 200 गुना तक बढ़ी हुई दर्ज हुई। शनिवार को रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम के बयान में पहली बार विस्फोट में परमाणु ईंधन की बात सामने आई।

रूस में मिसाइल परीक्षण से जुड़े एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन। फाइल

स्थानीय लोगों में संशय के बादल : सरकार के अनिश्चित बयानों से स्थानीय लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। रेडिएशन बढ़ने की बातें सामने आते ही लोगों ने आयोडीन की खरीद शुरू कर दी। रेडिएशन के प्रभाव से शरीर को बचाने में आयोडीन सहायक होता है। रूस के पूर्व नौसेना अधिकारी अलेक्जेंडर के. निकितिन ने कहा, 'जानकारियों को सामने लाना चाहिए। लोगों को पता चलेगा तो वे बचाव के कदम उठा सकेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है।'

अमेरिकी अधिकारी सतर्क

रूस के अलग-अलग बयानों और सेटेलाइट से मिली तस्वीरों ने इस ओर अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिकी अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश में हैं कि कहीं विस्फोट उस खास हथियार को बनाने की कोशिश के दौरान तो नहीं हुआ है, जिसकी तारीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने विस्फोट के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि अमेरिकी और यूरोपीय खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि इस विस्फोट से नए हथियार विकसित करने के रूस के प्रयासों को झटका लग सकता है। इससे रूस की कोशिशों में तकनीकी खामी का भी पता चल सकता है।

खास हथियार बना रहा है रूस : अमेरिका से हथियारों की होड़ में लगा रूस इन दिनों एक खास मिसाइल बनाने में जुटा है। 2018 में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पुतिन ने इस मिसाइल को लेकर एक एनिमेटेड वीडियो भी साझा किया था। इस मिसाइल को एक छोटे परमाणु संयंत्र से ऊर्जा मिलेगी। रूस का दावा है कि यह मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में निशाना साध सकती है। यह मिसाइल अपना रास्ता इतने अप्रत्याशित तरीके से तय करेगी और पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में इतनी कम ऊंचाई से निकलेगी कि अमेरिका की मिसाइलरोधी प्रणाली के लिए इसे पकड़ना संभव नहीं होगा।

दूसरा बड़ा परमाणु हादसा : पिछले हफ्ते हुआ हादसा रूस का दूसरा बड़ा परमाणु हादसा है। हालांकि पहले हादसे की तुलना में यह बहुत छोटा है। पहला हादसा 1986 में चेर्नोबिल के परमाणु संयंत्र में हुआ था। इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी।

नार्वे की मस्जिद पर हमले का संदिग्ध कोर्ट में हुआ पेश

ओस्लो, रायटर : नार्वे की मस्जिद में गोलीबारी करने वाले 21 वर्षीय संदिग्ध हमलावर फिलिप मनशाउस को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। जब वह कोर्ट पहुंचा तो उसकी आंख, चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान थे। फिलिप पर सौतेली बहन की हत्या का भी आरोप लगाया गया है। कई हथियारों से लैस फिलिप शनिवार को यहां अल-नूर इस्लामिक सेंटर में घुस गया था। वहां उसकी गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया था।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 65 वर्षीय एक बुजुर्ग ने उसे काबू में कर लिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। फिलिप के वकील के मुताबिक उसने अभी कोई जुर्म नहीं कुबूला है। हमले से ठीक पहले फिलिप के नाम पर कई पोस्ट किए गए थे, जिनमें गत मार्च में न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों पर हुए हमलों की सराहना की गई थी। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये पोस्ट उसने खुद किए थे या नहीं। नार्वे की पीएम एर्ना सोलबर्ग ने कहा कि सरकार घृणा अपराधों को खत्म करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है।

कमाल के भुवनेश्वर

भुवी के चार विकेट की बदौलत भारत दूसरा वनडे जीता

निखिल शर्मा • नई दिल्ली

17 दिसंबर 2007 को जब उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार अपना पहला रणजी मुकाबला खेलने बंगाल के खिलाफ उतरे थे, तो उनके लिए गए अहम तीन विकेटों ने उनके भविष्य की तकदीर तय कर दी थी। उन्हीं भुवनेश्वर ने रविवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में चार विकेट चटकाकर भारत को डकवर्थ लुइस आधार पर 59 रनों से जीत दिलाई। भारत ने पहले खेलते हुए मैन ऑफ द मैच विराट कोहली के 120 रनों की बदौलत सात विकेट पर 279 रन बनाए थे जबकि मेजबान टीम 42 ओवर में 210 रनों पर ऑलआउट हो गई। बारिश के कारण वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस के आधार पर 46 ओवर में 270 रनों का लक्ष्य मिला था लेकिन भुवी की दमदार गेंदबाजी के सामने कैरेबियाई बल्लेबाजों का दम निकल गया। भारत ने इस जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पिछला मैच बारिश के कारण बिना रिजल्ट के समाप्त हुआ था जबकि आखिरी मुकाबला बुधवार को होगा।

भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर को घरेलू क्रिकेट में पहली बार शून्य पर आउट करके सुर्खियां बनने वाले भुवनेश्वर इस समय टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज हैं। मेरठ के प्रवीण कुमार से प्रेरणा लेकर स्विंग गेंदबाज बनने वाले दुबले-पतले भुवनेश्वर अब दुनिया के सॉलिड तेज गेंदबाज हो गए हैं। कभी कम गति के कारण बाद के ओवरों में असरदार नहीं रहने वाले भुवी ने अपनी गेंदबाजी में अहम बदलाव किए और यही कारण है कि उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच पर शानदार गेंदबाजी की और वेस्टइंडीज की पारी के 10वें ओवर में पहला विकेट चटकाया। क्रिस गेल उनकी गेंद को समझ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू हो गए। इसके बाद उन्होंने 42 रन पर खेल रहे निकोलस पूरन को चलता किया। तीन गेंद बाद भुवी ने रोस्टन चेज का अपनी ही गेंद पर कमाल का कैच लपककर उन्हें पवेलियन भेजा। फिर केमार रोच का विकेट लेकर उन्होंने अपने वनडे करियर में चौथी बार पारी में चार विकेट लिए। इसके अलावा कुलदीप यादव और मुहम्मद शमी ने दो-दो विकेट चटकाए। खलील को एक विकेट मिला। वेस्टइंडीज ने एक समय पर चार विकेट के नुकसान पर 148 रन बना लिए थे लेकिन उसके बाकी छह विकेट 62 रन पर ही गिर गए। वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा 65 रन इविन लुइस ने बनाए।

टीम इंडिया ने सीरीज में ली 1-0 की बढ़त, स्विंग और चपलता ने भुवी को बनाया टीम का सबसे भरोसेमंद गेंदबाज

सिर्फ शुरुआत का खेल नहीं : अमूमन यह माना जाता था कि भुवी को शुरुआती ओवरों में लगाओ और वह नई गेंद से शुरू के पांच-छह ओवरों में गेंद को स्विंग कराकर विकेट लेंगे लेकिन अब उन्होंने अपने दायरे को बढ़ा लिया है। 30 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला वनडे खेलने वाला यह तेज गेंदबाज अब गति, स्विंग और चपलता के मिश्रण से टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बन चुका है। भुवी के 113 मैचों में 34.24 के औसत से 132 विकेट हो गए हैं।

लगातार बदलाव से भरा दौर : अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत में भुवनेश्वर की जान स्विंग रहती थी। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें विशेष परिस्थिति का गेंदबाज कहा जाने लगा। सपाट पिचों पर स्विंग नहीं मिलने से वह साइड लाइन होते चले गए। 2015 विश्व कप के बाद उन्होंने अपनी काबिलियत को स्विंग की जंजीरों से बाहर निकालना शुरू किया और अपने शरीर पर काम किया। विश्व कप से पहले चोटिल होने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में हुए इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच यूएई के खिलाफ खेलने को मिला। विश्व कप के बाद भुवी ने अपना वजन बढ़ाया जिससे उनकी स्पीड 130-132 से बढ़कर 140 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई। 2016 और 2017 आइपीएल में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। अब भुवी शुरुआती ओवरों में स्विंग और आखिरी ओवरों में अपनी चपलता से विकेट लेना सीख गए हैं।

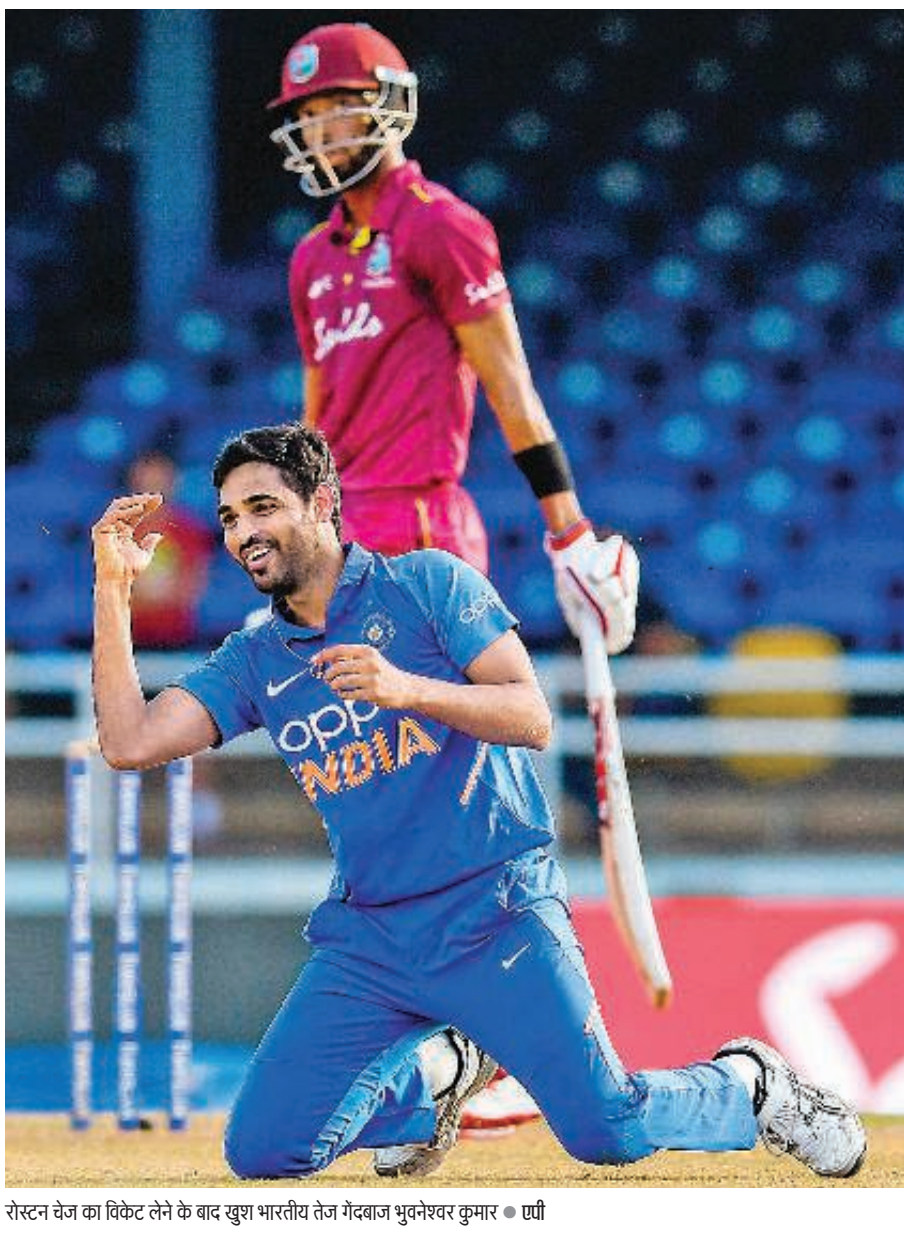

रोस्टन चेज का विकेट लेने के बाद खुश भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार • एपी

जब मन करता है नाच लेता हूं : विराट कोहली

पोर्ट ऑफ स्पेन, प्रेट्र : विराट कोहली नित दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर वह काफी सफल हैं और साथ ही एक इंसान के तौर पर वह अपने जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। खुद कोहली ने 'चहल टीवी' पर अपने साथी खिलाड़ी युजवेंद्रा सिंह चहल से यह बात कही। चहल ने कोहली का एक वीडियो इंटरव्यू शूट दिया है, जो बीसीसीआइ की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। चहल से बातचीत के दौरान कोहली ने कहा, 'मैं मैदान पर भरपूर आनंद ले रहा हूं। सिर्फ कप्तान होने के कारण मैं किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहता। हमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला है और इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जीवन का आनंद लें। हमें जब भी जहां भी संगीत बजे नाचना चाहिए और अपने विपक्षी साथियों को भी संग ले लेना चाहिए। मौजूदा समय में मैं काफी खुश हूं और यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है डांस करने से नहीं चूकता।'

कोहली ने दूसरे वनडे में 120 रनों की पारी खेली। कोहली ने इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड कायम किए। कोहली ने अपने वनडे करियर का 42वां शतक पूरा किया। कोहली ने आगे कहा, 'हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है कि शीर्ष तीन में से कोई एक बड़ा स्कोर करे। रोहित काफी समय से अच्छा कर रहे हैं। मुझे भी जब मौका मिला है, रन बनाए हैं। दुर्भाग्य से रोहित और धवन आज नहीं चल सके और इसी कारण मेरे लिए विकेट पर बने रहना जरूरी था।' यह पूछे जाने पर कि बल्लेबाजी या फिर फील्डिंग के दौरान क्या चीज उन्हें प्रेरित करती है? कोहली ने कहा, 'मेरा बहुत सरल माइंडसेट होता है। मैं टीम के लिए 100 फीसदी देना चाहता हूं। बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग या फिर कैच या फिर रन आउट, मैं अपना श्रेष्ठ देना चाहता हूं। इसके लिए अनुशासित जीवनशैली जरूरी है। अगर आप अपना 100 फीसद नहीं दे रहे हैं तो मेरी नजर में यह टीम के साथ नाइंसाफी है।'

विराट कोहली • एपी

अय्यर को चौथे स्थान पर चाहते हैं गावस्कर

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को वनडे टीम में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करानी चाहिए। अय्यर को इस क्रम पर नियमित बल्लेबाज के तौर पर स्थापित किया जाना चाहिए। अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 68 गेंदों पर 71 रन बनाए। रिषभ पंत मैच में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए थे जबकि अय्यर को पांचवें नंबर पर भेजा गया था। गावस्कर ने कहा कि मेरे मुताबिक पंत को महेंद्र सिंह धौनी की तरह पांचवें या छठे नंबर पर एक फिनिशर के रूप में भेजना चाहिए क्योंकि वहां उनका स्वाभाविक खेल निखकर सामने आएगा। अगर भारत को अच्छी शुरुआत मिलती है और विराट कोहली, शिखर धवन एवं रोहित शर्मा 40-45 ओवर तक टिक जाते हैं तो पंत को नंबर-4 आना चाहिए, लेकिन अगर 30-35 ओवर बल्लेबाजी करने का सवाल है तो मैं समझता हूं कि अय्यर को चार और फिर पंत को पांचवें नंबर पर भेजना चाहिए। अय्यर ने मौका का फायदा उठाया है। वह नंबर-5 पर आए और उनके पास काफी ओवर थे। उसे अपने कप्तान कोहली का साथ मिला। यह बढ़िया स्थिति होती है।

मेरे दिमाग में विकेट चटकाना नहीं था : भुवनेश्वर

पोर्ट ऑफ स्पेन : भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने मैच के बाद कहा कि दूसरे वनडे में उनके दिमाग में वेस्टइंडीज को रन बनाने से रोकना था, विकेट चटकाना नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि किफायती गेंदबाजी का फायदा हमेशा मिलता है। भुवनेश्वर ने मैच के बाद कहा, 'जब मैं गेंदबाजी के लिए आया तो सिर्फ इतना सोच रहा था कि मुझे किफायती गेंदबाजी करनी है, अधिक खाली गेंद फेंकनी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किफायती गेंदबाजी करोगे तो विकेट अपने आप मिलेंगे। मैं नतीजे के बारे में अधिक नहीं सोचता, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक-दो विकेट चटकाएंगे तो मैच में वापसी कर लेंगे।'

कोहली की तारीफ की : भारत ने कोहली की 125 गेंद पर 14 चौके और एक छक्के की मदद से 120 रन की पारी से सात विकेट पर 279 रन बनाए। यह वनडे में उनका 42वां शतक है। भुवनेश्वर ने कहा, 'आप विराट के हावभाव से देख सकते हैं कि उसे इस शतक की कितनी जरूरत थी इसलिए नहीं कि वह फॉर्म में नहीं थे बल्कि इसलिए, क्योंकि वह 70-80 रन के स्कोर पर आउट हो रहे थे और उन्हें हमेशा से बड़ी पारियां खेलने के लिए जाना जाता है।' कोहली ने अपना पिछला शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च में बनाया था। उन्होंने इसके बाद विश्व कप में पांच अर्धशतक लगाए लेकिन शतक बनाने में विफल रहे। भुवनेश्वर ने कहा, 'विकेट आसान नहीं था, जब विराट ड्रेसिंग रूम में लौटे तो उन्होंने कहा कि गेंद पुरानी होने के बाद रन बनाना आसान नहीं है। हम सीरीज में आगे हैं और इसे जीतना चाहते हैं। आप जब विदेश में खेल रहे होते हो तो सिर्फ सीरीज जीतना चाहते हो।'

चयनकर्ता बनना चाहते हैं सहवाग

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व भारतीय धुरंधर ओपनर वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव रहते हैं और अपने प्रशंसकों के लिए वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं। वह कभी-कभी सवाल भी पूछते हैं जिस पर उनके फॉलोअर्स जवाब देते हैं। उन्होंने रविवार को ट्विटर पर एक सवाल पूछा जिस पर कई लोगों ने जवाब दिए। सहवाग ने लिखा कि मुझे चयनकर्ता बनना है। कौन मुझे मौका देगा? इस पर कई लोगों ने जवाब दिए। एक यूजर ने लिखा, करण जौहर आपको मौका देंगे। सुप्रिया नाम की एक अन्य यूजर ने लिखा कि आप प्लीज चयनकर्ता बन जाओ। मनीष नाम के एक यूजर ने लिखा कि आप चयनकर्ता बनने के लिए नहीं हो। उसके लिए खराब खेलना पड़ता है।

जब सहवाग ने खुद को ही ट्रोल किया : सहवाग ने सोमवार को ट्विटर पर 2011 में आज ही के दिन हुई एक घटना के बारे में बताया और ऐसा करते हुए उन्होंने महान वैज्ञानिक आर्यभट को श्रद्धांजलि भी दी। आर्यभट ने ही शून्य की खोज की थी। भारत ने 2011 में इंग्लैंड का दौरा किया और इस सीरीज में मेजबान टीम ने 4-0 से क्लीन स्वीप किया था। बर्मिंघम में हुए तीसरे टेस्ट की दोनों पारियों में सहवाग बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए थे। पहली पारी में उन्हें स्टुअर्ट ब्रॉड ने जबकि दूसरी पारी में जेम्स एंडरसन ने आउट किया। इस घटना को याद करते हुए सहवाग ने ट्वीट किया कि आज के दिन आठ साल पहले, मैं बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ दो बार शून्य पर आउट हुआ था यह सब तब हुआ जब मैं दो दिन का सफर तय करने के बाद इंग्लैंड पहुंचा और फिर 188 ओवर फील्डिंग की। आर्यभट को श्रद्धांजलि। यदि असफल होने का प्रतिशत जीरो हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपने जान लिया है तो ऐसा करें।

एआइटीए ने की पाक में नए सिरे से सुरक्षा जांच की मांग

डेविस कप

- एआइटीए सचिव ने आइटीएफ से किया अनुरोध
- 14-15 सितंबर को इस्लामाबाद में होना है मुकाबला

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (एआइटीए) ने सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामाबाद में होने वाले डेविस कप मुकाबले का स्थान बदलने की मांग नहीं करने का फैसला किया, लेकिन ताजा राजनयिक तनाव के मद्देनजर वैश्विक संस्था आइटीएफ से नए सिरे से सुरक्षा जांच करवाने का अनुरोध किया है।

एशिया-ओसियाना जोन ग्रुप 1 डेविस कप मुकाबले 14 और 15 सितंबर को इस्लामाबाद में होने हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ राजनीतिक तनाव के चलते भारत का खेलना अनिश्चित माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध कम कर लिए हैं।

एआइटीए सचिव हिरण्यमय चटर्जी ने आइटीएफ के कार्यकारी निदेशक जस्टिन अलबर्ट को लिखे ईमेल में कहा, 'हमें पता है कि राजनयिक संबंध बिगड़ने से पहले आपने सुरक्षा जांच कराई थी। आइटीएफ अपनी संतुष्टि और संबंधित पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए एक और सुरक्षा जांच करा सकता है।' उन्होंने पहले कहा था कि एआइटीए यह मुकाबला तटस्थ स्थान पर कराने की मांग कर सकता है। उन्होंने हालांकि लिखा, 'एआइटीए सुरक्षा को लेकर आपकी आखिरी मंजूरी का इंतजार कर रहा है। टीम के आगमन से लेकर प्रस्थान तक का विस्तृत सुरक्षा कार्यक्रम का ब्यौरा चाहिए, ताकि हम खिलाड़ियों के वीजा के लिए आवेदन कर सकें।' एआइटीए ने कहा कि वह आइटीएफ के निर्देशों का पालन करेगा। चटर्जी ने कहा, 'अगर आइटीएफ पाकिस्तान टेनिस महासंघ से बात करने के बाद महसूस करता है कि सुरक्षा की 100 फीसदी गारंटी नहीं है तो वह आगे के लिए निर्देश दे सकता है। एआइटीए उसका अनुसरण करेगा।'

इससे पहले खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहकर मामले में दखल देने से इन्कार कर दिया था कि डेविस कप कोई द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं है। रिजिजू ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'अगर यह द्विपक्षीय खेल स्पर्धा होती तो क्या भारत पाकिस्तान के साथ खेलता, यह एक राजनीतिक फैसला हो जाता। लेकिन, डेविस कप द्विपक्षीय नहीं है और वैश्विक खेल संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। चूंकि भारत ओलंपिक चार्टर का हिस्सा है। इसलिए भारत के भाग लेने के फैसले पर भारत सरकार या राष्ट्रीय महासंघ कुछ नहीं कह सकते।'

मालूम हो कि भारतीय डेविस कप टीम ने 1964 से पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद से निष्क्रिय हैं। 2017 के बाद से पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अपने पांच घरेलू मुकाबलों में से चार की मेजबानी की है, जो कोरिया, थाइलैंड, उज्बेकिस्तान और ईरान के खिलाफ खेले गए। हांगकांग ने 2017 में वॉकओवर देते हुए पाकिस्तान की यात्रा करने से मना कर दिया था। आखिरी बार तब पाकिस्तान तटस्थ स्थान पर तब खेला था, जब उसने 2016 में कोलंबो में चीन की मेजबानी की थी।

दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ सकते हैं रहाणे

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली कैपिटल्स की टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रह चुके अजिंक्य रहाणे को अपने साथ जोड़ना चाहता है। इस संबंध में उनकी राजस्थान रॉयल्स के साथ बातचीत चल रही है। अगर दोनों फ्रेंचाइजी टीमों के बीच तालमेल बन जाता है तो आइपीएल के अगले सत्र में रहाणे दिल्ली के लिए खेलते नजर आएंगे।

सूत्रों ने कहा कि इस संबंध मे बताया कि दोनों फ्रेंचाइजी टीमों के बीच बातचीत जारी है और अगर सब कुछ मनमाफिक रहा तो फिर 2020 आइपीएल सत्र में रहाणे को दिल्ली के खिलाड़ी के रूप में मैदान में देखा जा सकता है। सूत्र ने कहा कि हां, दिल्ली कैपिटल्स रहाणे को अपने साथ जोड़ना चाहता है लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि यह करार मूर्त रूप ले ही लेगा। कई चीजों का ध्यान रखना होगा क्योंकि रहाणे सालों से राजस्थान टीम के लिए खेलते आएं हैं और एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। वैसे बातचीत जारी है। अगर करार को लेकर सहमति बनती है तो फिर दिल्ली की टीम को खुद को नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी।

भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीती अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज : भारत अंडर-19 टीम ने बांग्लादेश अंडर-19 टीम को छह विकेट से मात देते हुए त्रिकोणीय सीरीज अपने नाम कर ली है। बांग्लादेश अंडर-19 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत अंडर-19 टीम के सामने 262 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे भारत की युवा टीम ने 48.4 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा 73 रन कप्तान प्रियम गर्ग ने बनाए। उन्होंने 66 गेंदों का सामना कर चार चौके और दो छक्के लगाए। उनके अलावा ध्रुव जुरेल ने 59 नाबाद, दिव्यांश सक्सेना ने 55, यशस्वी जयसवाल ने 50 रनों का योगदान दिया।

नडाल ने जीता मांट्रियल मास्टर्स टूर्नामेंट

टेनिस डायरी

मांट्रियल, एएफपी : स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को सीधे सेटों में शिकस्त देकर मांट्रियल मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। विश्व के नंबर दो खिलाड़ी ने फाइनल में दमदार प्रदर्शन करते हुए सीधे सेटों में 6-3, 6-0 से जीत दर्ज की। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह एकतरफा मुकाबला केवल 70 मिनट तक चला।

पहले सेट में नडाल पहला गेम जीतकर 1-0 से आगे हो गए, लेकिन मेदवेदेव ने अगला गेम जीतकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद नडाल लगातार तीन गेम जीतकर 4-1 से आगे हो गए, लेकिन मेदवेदेव ने अगला गेम जीतकर स्कोर 4-2 कर दिया। फिर नडाल ने स्कोर 5-2 किया तो मेदवेदेव ने फिर से अगला गेम अपने नाम करके इस सेट में कुछ हद तक खुद को बनाए रखा। 5-3 के बाद नडाल ने इस सेट को 6-3 से जीतने में ज्यादा देर नहीं लगाई। दूसरे सेट में नडाल को रोक पाना मेदवेदेव के लिए काफी मुश्किल रहा। नडाल ने इस सेट में लगातार छह गेम जीतकर यह सेट 6-0 से जीता और खिताबी मैच अपने नाम किया।

नडाल ने कुल पांचवीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले अमेरिकी ओपन से पहले नडाल ने हार्ड कोर्ट पर सिर्फ तीन मुकाबले खेले हैं, जबकि वह मांट्रियल मास्टर्स का सेमीफाइनल मुकाबला भी नहीं खेल पाए थे क्योंकि चोटिल गाएल मोंफिल्स चोट के कारण इस मैच से हट गए थे। नडाल ने पहली बार क्ले कोर्ट से बाहर अपने किसी की खिताब का बचाव किया है। नडाल का पहली बार मेदवेदेव से सामना हुआ। मेदवेदेव का भी टूर्नामेंट में प्रदर्शन अच्छा रहा था और उन्होंने फाइनल को छोड़कर किसी भी मैच में कोई सेट नहीं गंवाया था।

सिनसिनाटी से हटे नडाल : यूएस ओपन की तैयारी करने के लिए नडाल ने सिनसिनाटी मास्टर्स से अपना नाम वापस ले लिया। नडाल ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस साल सिनसिनाटी में नहीं खेलूंगा। मैंने अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए और स्वस्थ्य रहने के लिए यह फैसला लिया है।'

05 वीं बार स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल ने मांट्रियल मास्टर्स का खिताब जीता

2019 से पहले नडाल ने मांट्रियल मास्टर्स की ट्रॉफी साल 2018, 2013, 2008 और 2005 में जीती थी

- खिताबी मुकाबले में रूस के मेदवेदेव को शिकस्त दी
- 70 मिनट तक चले मुकाबले को 6-3, 6-0 से जीता

राफेल नडाल

"मुझे अभी और सीखना है। मेदवेदेव बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन बाकी दिनों की तुलना में पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफी अच्छे रहे हैं। मेदवेदेव ने भी अच्छा टेनिस खेला। मैंने इस टूर्नामेंट में शानदार मैच खेले।
– राफेल नडाल

मैं शानदार टेनिस नहीं खेल सका। नडाल का प्रदर्शन बेहतरीन था। उन्हें खिताब के लिए बधाई। इस टूर्नामेंट में फाइनल को छोड़ दिया जाए तो सभी मैचों में मेरे खेल का स्तर काफी ऊंचा था।"
– डेनिल मेदवेदेव

35 वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब नडाल ने अपने नाम किया। वह विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविक से दो खिताब आगे हैं। जोकोविक ने 33वीं बार एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीते हैं

2019 साल में नडाल ने मांट्रियल के रूप में तीसरा खिताब जीता है। मांट्रियल से पहले वह रोम और फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके हैं

फिर नंबर एक बनीं ओसाका

पेरिस : जापान की महिला युवा टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने सोमवार को जारी डब्ल्यूटीए रैंकिंग में दोबारा पहला पायदान हासिल कर लिया। मांट्रियल मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को हार झेलने के बावजूद ओसाका ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी को हटाकर शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रही। बार्टी लगातार आठ सप्ताह के लिए विश्व की नंबर एक खिलाड़ी थीं। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने के बाद ओसाका लगातार 18 सप्ताह के लिए पहले पायदान पर मौजूद थीं। ओसाका अब तक कुल दो ग्रैंडस्लैम खिताब जीत चुकी है। दूसरे स्थान पर बार्टी हैं तो तीसरे पर कैरोलिना प्लिस्कोवा हैं। सेरेना विलियम्स दो स्थान की छलांग लगाकर आठवें पर पहुंच गईं।

सेरेना हटीं, एंड्रीस्क्यू ने रचा इतिहास

मॉन्ट्रियल : अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने चोट के कारण मांट्रियल मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में कनाडा की बिनाका एंड्रीस्क्यू के खिलाफ मैच को बीच में छोड़ दिया, जिससे एंड्रीस्क्यू यह खिताब जीतने में सफल हो गईं। महिला सिंगल्स के फाइनल में सेरेना के रिटायर होने के समय पहले सेट में कनाडाई खिलाड़ी 3-1 से आगे चल रही थीं, लेकिन सेरेना ने कमर में दर्द के कारण मैच से हटने का फैसला ले लिया। 19 साल की बिनाका 50 साल में इस टूर्नामेंट को जीतने वाली कनाडा की पहली खिलाड़ी बन गईं।

मैच जीतने के बाद एंड्रीस्क्यू ने अगले टूर्नामेंट सिनसिनाटी मास्टर्स से हटने का फैसला ले लिया। एंड्रीस्क्यू ने कहा, 'मैं सिनसिनाटी से नाम वापस लेकर दुखी हूं। मैं अभी अपने शरीर पर ध्यान दे रही हूं। पिछला सप्ताह मेरे लिए आसान नहीं रहा है।' वहीं, 37 वर्षीय सेरेना ने कहा कि वह सिनसिनाटी में खेलने का फैसला जल्द ही करेंगी। उन्होंने कहा, 'मेरे करियर में ज्यादातर कमर में दर्द रहा और यह निराशाजनक है। मैं इसका अलग तरह से उपचार करा रही हूं। सिनसिनाटी पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है।'

50 साल में मांट्रियल टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली कनाडा की पहली खिलाड़ी बन गईं बिनाका एंड्रीस्क्यू

साक्षात्कार

हेडली और बांड के सामने मैं बच्चा : बोल्ट

स्विंग के मास्टर और रफ्तार के जादूगर ट्रेंट बोल्ट ने इंग्लैंड में हुए विश्व कप में भारत ही नहीं बल्कि सभी टीमों की हालत खराब कर दी थी। विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वह भले ही विकेट नहीं ले सके हों लेकिन उन्होंने क्रिकेट के महाकुंभ में 17 विकेट चटकाए थे। न्यूजीलैंड की टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है जहां पर उसे बुधवार से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। अब देखना यह होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की पिच पर वह कैसा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि अपने देश के दो दिग्गज गेंदबाजों सर रिचर्ड हेडली और शेन बांड से तुलना पर वह खुद को बच्चा बताते हैं। **ट्रेंट बोल्ट से अभिषेक त्रिपाठी** ने खास बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश :

- **आपको स्विंग का मास्टर कहा जाता है। आप इतनी स्विंग कैसे करा लेते हैं। इसके बारे कुछ बताएं?**

-यह हालात पर निर्भर करता है। स्विंग गेंदबाजों में रिचर्ड हेडली, डेनी मॉरिसन, शेन बांड दिग्गज हैं और मैं उनके सामने बच्चा हूं। गेंदबाजी के दौरान अगर पिच पर अगर घास होती है तो उसकी मदद लेता हूं। हम इस तरह की पिचों पर न्यूजीलैंड में खेले हैं और इससे स्विंग गेंदबाजी करने में मदद मिलती है। न्यूजीलैंड में गेंदबाजों की मददगार पिच होती हैं। वसीम अकरम और डेल स्टेन भी इन पिचों पर गेंद को अच्छी तरह से मूव करा लेते थे।

- **श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज मलिंगा अब टेस्ट और वनडे से संन्यास ले चुके हैं। आपने उनके साथ काफी खेला है। क्या इस सीरीज में उनकी कमी खलेगी?**

-वह विशेष गेंदबाज हैं। उनका गेंदबाजी करने का अलग तरह का स्टाइल है। उनका लंबा करियर रहा है और उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखना अच्छा लगता है। वह अपने करियर में सफल रहे और दुनिया भर की ज्यादातर लीग में खेले। कुछ स्पैल उनके दमदार रहे। मुझे विश्वास है कि दुनिया भर में उनके प्रशंसक उन्हें याद करेंगे।

- **न्यूजीलैंड की टीम ने विश्व कप में खेल भावना दिखाई थी। आप वहां अपनी टीम के प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे?**

-हमारी टीम के सभी साथियों ने विश्व कप में व्यक्तिगत तौर पर अपना अच्छा प्रदर्शन किया। वहां के हालातों से तालमेल बैठाया। हम खेल भावना के साथ खेले। हमने वहां पर अपना स्वाभाविक खेल खेला। विश्व कप में अभियान थोड़ा भावुक हो गया था लेकिन हम टूर्नामेंट में विरोधी टीम को देखकर खेले थे। हमने विश्व कप में खूब आनंद लिया। हमें ऐसा लगता था कि हम टूर्नामेंट को जीत के साथ खत्म कर सकते थे। फाइनल में अजीबो-गरीब तरह से हारने से हमारी टीम के सभी साथी भावुक थे। सच कहूं तो लॉर्ड्स में विचित्र हालात हो गए थे। आज भी वह याद आता है।

- **विश्व टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो गई है और इसे आप कैसे देखते हैं? श्रीलंका में स्पिनरों की मददगार पिचें हैं और ऐसी चुनौतियों से निपटना आपके लिए कितना मुश्किल होगा?**

-विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत यह हमारा पहला टेस्ट मैच होगा और हम इसको लेकर उत्साहित हैं। कई सत्रों में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। यह एक चुनौती है। मैंने महसूस किया है कि मुझे स्पैल टू स्पैल गेंदबाजी करने की जरूरत है। हम एक इकाई के रूप में गेंदबाजी करेंगे। हमने पिछले कुछ समय में अच्छा क्रिकेट खेला है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही होगा। हम हर कीमत पर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे।

टेस्ट मैच	बुधवार सुबह 10:00 बजे से
न्यूजीलैंड vs श्रीलंका	स्थान : गॉल, श्रीलंका
	प्रसारण : सोनी नेटवर्क

भारत ने दिव्यांग क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया

नई दिल्ली, जेएनएन : भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने सोमवार को इंग्लैंड में विश्व चैंपियनशिप मुकाबले में पाकिस्तान को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारतीय टीम फाइनल में भी पहुंच गई। भारतीय टीम ने रविवार को ही इस टूर्नामेंट के एक अहम मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को हार का स्वाद चखाया था।

सोमवार को पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 150 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए हमीद ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। भारत के लिए केनी ने सबसे ज्यादा दो विकेट लिए।

जवाब में भारतीय टीम ने 17.1 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत के लिए डब्ल्यूआइ खान ने 69 और केडी फनासे ने 55 रन बनाए।

23 फीसद भूजल संग्रहण होता है उत्तराखंड के कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में मौजूद बांज के पेड़ों की वजह से। जबकि यहां 80 फीसद चीड़ के पेड़ मौजद हैं और मात्र तीन फीसद से कम बांज के पेड़ हैं।

गंदे नाले में बदल चुकी नदी को बना दिया आस्था का केंद्र

हौसला ▶ उपेक्षा का शिकार रही दुर्दशाग्रस्त नदी महज दो साल में बन गई श्रद्धा का विषय, नदी को बचाने की मिसाल बना संजय का संघर्ष

संदीप दीवान, भिलाई

स्वतंत्रता के सारथी जल प्रहरी

- छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से शुरू हुए शिवनाथ बचाओ आंदोलन में आज हर खास-ओ-आम शामिल
- आम से लेकर अधिकारी और न्यायाधीश तक, सब गा रहे शिवनाथ मैया की आरती

जनप्रेरणा का माध्यम बन गई है पूर्णिमा को होने वाली शिवनाथ नदी की महाआरती। नईदुनिया

हमने एक उपेक्षित और दुर्दशाग्रस्त नदी को जन आस्था का केंद्र बनाकर इसके संरक्षण के लिए शासन-प्रशासन और सरकारों को सोचने पर विवश कर दिया। नाले में तब्दील हो चुकी शिवनाथ नदी की आज लोग आरती उतार रहे हैं। लेकिन नदियों में मिलने वाले गंदे नालों का इलाज जनता नहीं बल्कि सरकार को ही करना है। छत्तीसगढ़ की दुर्दशाग्रस्त अन्य नदियों के संरक्षण को भी अभियान छेड़ा गया है, बस्तर की इंद्रावती नही, बिलासपुर की अरपा नदी के लिए स्थानीय लोगों को जोड़ प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

-संजय मिश्रा, संयोजक, शिवनाथ बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री रवींद्र चौबे (बाएं) को शिवनाथ नदी के संरक्षण के लिए ज्ञापन सौंपते संजय कुमार मिश्रा। नईदुनिया

शिवनाथ नदी की सफाई में जुटे संजय कुमार मिश्रा (दाएं से दूसरे) और शिवनाथ सेवा मंडल के सदस्य। नईदुनिया

श्रद्धा सहित गाते हैं।

शिवनाथ बचाओ आंदोलन के समन्वयक संजय कुमार मिश्रा बताते हैं, नदियां हमारी जीवनधारा हैं, हमारी धरोहर हैं, यदि इन्हें बचाने के लिए हम अब भी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों को एक भयावह भविष्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं दे सकेंगे। अपनी नदी को हम नहीं बचाएंगे तो यह काम कोई और क्यों करेगा। इसीलिए हमने आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत की ताकि जन-जन की भागीदारी बढ़ाते चलें। खुशी है कि आज हर व्यक्ति की जीवनचर्या जीवनदायिनी शिवनाथ के जल से ही शुरू होती है। अब इस आंदोलन से हर कोई जुड़ना चाहता है, कारवां बढ़ता जा रहा है। जनता की आस्था के आगे अब शासन-प्रशासन से लेकर सरकारों तक पर दबाव बन रहा है।

संजय ने बताया, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हुए मैंने प्रदूषण के कारकों को करीब से देखा। रसायन विज्ञान में एमएससी हूं, इसलिए समझ सका कि तमाम रसायनों का प्रकृति पर कितना घातक असर हो रहा है। फार्मास्यूटिकल का बिजनेस छोड़कर प्रकृति की ओर रुख करना बेहतर जाना। अपनी जरूरतें बेहद सीमित कर लीं। परिवार की जीविका को पारिवारिक कृषि व्यवसाय के हवाले कर समाजसेवा की राह पकड़ ली। लोगों ने फैसले पर सवाल उठाए, पर मैंने जिद पकड़ ली थी। राष्ट्रीय संस्था जनसुनवाई फाउंडेशन के साथ जुड़कर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण वंचित समुदायों की मदद और प्राकृतिक संसाधनों की हिफाजत के बड़े काम में सहभागी बना। शिवनाथ बचाओ आंदोलन की नींव 2017 में तब पड़ी, जब जनसुनवाई फाउंडेशन ने दुर्ग जिले के झेंझरी गांव में जनपंचायत कार्यक्रम किया। गांव वालों ने बताया कि नदी के पानी के स्पर्श मात्र से उन्हें घातक रोग हो रहे हैं। पशु मर रहे हैं। कृषि तबाह हो गई है। शहरों के तमाम बड़े नालों को नदी में छोड़ा जा रहा था। हमने नदी की दुर्दशा को देखते हुए आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन आम लोगों को नदी से कोई सरोकार शेष नहीं रह गया था। वे उम्मीद छोड़ चुके थे। लिहाजा, लोगों को नदी से जोड़ने के लिए हर पूर्णिमा को शिवनाथ महाआरती की पहल की गई। इसके बाद, गंदे नालों को डायवर्ट करने और उद्योगों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने सरकार को पत्र लिखकर मांग करने का सिलसिला शुरू हुआ। आरटीआइ लगा लगा कर नदी प्रदूषण के कारकों और नदी स्वास्थ्य की रिपोर्ट हासिल की गई। राज्य के जल संसाधन मंत्री को यह सारे दस्तावेज सौंप कर नदी के संवर्धन की मांग की गई।

प्रयास तब रंग लाते दिखा जब शिवनाथ नदी को बचाने के इस आंदोलन में जिला न्यायाधीश गोविंद कुमार मिश्रा सहित जिला न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने आरती में सहभाग शुरू किया। आज महज दो साल के भीतर शिवनाथ नदी को बचाने की मुहिम में हजारों लोग जुड़ गए हैं।

श्रावण पूर्णिमा दो दिन, रक्षाबंधन 15 को

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सनातन मतावलंबियों के प्रमुख त्योहारों में रक्षा पर्व रक्षा बंधन का विशिष्ट स्थान है। इसे सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा इस बार दो दिन यानी 14 व 15 अगस्त को पड़ रही है। पहले दिन 14 अगस्त को व्रत की पूर्णिमा और दूसरे दिन 15 अगस्त को रक्षा बंधन मनाया जाएगा। इस दिन ही पूर्णिमा का स्नान-दान होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी के अनुसार, रक्षा बंधन में पराह्णव्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि पूर्णिमा दो दिन हो या उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग करना चाहिए। भद्रा में रक्षा पर्व व फागुनी दोनों ही वर्जित है। श्रावणी में राजा व फागुनी में प्रजा का अनिष्ट होता है।

पूर्णिमा तिथि 14 अगस्त को दिन में ही 2.45 बजे लग रही है जो 15 अगस्त को शाम 4.30 बजे तक रहेगी। 15 अगस्त को सुबह से लेकर शाम 4.23 बजे तक बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। वहीं श्रावण पूर्णिमा पर ब्राह्मणों द्वारा ऋषि तर्पण क्रिया उपाकर्म किया जाता है। पंद्रह अगस्त को ही संस्कृत दिवस व स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा।

रक्षाबंधन की कथा : सतयुग में एक बार देवता और दानवों में 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। देवता बार-बार हारते चले गए। देव गुरु वृहस्पति की आज्ञा से युद्ध रोक दिया गया। देव गुरु के आदेश पर इंद्राणियों ने इंद्र को रक्षा बंधन किया। रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र ने दानवों का संहार किया और देवताओं को विजय मिली। यह तिथि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा थी। तभी से सनातन परंपरा में रक्षा बंधन मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को और ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांध कर एक वर्ष के लिए सुरक्षित कर देते हैं।

रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र

''येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः।
तेनत्वां बद्धनामि रक्षे माचल माचल।।''

गोलियां झेलकर भी 18 घंटे तक मोर्चा संभाले रहे राठौर

- 35 एनकाउंटर और आधा दर्जन नक्सल कमांडरों को मार गिराने वाले जांबाज पुलिस अफसर
- 15 अगस्त को वीरता पदक से नवाजे जाएंगे छत्तीसगढ़ के सुपरकॉप प्रकाश राठौर

छत्तीसगढ़ पुलिस के सुपरकॉप प्रकाश राठौर। नईदुनिया

विकास पांडेय, कोरबा

इस सुपरकॉप का नाम सुन नक्सलगढ़ के दहशतगर्द भी दहशतजदा हो जाते हैं। 35 एनकाउंटर और आधा दर्जन नक्सली कमांडरों को मार गिराने वाले जांबाज पुलिस अफसर प्रकाश राठौर को 15 अगस्त को वीरता पदक प्रदान किया जाएगा।

इस जांबाज पुलिस अफसर ने तब बेमिसाल शौर्य का परिचय दिया, जब कंधे में धंसी गोली की परवाह किए बिना पूरे 18 घंटों तक नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। नक्सलियों ने चारों ओर से घेर रखा था। जख्म की परवाह किए बगैर वे टीम का हौसला बढ़ाते हुए मोर्चे पर दीवार बनकर डटे रहे। सुकमा में कई दुर्दांत नक्सली कमांडरों को मौत के घाट उतारने वाले कोरबा के इस शूरवीर को पुलिस गैलेंट्री अवार्ड घोषित हुआ है। उन्हें राष्ट्रपति की ओर से प्रदत्त यह पुलिस वीरता पदक आगामी स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर में राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाएगा।

ढेर सारे नक्सल ऑपरेशन में अपनी हिम्मत का लोहा मनवा चुके प्रकाश की पहचान एक ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की है, जो कभी हार नहीं मानता। 2017 में 18 घंटे तक चला किस्टाराम थाना क्षेत्र के पोटकपल्ली में किया गया ऑपरेशन चर्चा में रहा। 16 जवानों का नेतृत्व करते हुए वे 150 कोबरा कमांडो के साथ पांच दिन के ऑपरेशन पर थे। दो दिन सर्चिंग के बाद तीसरे दिन नक्सलियों की पूरी बटालियन ने हमला कर दिया। 15 जवान घायल तो तीन कोबरा कमांडो शहीद हो गए। सुबह 10 बजे शुरू हुई मुठभेड़ के बीच दोपहर करीब तीन बजे उन्हें कंधे पर गोली लगी, लेकिन रात गुजर गई और सुबह हो गई, पर वे डटे रहे। अपनी जान पर खेलकर साथियों की ढाल बने रहे। तीन भाई-बहनों में प्रकाश सबसे छोटे हैं।

खत्म की भास्कर-जोगी की दहशत : इंस्पेक्टर प्रकाश राठौर को यह गैलेंट्री अवार्ड वर्ष 2016-17 के लिए मिलने जा रहा है। उन्होंने कोबरा कमांडो के साथ मिलकर दो ऐसे नक्सली कमांडरों भास्कर और महिला कमांडर जोगी को मार गिराया था, जिनके नाम से भेज्जी और कोंटा क्षेत्र में काफी दहशत थी।

जय हिंद
ताकत वतन की हमसे है...

आउट ऑफ टर्न प्रमोशन

एक साल पहले तबादले पर आए प्रकाश वर्तमान में बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना प्रभारी हैं। सीएसईबी के रिटायर्ड कर्मी मनहरणप्रसाद राठौर और स्व. धनबाई राठौर के पुत्र प्रकाश ने वर्ष 2003 में सशिमं सीएसईबी पूर्व से 12वीं तक पढ़ाई की और 2005-06 में शासकीय पीजी कॉलेज से बी-कॉम किया। इसके बाद वे आरक्षक बने और वर्ष 2012 में एसआइ परीक्षा देकर उपनिरीक्षक बने। वर्ष 2016 में उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला।

रात के अंधेरे में वह सींखचे काटते और ऊपर डामर चिपका देते

आशुतोष मिश्र, लखनऊ

कहानी-6

जय हिंद
मातृवेदी के बलिदानी

- शिवकृष्ण अग्रवाल को जमींदारी न आई थी रास, मातृभूमि को दासता से मुक्त कराने के लिए बने क्रांतिकारी
- कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर वह जेल काटकर निकले और अंग्रेज माथा पीटते रह गए
- शोधार्थी शाह आलम की किताब मातृवेदी : बागियों की अमर गाथा से शृंखला की अगली कहानी

मातृवेदी के बलिदानियों में एक नाम ऐसा भी है, जिसे जमींदारी का ऐश्वर्य रास न आया। मातृभूमि को दासता की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए शिवकृष्ण अग्रवाल ठाठ-बाट को त्याग क्रांतिकारी बन गए। मैनपुरी योजना (12 जिलों के डीएम और एसपी की हत्या की तैयारी) का राजफाश होने के बाद जारी छापेमारी के दौरान अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जंग-ए-आजादी के इस दीवाने के आगे जेल भी हार गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर वह जेल काटकर निकले तो फिर अंग्रेज बस माथा पीटते ही रह गए।

मातृभूमि के इस लाडले ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर बरनाहल कस्बे में जन्म लिया था। पिता भगवान दास वैश्य इलाके के जमींदार थे। मैनपुरी मिशन स्कूल में पढ़ाई के दौरान शिवकृष्ण अग्रवाल मातृवेदी के सिपाही बन गए। तेज दिमाग के चलते वह अपने ब्रांच के नेता बने। उन्हें दल के सदस्य कलक्टर कहकर पुकारते थे। क्रांतिकारी दम्मीलाल पांडेय और उनके शांति भवन पुस्तकालय के प्रभाव में युवा तेजी से मातृवेदी संगठन की ओर आकर्षित हो रहे थे। ऐसे में उन दिनों मैनपुरी मिशन स्कूल अंग्रेजों के रडार पर था। इसी कड़ी में एक गुप्तचर वहां संन्यासी के भेष में पहुंचा। शक होने पर युवाओं ने उसे जमकर पीटा। जयपुर के सीआइडी अधिकारी श्रीपद बनर्जी ने इसकी रिपोर्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट को दी। इस पर तत्काल छापेमारी हुई। तलाशी में शिवकृष्ण अग्रवाल के पास से एक पत्र मिला। इस पर क्लोरोफार्म बनाने का फार्मूला लिखा था। उन्हें रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके मैनपुरी जेल भेज दिया गया। उनके साथ कुछ और क्रांतिवीर गिरफ्तार किए गए थे। दूसरे दिन श्रीपद बनर्जी आया और क्रांतिकारियों पर जुल्म ढाने का आदेश दिया। नारकीय यातना की इंतहा करते हुए अंग्रेजों ने 10 माह बाद क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। इधर, मातृवेदी के कमांडर इन चीफ गेंदालाल दीक्षित हवालात से फरार हो चुके थे। ऐसे में क्रांतिकारियों ने मंसूबा बनाया कि अगर शिवकृष्ण अग्रवाल भी जेल से निकल भागें तो केस कमजोर हो जाएगा। मुकदमा शुरू हुआ तो शिवकृष्ण अग्रवाल ने भतीजे से आरी और डामर मंगाया। रात के अंधेरे में वह सींखचे काटते और ऊपर से डामर चिपका देते। तीसरी रात को बरसात के बीच वह काल कोठरी के सींखचे काटकर फरार हो गए। योजना के मुताबिक शिवकृष्ण के बड़े भाई हरिकृष्ण क्रांतिकारी साथियों के साथ जेल की दीवार के पास हथियार लेकर डटे थे। शिवकृष्ण जेल से निकल सकें, इसके लिए दीवार से सटाकर ऊंट खड़ा किया गया था। क्रांतिकारियों ने उन्हें शिकोहाबाद के किशन मुरारी कपड़े वाले के पास पहुंचाया। इसके बाद शिवकृष्ण का किसी को पता नहीं चला।

प्रतीकात्मक चित्रण

बैरक को संरक्षित करने की मांग : मातृवेदी के सिपाहियों की जानकारी जुटाते हुए लघु फिल्म निर्माता शाह आलम बरनाहल पहुंचे। यहां हरिकृष्ण के बड़े पौत्र बड़कन अग्रवाल के साथ उन्होंने शिवकृष्ण की उस पैतृक हवेली के अवशेष देखे, जिसमें क्रांतिकारी किसी घटना को अंजाम देने के बाद भूमिगत हो जाते थे। इसके साथ ही उन्होंने मैनपुरी जेल अधीक्षक से मिलकर उन सभी बैरक को संरक्षित करने की मांग की, जिसमें शिवकृष्ण अग्रवाल और मातृवेदी के अन्य क्रांतिकारी कैद रखे गए थे।

कारागार में जन्मे कान्हा की पोशाक सिलेंगे बंदी

योगेश जादौन, मथुरा

- दान में मिल चुकीं आधा दर्जन सिलाई मशीनें, स्वयंसेवी संस्थाएं देंगी कपड़ा

कंस की कारागार में जन्मे कान्हा की पोशाक भी अब जिला कारागार के बंदी तैयार करेंगे। जेल प्रशासन को इसके लिए सिलाई मशीनें मिल चुकी हैं, कपड़ा आदि मैटेरियल भी स्वयंसेवी संस्थाएं मुहैया करा देंगी। भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्योत्सव पर कारागार में ये कार्य शुरू हो जाएगा।

सजायाफ्ता होने के बाद बाहर आते ही लोगों के सामने समाज में खुद को स्थापित करना एक संकट बन जाता है। रोजी-रोटी के लिए कामकाज भी नहीं मिल पाता है। कोई उनको काम पर भी नहीं रखता है। बैंक भी ऋण नहीं देती है। बंदियों को रिहा होने के बाद इस जद्दोजहद का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला कारागार में बंदियों को ठाकुरजी की पोशाक बनाने का कार्य सिखाया जाएगा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर एक यूनिट की शुरुआत होने जा रही है। खजानी वूमेंस पॉलिटेक्निक की डायरेक्टर शिप्रा राठी ने आधा दर्जन सिलाई मशीनें भी उपलब्ध करा दी हैं। जेल अधीक्षक शैलेंद्र मैत्रेय बताते हैं कि एनजीओ के माध्यम से बंदियों को पोशाक तैयार करने का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। संस्थाओं से ही पोशाक का कपड़ा और सिलाई की सामग्री ली जाएगी। कारागार में पोशाक तैयार करके संबंधित संस्था को उपलब्ध करा दी जाएंगी। इससे होने वाली आय को बंदी कल्याण कोष में जमा कराया जाएगा। जेल से रिहा होने के बाद संबंधित बंदी को उसके हिस्से की धनराशि दे दी जाएगी।

स्कूल ड्रेस भी करेंगे तैयार: ठाकुरजी की पोशाक के साथ ही बंदियों को स्कूल ड्रेस बनाना भी सिखाया जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए बड़ी-बड़ी शैक्षणिक संस्थाओं से संपर्क किया है।

सस्ते में शुरू हो जाएगा खुद का रोजगार

जेल से बंदी के रिहा होने के बाद उसे रोजगार के लिए सहूलियत मिलेगी। किसी टेलर के यहां काम कर सकता है, या फिर दो चार हजार रुपये में अपना खुद का काम भी शुरू कर सकता है। उसको सिलाई मशीन और कुछ सामान की ही जरूरत पड़ेगी।

संकटग्रस्त बांज की तीन प्रजातियों का होगा संरक्षण

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : पहाड़ का हरा सोना यानी बांज अब विलुप्ति के कगार पर है। यूं तो बांज की सभी छह तरह की प्रजातियां खतरे में हैं, लेकिन सबसे अधिक तीन प्रजातियां रयांस, फ्यांठ और मोरू पर संकट है। वन विभाग के सामने बांज की इन तीन प्रजातियों को बचाने की चुनौती है।

पर्यावरणविदों के अनुसार बांज प्रजातियां रयांस, फ्यांठ व मोरू के बीज जंगल में कुदरतन नहीं उग रहे हैं। वन अनुसंधान केंद्र के रेंजर मदन बिष्ट के अनुसार पहले जंगलों में बांज के पेड़ अधिक दिखते थे। यही वजह थी कि धरती में नमी बनी रहती थी। स्रोतों से पानी भी निकलता था, लेकिन अब जंगलों में बांज की संख्या बहुत कम हो गई है। अब बांज की इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए नर्सरी तैयार की जा रही है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद अलग-अलग जगहों पर रोपे जाएंगे।

पर्यावरणविद चंदन नयाल ने बांज की प्रजातियों को बचाने के लिए ग्रामीणों के साथ मिलकर ओखलकांडा के देवगुरु जंगल को संरक्षित करने की पहल की है। बांज की मोरू प्रजाति पांच हजार फीट की ऊंचाई पर मिलती है। रयांस व अन्य प्रजातियां 1200 से 3500 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं।

उत्तराखंड की रंगत निखारेगा जम्मू-कश्मीर का चिनार

केदार दत्त, देहरादून

- कश्मीर के भांति अब उत्तराखंड में चिनार की रंगत से अभिभूत होंगे सैलानी
- अल्मोड़ा के रानीखेत में माल रोड पर वन अनुसंधान शाखा ने लगाए चिनार के 200 पौधे

'चिनार के दरख्त से...कभी हरे पत्तों की ताजगी लिए, फिर कभी उदास हो पीले रंग में रंग जाती हूं, फिर धीरे से पीले रंग में पगी हुई बैंजनी सी रक्तिमा ओढ़ लेती हूं।' कश्मीर के लोकरंगों में रचे-बसे चिनार के पेड़ों की रंगत बयां करने को अनाम कवि की ये पंक्तियां काफी हैं। पत्तियों के रंग बदलने के गुण के कारण यह सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। अब कश्मीर की भांति उत्तराखंड में भी चिनार की रंगत से पर्यटक अभिभूत होंगे। वन महकमे की अनुसंधान शाखा ने राज्य में ही इसकी पौध तैयार कर छावनी क्षेत्र रानीखेत में 200 पौधे लगाए हैं। प्रयोग सफल रहा तो दो साल बाद राज्य के अन्य पर्यटक स्थलों में भी कश्मीर की यह मिल्कियत रोपी जाएगी।

उत्तराखंड में बुरांस, बांज व काफल के पेड़ जिस तरह से यहां की लोक संस्कृति में गहरे तक रचे-बसे हैं, ठीक उसी तरह चिनार भी कश्मीरी लोक रंगों में समाया हुआ है। कश्मीर में चिनार (प्लेंटनस ओरिएंटलिस) के दरख्त वहां सैर को पहुंचने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जम्मू-कश्मीर का राज्यवृक्ष चिनार वहां की एक बड़ी पहचान में शुमार है। यूं कहें कि पर्यटन को बढ़ावा देने में इसकी भी भूमिका है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

चिनार के खूबसूरत पेड़ों और पतझड़ के वक्त रंग बदलने वाली इसकी पत्तियों के प्रति सैलानियों के आकर्षण को देखते हुए वन महकमे ने उत्तराखंड में भी इसे पनपाने की ठानी। वन संरक्षक अनुसंधान वृत्त संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक उत्तराखंड में नैनीताल में माल रोड व राजभवन क्षेत्र में सीमित दायरे में चिनार के पेड़ हैं। ये पेड़ 1890 में अंग्रेजों ने जम्मू-कश्मीर से लाकर लगाए थे। ये दरख्त भी नैनीताल आने वाले सैलानियों का ध्यान खींचते हैं।

प्रतीकात्मक

आइएफएस चतुर्वेदी बताते हैं कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी चिनार के पेड़ अस्तित्व में आएं, इसके लिए मार्च 2017 में पहल की गई। इस कड़ी में रानीखेत क्षेत्र की द्वारसौं नर्सरी में वानस्पतिक वर्धन (कलम) के जरिये पौधे तैयार करने का निर्णय लिया गया। पहल रंग लाई और वहां चिनार के 200 स्वस्थ पौधे तैयार हुए। अब एक से 10 अगस्त तक इन पौधों का रोपण छावनी क्षेत्र रानीखेत में माल रोड पर किया गया।

पर्यटक स्थलों में भी रोपेंगे चिनार : आइएफएस चतुर्वेदी के अनुसार दो साल तक रानीखेत में लगाए गए पौधों की देखभाल होगी। प्रयोग सफल रहने पर मसूरी, धनोल्टी, अल्मोड़ा, मुनस्यारी समेत अन्य पर्यटक स्थलों के साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों पर भी चिनार के पौधों का रोपण किया जाएगा। इनके दरख्त बनने पर यहां भी सैलानी कश्मीर की तरह चिनार के पेड़ों की रंगत का लुत्फ उठा सकेंगे।

जज्बा

आदिवासी पुरुषों और महिलाओं को जागरूक करने के लिए करती हैं दिन-रात एक, बारिश के दिनों में जंगल वाले गावों में बितानी पड़ती है रात

आदिवासियों को बीमारियों से बचाने को रोज करतीं 32 किमी का सफर

गुनेश्वर सहारे, बालाघाट

अडोरी गांव की 52 वर्षीय आदिवासी महिला राया परते को न तो वन्यप्राणियों का डर है और न ही नक्सलियों का। वह सुबह से पैदल जंगल वाले गांवों में बैगाओं को शासकीय योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाने निकल पड़ती हैं। इसके लिए रोजाना वह करीब 32 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। बारिश के दिनों में कई बार जंगल वाले गांवों में रात बितानी पड़ती है। उनके प्रयास का असर भी हुआ है। बैगा आदिवासी अस्पताल तक इलाज कराने पहुंच रहे हैं। एक दशक में एक दर्जन से अधिक नक्सल प्रभावित गांवों में बीमारी से मौत का आंकड़ा कम हुआ है।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला मुख्यालय से करीब 98 किलोमीटर दूर जनपद पंचायत बिरसा के अडोरी गांव की निवासी राया परते पति नसीब परते ने बताया कि वे प्रतिदिन अडोरी सहित आसपास के नक्सल प्रभावित गांवों में जाकर बैगा आदिवासी महिला, पुरुष, बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेती हैं। यदि किसी को बीमारी है तो उन्हें शासकीय अस्पताल पहुंचकर इलाज कराने के लिए कहती हैं। जो अस्पताल जाने तैयार नहीं रहते उनके लिए एंबुलेंस बुलाकर इलाज कराया जाता है। राया परते बताती हैं कि 15 साल पहले अडोरी में पांच बैगा आदिवासियों की बुखार के दौरान इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई थी। बैगा आदिवासी अस्पताल जाने से डरते थे। वे समझते थे कि अस्पताल में इलाज के पैसे लगते हैं। इसके बाद से उन्होंने संकल्प लिया कि सभी बैगा आदिवासियों को सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देकर समय पर इलाज होने से उनकी जान बचाई जा सकती है। इसीलिए गांव-गांव में जाकर जाकर यह प्रयास शुरू किया और कई लोगों को अस्पताल तक ले आईं। राया परते के कार्यों को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2008-2009 में उन्हें आशा सहयोगिनी का पद सौंप दिया।

बैगा महिलाओं को जानकारी देने के बाद जाती हुईं राया परते। नईदुनिया

एक गांव में तीन घंटे का देती हैं समय: राया परते बैगा आदिवासी ग्राम घुम्मुर, मुरकुटा, परसाई, कोड बिरकोना, चिखली, मालिया, रजना, महुआपानी, कोमो, कुंडेकसा, बोंदारी, उर्सेकाल समेत अन्य गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देने पहुंचती हैं। ये पूरे ग्राम नक्सल प्रभावित हैं। चाहे फिर गर्मी, ठंड हो या फिर बारिश के दिन अकेली राया जंगल के रास्तों से पैदल होकर एक गांव में रोजाना तीन घंटे सेवाएं देती हैं। कई बार शाम होने पर इन गांवों में रात गुजारनी पड़ती है इसलिए वह रात की भोजन सामग्री साथ में लेकर चलती हैं।

-डॉ. मदन मेश्राम, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, बिरसा

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी तथा तेज हवाओं का असर रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के अनेक स्थानों पर मौसम शुष्क व गर्म रहेगा। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा तथा भूस्खलन की संभावना है।

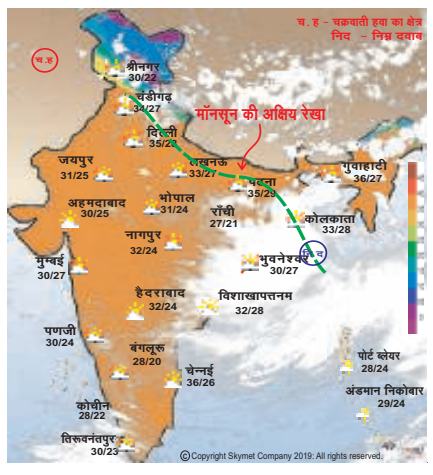

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	29/27/व	अहमदाबाद	32/25/व
कोलकाता	32/26/व	बड़ोदा	32/25/व
चेन्नई	37/29/व	नागपुर	26/23/व
हैदराबाद	33/25/व	इन्दौर	26/23/आंबा
बंगलूरु	27/21/व	रांची	31/25/व
त्रिवेन्द्रम	29/22/आंबा	पटना	32/26/व
गुवाहाटी	30/25/व	जमशेदपुर	34/26/आंबा
जंगटोक	20/10/व	पुणे	24/22/व

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

मंगलवार 13 अगस्त 2019

14

www.jagran.com

पहली बार बनाया स्टेनलेस स्टील

1913 में आज ही ब्रिटिश धातुकर्मी हैरी ब्रियरले ने इंग्लैंड के शेफील्ड में स्टेनलेस स्टील बनाया था। राइफल बैरल के लिए जंग प्रतिरोधक मिश्रित धातु बनाते समय इसकी खोज हुई थी। पहले इसे रस्टलेस स्टील नाम दिया गया था।

पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का बॉर्डर बंद कर दिया गया

1961 में आज ही अमेरिका और रूस के बीच चल रहे शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का बॉर्डर बंद कर दिया गया था। इसी के साथ कटीली तार लगाने का काम शुरू हुआ था। बर्लिन की दीवार बनाने की दिशा में यह पहला कदम था।

हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थीं श्रीदेवी

चुलबुली आदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वालीं अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म 1963 में आज ही तमिलनाडु में हुआ था। अपने 50 साल के करियर में हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु फिल्मों में काम किया। 1972 में आई फिल्म रानी मेरा नाम से बतौर बाल कलाकार हिंदी सिनेमा में करियर की शुरुआत की। 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला से पहचान मिली। चांदनी, नगीना, तोहफा, कर्मा, चालबाज, सदमा उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में रहीं। 2013 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। 24 फरवरी, 2018 को दुबई में उनका देहांत हो गया।

इधर-उधर की

दुनिया के सबसे महंगे आलू के चिप्स

स्टॉकहोम,एजेंसी : आमतौर पर चिप्स के पैकेटों की कीमत पांच, दस या बीस रुपये होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे आलू के चिप्स की कीमत 56 डॉलर यानी करीब 4000 रुपये है। खास किस्म के पैक में इन चिप्स को रखा गया है। इस पैक में महज पांच ही चिप्स हैं। इस हिसाब से एक चिप्स की कीमत करीब 785 रुपये होती है। इन चिप्स को स्वीडन की एक कंपनी सेंट एरिक्स ब्रूवरी ने बनाया है। इसकी पैकिंग ऐसे की गई है, जैसे वो कोई आलू चिप्स नहीं बल्कि महंगी ज्वैलरी हो। यह खास चिप्स पांच जायकों में उपलब्ध हैं। हालांकि यह ग्राहकों की खास मांग पर ही बनाये जाते हैं। कंपनी के मुताबिक, इसमें जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, वो काफी दुर्लभ हैं। चिप्स में जिस प्याज का इस्तेमाल किया गया है, वो एक खास प्रजाति का है, जो सिर्फ लेकसैड शहर में ही पैदा होता है।

शोध अनुसंधान

दिल की हिफाजत कर सकती है तेज रोशनी

तेज रोशनी से रक्त वाहिकाओं से संबंधित एक जीन सक्रिय हो जाता है और हार्ट अटैक से बचने में मदद मिलती है। विज्ञान पत्रिका 'सेल रिपोर्ट्स' में प्रकाशित शोध में यह बात सामने आई है। शोधकर्ता तोबियास एकले ने कहा, 'हमें पहले से पता है कि तेज रोशनी हार्ट अटैक से बचाने में मददगार हो सकती है। अब हमने इसके पीछे के कारण को भी जान लिया है। सर्जरी से हफ्तेभर पहले मरीजों को लाइट थेरेपी देने से दिल के ऊतकों के सुरक्षित रहने की दर बढ़ाई जा सकती है। इस प्रक्रिया को समझते हुए ऐसी दवाएं भी विकसित की जा सकती हैं।' चूहों पर प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि रोशनी से इलाज करने से हार्ट अटैक के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले ऊतकों में बहुत कमी देखी गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रकाश से पीईआर-2 जीन सक्रिय होते हैं और कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी दिल के ऊतकों की हिफाजत करते हैं। - एएनआइ

व्यायाम को भी बनाएं रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा

50 की उम्र से आगे बढ़ते हुए ज्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसमें पूरा ध्यान आर्थिक पहलू पर ही टिका रहता है। वैज्ञानिकों ने इससे एक कदम आगे बढ़ने की बात कही है। उनका कहना है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके लिए 55 की उम्र के आसपास से ही व्यायाम की शुरुआत कर देनी चाहिए। इस अध्ययन में 1,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि बड़ी उम्र के साथ ऐसी कई परेशानियां सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां कम होती चली जाती हैं। हालांकि रिटायरमेंट के बाद स्वस्थ जीवन जीने और मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए व्यायाम की आदत बनाए रखना जरूरी है। - आइएएनएस

जलवायु परिवर्तन से बढ़ सकता है हवाई यात्राओं का जोखिम

- जेट स्ट्रीम पर पड़ रहा है गंभीर असर, 15 फीसद हो गई हैं तेज
- ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन

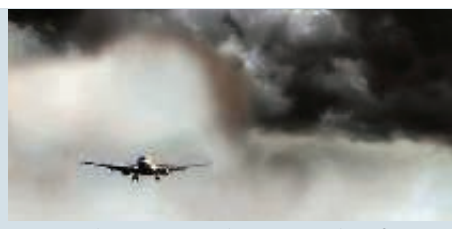

यह अध्ययन नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : भविष्य में हवाई (एयरलाइंस) यात्रियों को यात्रा के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जेट स्ट्रीम यानी जेट धाराओं पर अनुमान से कहीं ज्यादा असर पड़ रहा है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। एक उपग्रह से प्राप्त डाटा का विश्लेषण कर उन्होंने यह पता लगाया है कि 1979 से उत्तरी अटलांटिक के ऊपरी वायुमंडल में जेट स्ट्रीम 15 फीसद तेज गति से चलने लगी हैं, जो भविष्य में और भी तेज हो सकती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर एयरलाइंस सेवाओं पर पड़ सकता है।

जेट स्ट्रीम क्या हैं : जेट स्ट्रीम पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के ऊपरी वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवाएं होती हैं। पृथ्वी पर जेट स्ट्रीम ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल में पश्चिम से पूर्व ओर घूर्णन करते हुए बहती हैं और दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित भी हो सकती हैं। सबसे तेज गति की जेट स्ट्रीम समुद्र तल से 9-12 किमी ऊंचाई पर चलने वाली ध्रुवीय जेट हैं और कुछ कमजोर उपोष्णकटिबंधीय जेट 10-16 किमी पर भी बहती हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में ध्रुवीय जेट मध्य अमेरिका, यूरोप और एशिया और उनके मध्यवर्ती महासागरों के ऊपर बहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध की ध्रुवीय जेट ज्यादातर अंटार्कटिका के ऊपर बहती है।

तीन गुना ज्यादा गंभीर हो सकती है स्थिति : नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए अध्ययन में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 के बाद हवाई यात्रियों को यात्रा के दौरान तीन गुना ज्यादा गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ऊंचाई में हवा की गति ज्यादा होने से उड़ानों पर असर देखने को मिल सकता है। इनका असर इतना तीव्र हो सकता है कि ये हवाई जहाज में बैठे यात्री को सीट से फर्श पर गिरा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जो यात्री हवाई जहाज में यात्रा करने से कतराते हैं, ऐसी स्थिति उन्हें भयभीत कर सकती है और हर साल इससे सैकड़ों यात्री घायल भी हो सकते हैं।

प्रभावित होगा हवाई जहाजों का परिचालन: अध्ययन में पहली बार पता चला है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी के ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच तापमान भी अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही लगभग 34 हजार फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाजों में भी संकट मंडराता नजर आ रहा है। रीडिंग यूनिवर्सिटी से मौसम विज्ञान में पीएचडी करने वाले छात्र साइमन ली ने कहा कि पिछले चार दशकों में आर्कटिक के ऊपर तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि समताप मंडल यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर अपेक्षाकृत ठंडा है। उन्होंने कहा कि सतह का तापमान बदलने से जेट की गति धीमी होगी और ऊंचाई में ताप बदलने से गति बढ़ेगी ऐसे में दोनों के बीच रस्साकशी शुरू हो सकती है और इससे हवाई जहाजों परिचालन प्रभावित हो सकता है।

दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाती है गठिया की दवा

स्पेक्ट्रम

- एनएसएआइडी का उपयोग करने वालों में हार्ट फेल होने का जोखिम 42 फीसद ज्यादा
- आर्थराइटिस एंड रूमेटोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ अध्ययन

गठिया के दर्द से निजात पाने के लिए ली जाती है एनएसएआइडी। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, एएनआइ : ऑस्टियोआर्थराइटिस (गठिया का एक प्रकार) और दिल की बीमारियों के बीच संबंध की बात पहले भी सामने आ चुकी है। अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि गठिया में दर्द से निजात के लिए इस्तेमाल होने वाली एक नॉनस्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा (एनएसएआइडी) इस खतरे को और बढ़ा देती है। यह अध्ययन आर्थराइटिस एंड रूमेटोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसमें 7,743 गठिया पीड़ित और 23,229 स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया। इसमें पाया गया कि गठिया पीड़ित लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा 23 फीसद तक बढ़ जाता है। ऐसे लोगों में स्ट्रोक का खतरा भी जाता रहता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि दिल की बीमारियों का खतरा गठिया के ऐसे मरीजों में ज्यादा पाया गया, जो एनएसएआइडी का सेवन करते हैं। गठिया और दिल की बीमारियों के बीच संबंध को समझने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण जानकारी है। इस दवा का इस्तेमाल करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दवा के उपयोग करने से ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में हार्ट फेल होने का जोखिम 42 फीसद ज्यादा पाया गया। साथ ही इससे 17 फीसद इस्कीमिक हृदय रोग और 14 फीसद स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अध्ययन के दौरान 41 फीसद लोगों में हृदय संबंधी विकारों का खतरा भी देखा गया। इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक, असलम अनीस ने कहा कि यह पहला अध्ययन है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और हृदय रोग के बीच संबंध में एसएसएआइडी की भूमिका का अध्ययन किया गया। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हृदय रोगों के लिए एक प्रमुख कारक है। अनीस ने कहा एसएसएआइडी ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीजों द्वारा दर्द को कम करने के लिए ली जाने वाली एक सामान्य दवा है। लेकिन मरीजों का चाहिए कि वे एसएसएआइडी के प्रयोग से बचें।

20 को चांद की कक्षा में पहुंचेगा चंद्रयान-2

बड़ी बात ▶ बुधवार को पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा की तरफ बढ़ेगा

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आगामी सात सितंबर को उतरेगा इसरो का यान

अहमदाबाद, प्रेट्र : भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-2 इस महीने की 20 तारीख को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त तक चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करता रहेगा। फिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेगा। सात सितंबर को चंद्रयान-2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अभी तक चंद्रमा के इस हिस्से में कोई उपग्रह नहीं उतरा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के सिवन ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सिवन ने पत्रकारों से कहा कि चंद्रयान-2 उपग्रह दो दिन बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा की तरफ बढ़ चलेगा। पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा के बीच के गलियारे की यह यात्रा लगभग सात दिनों की होगी। डॉ. सिवन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉ. विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने यहां आए थे। डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर ही चंद्रयान-2 के लैंडर एयरक्राफ्ट का नाम विक्रम रखा गया है।

चंद्रयान-2 का वजन लगभग 3.8 टन है। इसके तीन हिस्से हैं-ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में डॉ. सतीश धवन अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया गया था।

सिवन ने बताया कि प्रक्षेपण के बाद से चंद्रयान-2 की पृथ्वी की कक्षा पांच बार बदली गई है। उपग्रह इस समय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब अगला और सबसे कठिन कक्षा परिवर्तन बुधवार यानी 14 अगस्त को होगा, जब चंद्रयान-2 को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा की तरफ भेजा जाएगा।

सिवन ने कहा, '14 अगस्त को तड़के 3.30 बजे चंद्रयान-2 की कक्षा बदली जाएगी, जिसे ट्रांस-लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इस कक्ष परिवर्तन के बाद उपग्रह पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा की तरफ बढ़ेगा और 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा।' उन्होंने बताया कि पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बाद चंद्र कक्ष में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके द्वारा 20 अगस्त तक उपग्रह को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाया जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद एक बार फिर चंद्रयान के कक्षा में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद वह सात सितंबर को अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 अभी तक तय कार्यक्रम के मुताबिक काम कर रहा है। उसके सभी उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। सिवन ने बताया कि आने वाले दिनों खासकर दिसंबर में इसरो के वैज्ञानिकों की व्यस्तता बहुत बढ़ जाएगी। दिसंबर में इसरो छोटे उपग्रहों को लांच करने का अभियान शुरू करेगा। पहली बार इसरो छोटे उपग्रह लांच करेगा।

बता दें कि चंद्रयान-2 के चंद्रमा पर उतरने के साथ ही भारत चांद पर जाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पृथ्वी के निर्माणक्रम से लेकर हमारे सौरमंडल को और करीब से समझने का रास्ता भी खुलेगा।

अहमदाबाद में डॉ. विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी समारोह में उनकी जीवनी से जुड़ी एल्बम का विमोचन करते इसरो के अध्यक्ष के सिवन (दाएं से दूसरे) व अन्य। एनएनआइ

अब टेलीग्राम से भेज सकेंगे मूक संदेश और एनिमेटेड इमोजी

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : निजी इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉयस एप टेलीग्राम ने ऐसे अपडेट जारी किए हैं, जो यूजर के लिए मूक संदेश और एनिमेटेड इमोजी भेजने में मदद करेंगे। मूक संदेश भेजने की क्षमता का मतलब है, अगर यूजर्स चाहते हैं कि वे किसी को मैसेज दें पर उसका डिवाइस आवाज न करे, तो वे अब ध्वनि के बिना संदेश भेजने का विकल्प चुन सकते हैं।

जीएसएम एरेना ने कहा कि इसके लिए सेंड बटन को थोड़ी देर तक होल्ड करें और बस बिना आवाज के मैसेज भेजें का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसको मैसेज किया गया है, यदि वह मीटिंग में हो या सो रहा हो तो उसे यह संदेश केवल डिस्प्ले में दिखेगा और कोई आवाज नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा नया फीचर वीडियो थंबनेल्स और टाइमस्टेंप्स है। जब आप वीडियो के माध्यम से स्क्रब करेंगे, यह आपको थंबनेल दिखाएगा, जिससे आप को पता चलेगा कि आप वीडियो पर कहां पर है। इसके अलावा, यदि आप टाइमस्टेंप एक मैसेज के साथ जोड़ते हैं, तो टाइमस्टेंप पर क्लिक करने के साथ ही आप जोड़े गए वीडियो के सटीक स्थान पर पहुंच जाएंगे।

नए अपडेट में एनिमेटेड इमोजी भी शामिल हैं और जब भी इन्हें टेलीग्राम चैट में पोस्ट किया जाता है, यह इमोजी का एनिमेटेड वर्जन दिखाते हैं।

एक्वेरियम में मनेगा आजादी का जश्न

दक्षिण कोरिया में आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वर्ष जापान से आजादी की 74 वी वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी सियोल में स्थित सीओइएक्स एक्वेरियम में पानी के भीतर देश के विशाल झंडे के जश्न मनाया जाएगा। सोमवार को कलाकारों ने रिहर्सल की। दक्षिण कोरिया को 1945 में जापान औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल हुई थी। एएफपी

समर फेस्टिवल का जश्न

कोलंबिया के बगोटा शहर में समर फेस्टिवल पारंपरिक तरीके से धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर कोलंबिया की स्वतंत्रता बाइसेंटेनियल के सम्मान में आयोजित परेड आकर्षण का खास केंद्र होती है। इसमें आर्टिस्ट तरह-तरह के आकर्षक रंग-बिरंगे आउटफिट पहनकर परेड में शामिल होते हैं। एएफपी

स्क्रीन शॉट

बोर्ड परीक्षा के परिणाम जैसी होती है राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा : आयुष्मान

राष्ट्रीय पुरस्कार पाने की खुशी के बीच आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म 'ड्रीमगर्ल' का ट्रेलर सोमवार को मुंबई में लॉन्च किया गया। इस मौके पर शो की निर्माता एकता कपूर के साथ आयुष्मान खुराना, नुसरत भरूचा और फिल्म के लेखक और निर्देशक राज शांडिल्य मौजूद रहे। फिल्म 'अंधाधुन' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद आयुष्मान पहली बार मीडिया के सामने थे। अपनी विश्वसनीयता के लिए लगातार विवादों में घिरे रहने वाले कई अवॉर्ड्स के बीच अवॉर्ड जीतने वाले अभिनेता उन पुरस्कारों के कितने हकदार हैं, उसे लेकर आयुष्मान का मानना है कि जिन्हें अवॉर्ड मिलता है, वे वाकई हकदार हैं, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में अगर उनकी फिल्में चल रही हैं तो इसलिए, क्योंकि दर्शक उन्हें पसंद कर रहे हैं। आयुष्मान का मानना है कि कलाकार एक बच्चे की तरह होता है, जब उसको अवॉर्ड मिलता है, तो वह उत्सुक हो जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार देश से जुड़ा पुरस्कार है, जिसकी घोषणा सबके सामने होती है। यह कुछ-कुछ बोर्ड की परीक्षा के परिणाम की तरह होती है, जिसमें लोग बताते हैं कि आपके इतने नंबर आए हैं। टीवी पर सबके सामने इस अवॉर्ड की घोषणा होती है। आयुष्मान को जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तब उस वक्त वह फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अब तक अवॉर्ड मिलने की बात वह हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह उस दौरान शॉट में थे और जब लौटकर मोबाइल फोन देखा तो चालीस मिस्ड कॉल्स पड़ी थीं। वह सेट पर पचास लोगों के बीच खुद की भावनाओं को जता नहीं पाए थे।

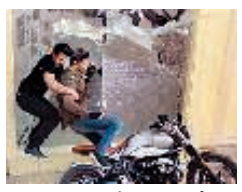

'खतरनाक एक्शन सीन को अंजाम दिया रितिक और टाइगर ने!'

फिल्म 'वार' में रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक-दूसरे को मात देने की कोशिश में एक-दूसरे का पीछा करते नजर आएंगे और चौंका देने वाले स्टंट करते दिखेंगे। ऐसी ही एक खतरनाक बाइक चेज सीक्वेंस की शूटिंग के बारे में निर्देशक सिद्धार्थ आनंद बताते हैं, 'यह बड़ा जोखिमवाला सीन था, क्योंकि जरा-सी चूक होने पर कलाकार गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। यह एक हाईस्पीड बाइक चेस सीन है, जिसमें रितिक सुपर बाइक को भगा रहे हैं और टाइगर पैदल उनका पीछा करते हैं। टाइगर को रितिक पर सही समय पर कूदना था, ताकि दोनों खिड़की के शीशे तोड़ते हुए उस पार निकल जाएं। इस सीन को ऐसे ब्लाइंड स्पॉट पर फिल्माया था, जहां दो रास्ते मिलते थे। इस वजह से रितिक और टाइगर एक-दूसरे को देखकर टाइमिंग तय नहीं कर सकते थे। अभिनेताओं का एक-दूसरे पर भरोसा होना जरूरी था। दोनों बड़े एक्शन हीरो हैं और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए जी-जान लड़ा देते हैं।' फिल्म दो अक्टूबर को रिलीज होगी।

सूटेबल ब्वॉय बनेंगे ईशान खट्टर

हाल ही में भाई शाहिद कपूर के साथ यूरोप टूर पर गए अभिनेता ईशान खट्टर के प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है। ईशान जल्द ही बीबीसी की सीरीज 'ए सूटेबल ब्वॉय' में नजर आएंगे। भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद चार परिवारों की कहानी बयां करती यह सीरीज विक्रम सेठ के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस सीरीज का निर्देशन मीरा नायर करेंगी। तब्बू भी सीरीज का अहम हिस्सा होंगी। तब्बू पहले भी मीरा नायर के निर्देशन में बनी 'द नेमसेक' में काम कर चुकी हैं। इस सीरीज में वह सईदा बाई का किरदार निभाएंगी, जबकि ईशान एक राजनेता के जिद्दी बेटे मान कपूर की भूमिका में होंगे। मीरा नायर के साथ काम करके ईशान काफी खुश हैं। उनका कहना है कि वह उनकी उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ईशान के लिए बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने मान कपूर के किरदार को सही तरीके से निभाने की होगी। सीरीज में तब्बू व ईशान के अलावा नवोदित अभिनेत्री तान्या मणिकतला भी होंगी। उत्तर भारत के महलों व गांवों में शूटिंग की जाएगी। छह भागों में बनने वाली यह सीरीज अगले साल जून तक प्रसारित होगी।

सारा को वरुण ने दिया जन्मदिन का तोहफा

सोमवार को सारा अली खान के जन्मदिन पर वरुण धवन ने उन्हें तोहफे में दिया उनकी अगली फिल्म 'कुली नंबर1' का पोस्टर। पोस्टर में वरुण धवन के साथ सारा अली खान नजर आ रही हैं। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन कर रहे हैं, जिनकी यह 45वीं फिल्म है। वरुण ने पोस्टर साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'हीरोइन तेरा बर्थडे आया, बर्थडे के दिन मैं तेरे लिए पोस्टर लाया।' यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी।

चिंताजनक

ध्रुवों से समुद्री तटों पर भी आने लगे हैं भालू, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता, आमतौर पर अगस्त के मध्य में जमीन पर आते हैं, इस साल मई में भी दिखे थे

लोगों के लिए परेशानी बन सकते हैं ध्रुवीय भालू

- 1990 के बाद से औसतन 36 दिन बढ़ गई है बर्फ पिघलने के मौसम की अवधि
- आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले जानवरों पर भी पड़ रहा जलवायु परिवर्तन का असर

अक्सर गर्मियों के मौसम में जमीन पर आते हैं ध्रुवीय भालू। प्रतीकात्मक

एंकरेज, एपी : भविष्य में मनुष्यों का ध्रुवीय भालुओं से अपने घरों के आसपास भी आमना-सामना हो सकता है क्योंकि भालू ध्रुवों को छोड़ कर समुद्र के किनारों पर भी आने लगे हैं। अलास्का के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में भालू हमारी आबादी के और करीब आ सकते हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।

एंकरेज डेली न्यूज के मुताबिक, अमेरीकी भू-विज्ञान सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि समुद्री बर्फ में रहने योग्य क्षेत्रों में बदलाव आने के कारण ध्रुवीय भालुओं ने जमीन की ओर आना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि गर्मियों में जब बर्फ पिघलने लगती है तो ध्रुवीय भालू ब्यूफोर्ट सागर में उतरने के बाद जमीन तक आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि 1990 के बाद से बर्फ पिघलने के मौसम की अवधि में औसतन 36 दिनों तक बढ़ गई है। अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के ध्रुवीय भालू अनुसंधान कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे वन्यजीव जीव विज्ञानी टॉड एटवुड ने कहा कि पिछले दशक के मुकाबले अब ध्रुवीय भालू जमीन पर ज्यादा दिखने लगे हैं। आम तौर पर ये भालू अगस्त के मध्य में समुद्र के किनारों पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार मई के शुरू में भी एंकरेज से लगभग 1,030 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे शहर काकटोविक में भी ध्रुवीय भालू देखे जाने की सूचना है। स्थानीय निवासी एनी टिक्लुक उन लोगों में से एक हैं, जिन्होंने सोमवार को भी भालू का सामना किया। टिक्लुक ने कहा 'उनकी बेटी और भतीजी घर के बाहर खेल रही थी। तभी मैंने देखा कि कहीं से भालू आ गया। आस-पड़ोस के लोगों ने जब उसे देखा तो सभी भालू को भगाने के लिए दौड़ पड़े और मैं समय रहते बच्चों को लेकर वहां से भाग गई।' एटवुड ने कहा कि दक्षिणी ब्यूफोर्ट में भालू अब रहने के लिए जमीन का भी उपयोग करने लगे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ध्रुवीय भालू यहां तक आ जाएं। उन्होंने कहा कि आर्कटिक में बढ़ती गतिविधियों के कारण शायद भालू अब इंसानों के आवासों की ओर रुख करने लगे हैं। एटवुड ने कहा कि यह मुद्दा बड़ा तो है ही, साथ ही चिंताजनक भी है। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन के कारण हिमखंड पिघल रहे हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी इससे अछूते नहीं हैं। आर्कटिक क्षेत्र से भालुओं का जमीन की ओर आना इस बात की ओर संकेत करता है कि जलवायु परिवर्तन का असर इन जानवरों पर भी पड़ रहा है। इनके आवासों को बचाने के लिए हमें समय रहते सख्त कदम उठाने की जरूरत है।